चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 02 नवंबर-08 नवंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव

नीतीश का पलड़ा भारी

नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनके आक्रामक अंदाज़ से बहुत अलग अपनी चुनाव शैली प्रवीणता के साथ संचालित कर रहे हैं. यह अलग बात है कि पहले सवर्णों का एक छोटा वर्ग ही सही, लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहता था, पर अगड़ों और पिछड़ों के सवाल ने उसे वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ मोड़ दिया. अगड़ों में नीतीश कुमार की तारीफ़ करने वाले तो काफी लोग हैं, लेकिन उन्हें अगड़ों के कितने वोट मिलेंगे, यह नहीं कहा जा सकता. आरक्षण के सवाल ने पूरा चुनाव लालू यादव और नीतीश कुमार की झोली में डाल दिया है, ऐसा लग रहा है. इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और लालू यादव के चुनाव प्रचार ने बिहार के मुसलमानों को बिल्कुल एकजुट कर दिया है, इसलिए ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोटों में जिस टूट का डर था, वह नहीं हुई और ओवैसी को हक़ीकत में उम्मीदवार ही नहीं मिले. ओवैसी को मुस्लिम उम्मीदवार न मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नुक़सान के रूप में देखा जा रहा है.

संतोष भारतीय

क्या एक बयान चुनाव को इधर से उधर कर सकता है? कम से कम मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सोनिया गांधी के एक बयान को गुजरात में अपने कैंपेन का मुख्य मुद्दा बना लिया था और भाजपा के लोगों का मानना है कि उसी मुद्दे के आधार पर नरेंद्र मोदी गुजरात के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव ठीक वैसे लड़ रहे हैं, जैसे किसी भी पार्टी का प्रदेश स्तर का नेता, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चुनाव लड़ता है. धुआंधार सभाएं, उन सभाओं में जमकर बोलना और लोगों को बिहार के विकास का नक्शा बताने के साथ-साथ एक नए बिहार का सपना दिखाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य बन गया है. बिहार में एक तरफ़ भाजपा है, जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ़ महा-गठबंधन है, जिसके नेता नीतीश कुमार एवं लालू यादव दिखाई दे रहे हैं. भाजपा में राज्य स्तर पर कई सारे नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पर उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं है कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं. सिर्फ़ एक व्यक्ति को भरोसा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और उनका नाम सुशील मोदी है. लालू यादव ने लगभग हर जगह स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ़ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ने भी अपने भाषणों में हर जगह लालू यादव के साथ अपनी एकता दर्शाई है.

बिहार विधानसभा चुनाव एक मायने में देश की राजनीति तय करने वाला चुनाव बन गया है. दिल्ली में भाजपा की करारी हार के बाद बिहार का यह चुनाव कुछ यूं देखा जा रहा है कि अगर बिहार में भाजपा जीतती है, तो उसे उत्तर प्रदेश या पंजाब जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी. अगर बिहार में भाजपा चुनाव हारती है, तो उसके हाथ से उत्तर प्रदेश भी जाएगा और पंजाब भी जाएगा. इसलिए शायद भाजपा ने बिहार में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बैठा दिया है, जो चुनाव का संचालन कर रहे हैं. शायद भाजपा को यह डर है कि प्रदेश के नेता चुनाव नहीं संभाल पाएंगे और वह नीतीश कुमार एवं लालू यादव के सामने तिनके की तरह उड़ जाएंगे. इसलिए संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बिहार में चुनाव लड़ रहा है. अगर अफ़वाहों को छोड़ दें, तो किसी को नहीं मालूम कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है.

सबसे पहले भाजपा की रणनीति देखें, तो भाजपा ने इस चुनाव को अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई में बदल दिया. उसने ज़्यादातर सीटों पर या कहें कि बहुमत में टिकट सवर्णों को दिए. भाजपा के सवर्ण नेता ही प्रचार में सामने आए. आरएसएस ने एक नई रणनीति चली. उसने हर चुनाव क्षेत्र में 500 से 1,000 ऐसे बाहरी लोगों को उतारा, जिनका कोई रिश्ता उस क्षेत्र के उम्मीदवार से नहीं रहा. वे लोग गांव-गांव में बैठते थे, चाय की दुकान पर बैठते थे. किसी न किसी से रिश्तेदारी निकाल कर उसके यहां रुक जाते थे. वे लोग एक ऐसा प्रचार अभियान चला रहे हैं, जिससे वहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके. भाजपा ने प्रचार में अपनी सारी ताकत झोंक दी है. अख़बारों में किसी पार्टी के विज्ञापन नज़र नहीं आते, लेकिन भाजपा के नेताओं के कार्यक्रम विज्ञापन के रूप में अख़बारों में दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं, भाजपा में दो तरह से उम्मीदवारों का बंटवारा है. कुछ उम्मीदवारों को ज़्यादा पैसे दिए गए हैं और कुछ उम्मीदवारों को साधारण से भी कम पैसे दिए गए हैं. भाजपा ने पूरे बिहार में प्रचार रथ चलाए हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा रथ डीजल के अभाव में रुके पड़े हैं. दरअसल, भाजपा का चुनाव अभियान प्रोफेशनल्स के हाथों में है और वह कहीं पर लालू यादव एवं नीतीश कुमार की संयुक्त रणनीति के आगे अपने को बेबस पा रही है. शायद इसीलिए अमित शाह का कहना है कि अगर सरकार बन गई महा-गठबंधन की, तो लालू यादव उसे रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे. दूसरी तरफ़ वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अगर सरकार बन गई, तो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी. सवाल यहां यह उठता है कि क्यों इस तरह की भाषा अमित शाह और अरुण जेटली इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका मतलब उनके आत्मविश्वास में

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बिहार में एक ही नाम मुसलमानों के बीच का है, जिसे शाहनवाज हुसैन के नाम से जाना जाता है. शाहनवाज हुसैन मंच पर बोलते हैं, तो तालियां बजती हैं. वह सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं, तर्कपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में उनका नाम लेना भूल जाते हैं. इससे बिहार के मुसलमानों में एक संदेश गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहनवाज हुसैन को सिर्फ़ नाम के लिए आगे कर रहे हैं और उनके मन में मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का कोई जज्बा नहीं है. सुशील मोदी अपने लिए कई बार केंद्रीय नेतृत्व से लड़ चुके हैं. इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वह अपने लिए युद्ध करेंगे.

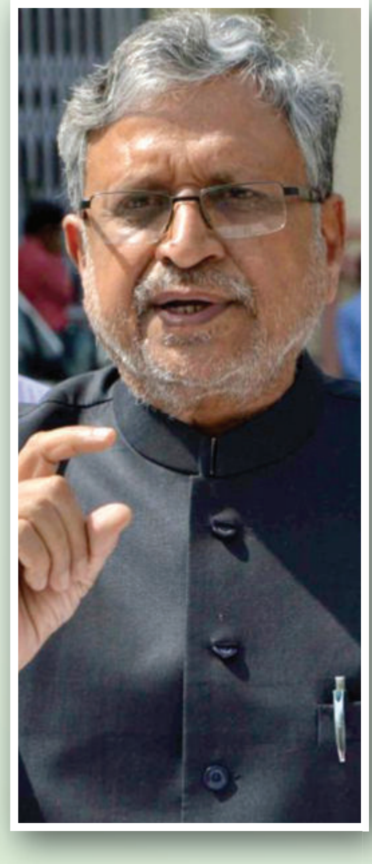

न्यायपालिका की आज़ादी से ज़्यादा जवाबदेही की ज़रूरत है | P-3

सौ फ़ीसद शौचालय निर्माण इस सरकारी दावे की हक़ीकत क्या है | P-4

बिहार विधानसभा चुनाव पर्दे के पीछे के योद्धा | P-6

नीतीश का पलड़ा भारी

पृष्ठ 1 का शेष

कहीं कोई कमी है. बिहार चुनाव की शुरुआत से लेकर दूसरा चरण समाप्त होने तक पूरे बिहार में सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सहारे यह चुनाव लड़ा जा रहा था. दूसरी अगर कोई तस्वीर जो थी, वह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की थी. महत्वपूर्ण जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरों ने बिहार के लोगों को थोड़ा-सा हिला दिया. पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में भी एक रोष पैदा हुआ कि क्या बिहार के नेताओं में एक भी ऐसा नहीं है, जिसे इस चुनाव में आगे किया जा सकता हो और जब यह बात भाजपा कार्यकर्ताओं में फैल गई, तब फिर अचानक एक सुबह देखा गया कि होर्डिंग्स पर बिहार के नेताओं के भी चेहरे दिख रहे हैं. बिहार के नेताओं में जिन लोगों को भाजपा सामने ला रही है, उनमें सुशील मोदी, गिरिराज सिंह के नाम प्रमुख हैं. बिहार में एक ही नाम मुसलमानों के बीच का है, जिसे शाहनवाज हुसैन के नाम से जाना जाता है. शाहनवाज हुसैन मंच पर बोलते हैं, तो तालियां बजती हैं. वह सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं, तर्कपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में उनका नाम लेना भूल जाते हैं. इससे बिहार के मुसलमानों में एक संदेश गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहनवाज हुसैन को सिर्फ़ नाम के लिए आगे कर रहे हैं और उनके मन में मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का कोई जज्बा नहीं है. सुशील मोदी अपने लिए कई बार केंद्रीय नेतृत्व से लड़ चुके हैं. इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वह अपने लिए युद्ध करेंगे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने बिहार चुनाव में चिंगारी का काम किया है और वह बयान है कि आरक्षण के ऊपर बहस होनी चाहिए और आरक्षण ख़त्म होना चाहिए. कम से कम बिहार में लोगों के बीच यही संदेश गया है और इस संदेश ने अधिकांश पिछड़ों को एकजुट कर दिया, दलितों को एकजुट कर दिया और दलितों में एक दरार डाल दी. ज़्यादातर दलितों और पिछड़ों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका आरक्षण छीन लेना चाहती है. सफ़ाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मंत्री और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा. लेकिन, लोगों के मन में यह डर बैठ गया है और इस डर ने दलितों के एक बड़े हिस्से को नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ जोड़ दिया है. यह मुद्दा मोहन भागवत ने क्यों उठाया, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मोहन

भागवत ने इस मुद्दे के ज़रिये बिहार में एक परीक्षण किया है कि अगर इस मुद्दे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो इसका मतलब होगा कि सारा देश आरक्षण समाप्त करने के पक्ष में है और यही बहस बिहार चुनाव में जारी है.

नीतीश कुमार एवं लालू यादव अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तार्किक हमले कर रहे हैं और कम से कम अपने चुनाव को बिहार की धरती से जुड़ा हुआ दिखाने में सफल हो रहे हैं. इस चुनाव में मोहन भागवत के बयान ने लालू यादव को नए सिरे से आरक्षण के लिए लड़ने वाले बड़े योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है और यह लालू यादव के लिए एक बड़ा अवसर है. लालू यादव के दोनों पुत्र चुनाव मैदान में हैं. शायद लालू यादव अपने दोनों पुत्रों को चुनाव में जिताना चाह रहे होंगे और इसीलिए वह प्रतिदिन हेलिकॉप्टर से दौरा समाप्त करने के बाद कार से अपने पुत्रों के चुनाव क्षेत्र में चले जाते हैं. नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और उनके आक्रामक अंदाज़ से बहुत अलग अपनी चुनाव शैली प्रवीणता के साथ संचालित कर रहे हैं. यह अलग बात है कि पहले सवर्णों का एक छोटा वर्ग ही सही, लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहता था, पर अगड़ों और पिछड़ों के सवाल ने उसे वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ़ मोड़ दिया. अगड़ों में नीतीश कुमार की तारीफ़ करने वाले तो काफी लोग हैं, लेकिन उन्हें अगड़ों के कितने वोट मिलेंगे, यह नहीं कहा जा सकता. आरक्षण के सवाल ने पूरा चुनाव लालू यादव और नीतीश कुमार की झोली में डाल दिया है, ऐसा लग रहा है. इतना ही नहीं, नीतीश कुमार और लालू यादव के चुनाव प्रचार ने बिहार के मुसलमानों को बिल्कुल एकजुट कर दिया है, इसलिए ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोटों में जिस टूट का डर था, वह नहीं हुई और ओवैसी को हक़ीक़त में उम्मीदवार ही नहीं मिले. ओवैसी को मुस्लिम उम्मीदवार न मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नुक़सान के रूप में देखा जा रहा है.

कांग्रेस का चुनाव प्रचार अजीब ढंग से चल रहा है. जिस आक्रामकता के साथ नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, उसका एक प्रतिशत भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी में तेजी नहीं दिखाई दे रही है. कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं दिए गए हैं. उनके पर्चे, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि प्रचार सामग्री बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है. एक मोटा आकलन है कि हो सकता है कि कांग्रेस 10 से 15 सीटें जीत जाए, पर वह चुनाव तो 40 सीटों पर लड़ रही है. ये बची हुई 25 सीटें किसके पास जाएंगी, यह एक यक्ष प्रश्न है. कुछ सीटें तो निर्दलीय जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगी और यह भारतीय जनता पार्टी का खुशी का बिंदु है. वहीं दूसरी तरफ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने अपने टिकट मजबूत उम्मीदवारों को नहीं दिए हैं. बिहार में यह अफ़वाह है कि टिकट बेचे गए हैं. उन उम्मीदवारों को दिए गए हैं, जो सहयोगी दलों के नेता या कार्यकर्ता नहीं थे. बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी अपने वोट ट्रांसफर करा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाकी दो सहयोगी नेता अपने वोट 100 प्रतिशत ट्रांसफर नहीं करा पाए. इतना ही नहीं, कई सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेताओं ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बागी उम्मीदवार भी खड़े कराए हैं और यह भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर कड़ी है. भारतीय जनता पार्टी की एक और कमज़ोर कड़ी है और वह है, बिहार का यादव वोट बैंक. भाजपा को लगता था कि वह यादव वोटों में काफी बंटवारा करा पाएगी, लेकिन नंद किशोर यादव को नेतृत्व की पंक्ति में न खड़ा करना, मोहन भागवत का आरक्षण संबंधी बयान और लालू यादव का आरक्षण को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ गया.

मुलायम सिंह यादव का बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने का प्रयोग विफल हो गया. उनसे न केवल शरद पवार, बल्कि पप्पू यादव ने भी किनारा कर लिया. दरअसल, मुलायम सिंह का एक बयान भाजपा के पक्ष में गया, जिसने इस मोर्चे को तोड़ दिया. मुलायम सिंह ने दौरे भी बंद कर दिए हैं. काश, मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव और नीतीश कुमार का साथ दिया होता, तो उन्हें अपने उम्मीदवारों की संभावित भयानक हार का सामना न करना पड़ता. उनकी मुट्ठी बंद रहती, जो उन्हें ग़ैर भाजपा दलों के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित कर देती.

बिहार विधानसभा चुनाव को कुछ नेताओं ने सांप्रदायिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बिहार में मोटे तौर पर यह अंदाज़न माना जाता था कि सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ा दो कि दंगे हो जाएं. दंगे होने की स्थिति में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी. इस ध्रुवीकरण के सिद्धांत के पीछे भारतीय जनता पार्टी या उसका समर्थन करने और राजनीति से अलग रहने वाले लोग हैं. इसे निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे बिहार में सांप्रदायिक माहौल बना. दिल्ली के नज़दीक दादरी में हुए हत्याकांड में गाय का मांस खाना चाहिए या नहीं, इसे प्रमुख विषय बना दिया गया. लेकिन, बिहार के मुसलमानों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई. तमाम उकसावे के बावजूद बिहार में सांप्रदायिक दंगे तीसरे चरण की समाप्ति तक नहीं हुए और उन लोगों को प्रश्रय भी नहीं मिला, जो चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते थे. इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार के मुसलमान धन्यवाद के पात्र हैं. लेकिन, बिहार में इस तरह की कोशिश होने और ऐसी कोशिश करने वालों को न पकड़े जाने या उन्हें चिन्हित न कर पाने को सरकारों की असफलता माना जा सकता है. बिहार विधानसभा चुनाव मुद्दों से परे है और एक अंदाज़ के हिसाब से दोनों पक्षों में कड़ी टक्कर है. सवाल उठता है कि केंद्र में प्रचंड बहुमत से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लालू यादव को लेकर किया जाने वाला जंगलराज का प्रचार और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बिहार में उपस्थिति यदि इस नतीजे पर ले आती है कि चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर है, तो फिर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है और साधारण बहुमत से जीतती है, तो यह माना जाएगा कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह ख़त्म हो रहा है. खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर उसके बड़े नेताओं द्वारा बार-बार यह कहने के बावजूद कि चुनाव में हमारे कार्यक्रम लगाए जाएं, लोग उनके कार्यक्रम नहीं लगवा रहे हैं. दूसरी तरफ़ कांग्रेस के लोग चुनाव प्रचारकों का इंतज़ार करते रहते हैं और प्रचारक वहां पहुंच नहीं पाते. लालू यादव एवं नीतीश कुमार धुआंधार सभाएं कर रहे हैं और उनकी सभाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं. इन दोनों पार्टियों के पास प्रचार के लिए पैसे नहीं हैं और वह दिखाई भी दे रहा है. नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार की कमान प्रशांत किशोर के पास है, जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान संचालित किया था. अभी का चुनाव अभियान संगठित अवश्य है, लेकिन जदयू के नेताओं में इस अभियान को लेकर थोड़ी नाराज़गी है, पर युद्ध अपने पूरे उफान पर है. और, यदि बिहार विधानसभा चुनाव तराज़ू के पलड़े पर तौलें, तो नीतीश कुमार की तरफ़ यह कुछ ज़्यादा झुका दिखाई दे रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 35
दिल्ली, 02 नवंबर-08 नवंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

वरिष्ठों की छत्रछाया में नए बाबू

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ सचिवों जैसे अमिताभ कांत, जुगल मोहापात्रा, संजय कोठारी एवं अंजुली छिब दुग्गल को यह निर्देश दिया है कि वे नए आईएएस अधिकारियों, जिन्हें केंद्र में सहायक सचिव बनाया गया है, को प्रशिक्षित करें, सलाह दें. इसका मकसद यह है कि विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में होने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में नए अधिकारी भी भाग लें यानी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिरकत करें. मोदी सरकार के इस प्रमुख कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा एवं चार अन्य वरिष्ठ बाबू. अमिताभ कांत मेक इन इंडिया के मुख्य कर्ताधर्ता हैं, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव मोहापात्रा मुख्य रूप से सोशल सेक्टर का कार्यक्रम देख रहे हैं. दूसरी तरफ़ वित्तीय सेवा सचिव अंजुली दुग्गल आर्थिक क्षेत्र में होने वाली पहल की इंचार्ज हैं. युवा आईएएस अधिकारियों के पास सीखने और प्रशासनिक कौशल विकास के लिए पर्याप्त अवसर होंगे, जिसका उन्हें आगे चलकर फ़ायदा मिलेगा. ■

अफ़वाहों का बाज़ार गर्म

दिल्ली में अफ़वाहों का बाज़ार कभी बंद नहीं होता. पिछले महीने कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी छह महीने का कार्यकाल बचे होने के बाद भी बाहर निकलने वाले हैं. बस्सी पिछले कुछ समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जुबानी लड़ाई में व्यस्त हैं. अब यह संकेत मिल रहा है कि एक दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद बस्सी को विजय शर्मा के स्थान पर मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स यह भी संकेत दे रही हैं कि उच्च पुलिस अधिकारियों में छिड़े पावर स्ट्रगल के बीच बस्सी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उक्त उच्चाधिकारी उनकी जगह आना चाहते हैं. दिल्ली के अफ़वाहों के बाज़ार में यह भी चर्चा गर्म है कि मोदी के विश्वासपात्र एवं गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश मुर्मु प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बनाए जा सकते हैं. अभी ईडी के निदेशक आईपीएस अधिकारी कर्नल सिंह हैं, जिन्हें राजन कटोच के हटाए जाने के बाद प्रभार दिया गया था. इधर सरकार संजीव भट्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार कर रही थी. इस मामले में संजीव भट्ट ने मुर्मु के ख़िलाफ़ जांच की मांग की थी. यह याचिका खारिज हो गई है. सूत्र बताते हैं कि इसके बाद मुर्मु के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बनने का रास्ता साफ़ हो गया है. ■

दिल्ली में जंग जारी है

एमके मीणा के एसीबी चीफ बनने का मुद्दा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच विवाद का विषय बन गया. हालांकि, मीणा बाजी मार ले गए, फिर भी दिल्ली सरकार ने हार नहीं मानी है. सरकार ने अब ग़लत नीयत से की गई अवैधानिक कार्रवाई और लापरवाही की जांच कराने की धमकी दी है. वहीं मोदी सरकार ने वैट कमिश्नर विजय कुमार का तबादला कर दिया है, वह भी बिना राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किए. आप नेताओं के मुताबिक, कुमार बेहतर काम कर रहे थे और राजधानी में कर चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे थे. यह आरोप लगाया जा रहा है कि ताकतवर व्यापारिक लॉबी के दबाव में केंद्र सरकार ने कुमार का तबादला लक्षद्वीप कर दिया है. राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि वह कुमार के तबादले को केंद्र सरकार की तानाशाही के रूप में प्रचारित करेगी. ■

dilipcherian@gmail..com

दुनिया के किसी भी देश में जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं. यह सिर्फ भारत में होता है. फ्रांस में न्यायपालिका की आजादी पर कोई विवाद नहीं है. वहां न्यायपालिका को ज्यूडीशियल सर्विस के जरिए संचालित किया जाता है. फ्रांस का सिस्टम सबसे ज्यादा पारदर्शी, ऑब्जेक्टिव और जवाबदेह है. इंग्लैंड में न्यायपालिका में कार्यरत लोगों के बीच से ही सरकार जजों का चुनाव करती है,लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जज बन सकता है, यह जरूरी नहीं कि उसके पास न्यायपालिका का कोई अनुभव हो. दुनिया के किसी भी देश में जज स्वयं जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो क्या उन सभी देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है?

"जजों की नियुक्ति का मामला हमेशा से विवादों में रहा है. पहले जजों की नियुक्ति सीधे सरकार करती थी और चीफ जस्टिस से इस मसले पर सिर्फ सलाह ली जाती थी. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली पर सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अहम बताया गया है और जजों की नियुक्ति में सरकार का दख़ल उचित नहीं है. इसके बाद भारत में हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बनी. जजों का पैनल या कॉलेजियम जजों के नाम तय कर सरकार के पास भेजता है और सरकार को इसे मानना पड़ता है."

न्यायपालिका की आज़ादी से ज़्यादा जवाबदेही की ज़रूरत है

मनीष कुमार

क्या इस देश में गरीबों को अदालत से न्याय मिलना आसान है? इसका साधारण और सीधा जवाब है, नहीं. वजह साफ है कि देश की न्यायिक प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है या फिर इसे इतना उलझा दिया गया है कि लोग कोर्ट-कचहरी को न्याय का मंदिर नहीं बल्कि एक दलदल मानते हैं जिसमें कोई एक बार फंसा तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है. न्याय मिलने में देर तो होती ही है साथ ही यह महंगा भी है. जो गरीब हैं वे कोर्ट कचहरी में होने वाले खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं. यह कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है बल्कि यही दस्तूर है, यही व्यवस्था है. इसका मतलब तो यह हुआ कि देश की 75 फ़ीसदी आबादी जिनकी आय दो डॉलर प्रतिदिन से कम है, वह तो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही नहीं सकता है. गरीब ही क्यों, अदालतों की व्यवस्था ऐसी है जो कि मध्यम वर्ग के लिए भी परेशानी का सबब है. हक़ीकत तो यह है कि देश में कई लोगों ने कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला. देश में शायद एक फीसदी लोग भी ऐसे नहीं हैं जो महंगे वकील की सेवा लेने की सामर्थ्य रखते हैं. मतलब यह कि देश में न्यायिक व्यवस्था गरीबों के लिए नहीं, बल्कि अमीरों के लिए है. यही वजह है कि हमें एक तरफ सलमान ख़ान का उदाहरण देखने को मिलता है और दूसरी तरफ ऐसे हजारों लोगों की कहानी सुनने को मिलती है जो एक छोटे से जुर्म के आरोप में सालों से जेलों में बंद हैं और उन्हें जमानत तक नहीं मिल सकी. इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और अनैतिक क्रियाकलापों की खबरें भी आम हो गई हैं. अदालतों में पैसे का बोल-बाला है. भ्रष्टाचार है. न्याय मिलने में देरी होती है. इसके अलावा भी न्यायिक व्यवस्था में कई खामियां और समस्याएं हैं जिन्हें अविलंब सुधारने की जरूरत है. न्यायपालिका को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया किस तरह जनता के लिए सुलभ, सरल, स्वतंत्र, नि:शुल्क और शीघ्र उपलब्ध हो, लेकिन देश की सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर महाभारत शुरू हो गई है.

यह विवाद तब शुरु हुआ जब जजों की नियुक्ति की नई व्यवस्था के लिए लाए गए 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर निरस्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की दलील यह है कि नई व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध है. जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्टर(आधारभूत ढांचे) के ख़िलाफ है इसलिए यह क़ानून असंवैधानिक है. कोर्ट ने यह दलील दी है कि चूंकि, भारत में सिविल सोसाइटी का विकास नहीं हो पाया है इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है. वर्तमान में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है. इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जज होते हैं. जजों का यह पैनल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की सिफारिशें करता है. कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. उनकी सहमति के बाद अंतिम फैसला लागू होता है. तकरीबन 20 सालों से कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति हो रही है. इस सिस्टम को लागू करने के पीछे यह दलील थी कि जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की राय को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. इस सिस्टम में सरकार की भूमिका न के बराबर है. लेकिन इस प्रणाली पर निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे. मोदी सरकार ने सरकार बनाते ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की मुहिम तेज़ कर दी और इसके लिए क़ानून में संशोधन भी कर दिया. नेशनल ज्यूडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (एनजेएसी) बिल (99वां संविधान संशोधन) के संसद में पास होने के बाद, उसे आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति भी मिल चुकी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. इस संवैधानिक संसोधन को असंवैधानिक करार देने से एक नई समस्या खड़ी हो गई. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार तिलमिला उठी. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विवादों के घेरे में आ गया. इस फैसले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिना किसी शक के बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अलावा भी संविधान के कई बेसिक स्ट्रक्चर हैं. जिन्हें इस फैसले में नजरअंदाज किया गया है. जटली के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने संविधान के एक बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए पांच अन्य बेसिक स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाई है.

संसद के दोनों सदनों और 20 विधानसभाओं द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग(99वें संविधान संशोधन) विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक बताना कोई सामान्य घटना नहीं है. यह न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति है. यह स्थिति भारत के प्रजातंत्र के लिए हितकारी नहीं है. बड़े-बड़े क़ानूनविद बंटे हुए हैं. जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं उनका मानना है कि यदि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित हो जाता, तो इससे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ता. इससे जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि इस आयोग का सचिवालय क़ानून मंत्रालय के अधीन काम करता. इससे सरकार के पक्ष में काम करनेवाले लोगों की जज के रूप में नियुक्त होने की संभावना होती.

जजों की नियुक्ति का मामला हमेशा से विवादों में रहा है. पहले जजों की नियुक्ति सीधे सरकार करती थी और चीफ जस्टिस से इस मसले पर सिर्फ सलाह ली जाती थी. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली पर सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अहम बताया गया है और जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल उचित नहीं है. इसके बाद भारत में हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बनी. जजों का पैनल या कॉलेजियम जजों के नाम तय कर सरकार के पास भेजता है और सरकार को इसे मानना पड़ता है. सरकार सिर्फ इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है. लेकिन, यदि कॉलेजियम नियुक्ति पर सर्वसम्मत फैसला सुनाता है, तो सरकार इसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होती है. इस प्रणाली के तहत जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता है.

कई क़ानूनविद ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं. उनका कहना है कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति नहीं होती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताने वालों में भी ऐसे कई क़ानूनविद हैं जो जजों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को भी पारदर्शी नहीं मानते हैं और उसमें बदलाव चाहते हैं. उनका मानना है कि इस प्रक्रिया के कारण जज अपने चहेतों को जज नियकुत करते हैं. इस प्रणाली में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जज ही जज की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं. अब सवाल यह है कि क्या प्रजातंत्र में किसी संस्था का निरंकुश होना उचित है या नहीं. प्रजातांत्रिक व्यवस्था जनता द्वारा संचालित व्यवस्था है, इसके साथ ही यह एक जवाबदेह व्यवस्था है. इसमें हर संस्था का जवाबदेह होना लाज़मी है. संविधान और स्वतंत्रता की आड़ में कोई संस्था या व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है. यहां समझने वाली बात यह है कि प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोच्च है,वही मालिक है. रही बात व्यवस्था या प्रणाली की तो वह समय, काल और जरूरत के हिसाब से बदली जा सकती है. लेकिन जब तक देश प्रजातंत्र है तब तक सभी सरकारी संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा. चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका. सबकी जवाबदेही है और यही प्रजातंत्र की मूल भावना है.

सुप्रीम कोर्ट का सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया जाना कई सवाल खड़े करता है. जहां तक बात संविधान में जजों की नियुक्ति के प्रावधान की है तो आर्टिकल 124 में यह साफ लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट की या वह जिनकी चाहेंगे उनकी राय लेंगे. संविधान ने जजों की नियुक्ति की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को दी है. दूसरी बात यह कि, यदि सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया है, तो उसे यह भी बताना पड़ेगा कि सरकार का यह प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद के विरुद्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि संविधान किस अनुच्छेद, किस धारा में कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख है. जिस संस्था का संस्थान में उल्लेख नहीं है वह व्यवस्था संवैधानिक कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए था कि कॉलेजियम प्रणाली की निष्पक्षता और पार्दशिता को लेकर जो आरोप हैं उसका क्या हल है? कॉलेजियम प्रणाली पर उठी शंकाओं का क्या निदान है?

दुनिया के किसी भी देश में जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं. यह सिर्फ भारत में होता है. फ्रांस में न्यायपालिका की आजादी पर कोई विवाद नहीं है. वहां न्यायपालिका को ज्यूडीशियल सर्विस के जरिए संचालित किया जाता है. फ्रांस का सिस्टम सबसे ज्यादा पारदर्शी, ऑब्जेक्टिव (वस्तुनिष्ठ) और जवाबदेह है. इंग्लैंड में न्यायपालिका में कार्यरत लोगों के बीच से ही सरकार जजों का चुनाव करती है, लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जज बन सकता है, यह जरूरी नहीं कि उसके पास न्यायपालिका का कोई अनुभव हो. दुनिया के किसी भी देश में जज स्वयं जजों की नियुक्ति नहीं करते हैं तो क्या उन सभी देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? यहां समझने वाली बात यह है कि कई सालों से ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा) के सृजन की मांग हो रही है. कई लोगों का मानना है कि न्यायपालिका में भारी बदलाव की जरूरत है. कई लोगों ने यह सुझाव भी दिया है कि ऑल इंडिया सर्विसेज की तर्ज़ पर न्यायपालिका के लिए भी ऑल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विस बने. जजों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी) जैसी संस्था द्वारा हो. नियुक्ति की शुरुआत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) से हो. चयनित व्यक्ति वहां से अपनी काबिलियत और वरीयता के आधार पर हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनें. लेकिन इस सुझाव को हर बार न्यायपालिका की आजादी की दलील की आड़ में ताक पर रख दिया जाता है. ऐसे सही बात तो यह है कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन हो, जो सरकार और जजों के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो. जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए मानक तय किए जाने चाहिए. जिस तरह अखिल भारतीय सेवाओं (ऑल इंडिया सर्विसेज) के लिए प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित होती हैं उसी तरह न्यायिक सेवाओं के लिए भी परीक्षा हो ताकि मेधावी छात्र-छात्राओं को मौक़ा मिल सके.

हक़ीकत यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि उसकी जवाबदेही तय नहीं हो, और जज ही जज की नियुक्ति करें. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सही मतलब न्याय की प्रक्रिया में जज स्वतंत्र हों, बिना किसी बाहरी प्रभाव के जज अपना फैसला दें, अदालतों में भ्रष्टाचार न हो. न्याय प्रक्रिया में पैसे और प्रभाव का खत्म होना ही सही आजादी है. पैसे लेकर काम करवाने और बड़े-बड़े वकीलों के प्रति पक्षपात बंद हो. अमीर और ग़रीब के लिए अदालत समान भाव से फैसला सुनाए, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आत्मा होनी चाहिए. जनता का न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आदर और भरोसा मजबूत होना ही न्यायालय की सबसे बड़ी जीत है. न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. न्यायिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की जरूरत है. जजों की नियुक्ति से ज्यादा देश के श्रम न्यायालय (लेबर कोर्ट) की दिशा और दशा बदलने को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जिला स्तर और उससे नीचे की न्यायिक व्यवस्था निराशाजनक है. ■

manishbph244@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान: सरकारी स्कूलों में सौ फ़ीसद शौचालय निर्माण

इस सरकारी दावे की हक़ीकत क्या है

शौचालय निर्माण योजना की स्थिति का अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सौ फ़ीसद लक्ष्य पाने के दावे के ठीक छह दिनों बाद ही सरायकेला ज़िले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से 200 छात्राओं ने अपना नाम इसलिए कटा लिया, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में शौचालय नहीं थे. नियमानुसार हर 40 छात्र-छात्राओं पर एक शौचालय होना चाहिए. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विकलांग बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाला शौचालय अलग से होना चाहिए. लेकिन, ऐसी सुविधा शायद कहीं देखने को मिले.

चौथी दुनिया ब्यूरो

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा है कि उसने देश भर के सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण का अपना लक्ष्य दो अक्टूबर, 2015 तक हासिल कर लिया है. मंत्रालय के मुताबिक, सौ फ़ीसद लक्ष्य हासिल कर लिया गया है (देखें तस्वीर). लेकिन, यह दावा कितना सही है? जब चौथी दुनिया संवाददाताओं ने बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विभिन्न ज़िलों में इस दावे की जांच की, तो इसकी कलई खुलती नज़र आई. हमारी रिपोर्ट बताती है कि अव्वल तो कई स्कूलों में तो शौचालय नहीं हैं, जहां बने हैं उनमें से अधिकांश में दरवाजे नहीं हैं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है और जहां दरवाजे हैं, उनमें ताला लटक रहा है. चौथी दुनिया संवाददाताओं ने यह भी पाया कि शौचालय निर्माण में जमकर धांधली हुई है. सरकार की ओर से शौचालय बनाने के लिए अच्छी-खासी धनराशि दी गई, निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरतीं.

कुछ निजी संस्थाओं की तरफ़ से की गई स्वतंत्र जांच भी इन दावों की पोल खोलती है. मसलन, मुंबई स्थित संस्था इंडिया स्पेंड ने जब देश के कुछ स्कूलों का दौरा किया, तो पाया कि अधिकतर स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय की सुविधा का दावा सच नहीं है. संस्था ने जब दिल्ली, सीतापुर (उत्तर प्रदेश), तुमकुर (कर्नाटक) एवं दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) के स्कूलों की जांच की, तो पाया कि जहां पहले से शौचालय हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है. शौचालय गंदे पड़े हैं. इसलिए बच्चे उनका इस्तेमाल नहीं करते. शौचालय निर्माण योजना की स्थिति का अंदाज़ा सिर्फ़ इस बात से लगाया जा सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सौ फ़ीसद लक्ष्य पाने के दावे के ठीक छह दिनों बाद ही सरायकेला ज़िले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से 200 छात्राओं ने अपना नाम इसलिए कटा लिया, क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में शौचालय नहीं थे. नियमानुसार हर 40 छात्र-छात्राओं पर एक शौचालय होना चाहिए. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विकलांग बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाला शौचालय अलग से होना चाहिए. लेकिन, ऐसी सुविधा शायद कहीं देखने को मिले.

शौचालय निर्माण कार्यक्रम में कॉरपोरेट घरानों ने भी कॉरपोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) के तहत काम किया है. बावजूद इसके अगर यह स्थिति है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारी सहायता से बनने वाले शौचालयों की हालत क्या होगी. और तो और, इस योजना के तहत जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक, दिल्ली जैसे राज्य में एक भी शौचालय का निर्माण नहीं हुआ. शायद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए शौचालयों की ज़रूरत नहीं थी या फिर इस दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार ने उदासीनता बरती. हालांकि, देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में शौचालयों की हालत काफी खराब है. मसलन, दिल्ली के संगम विहार स्थित एक बालिका विद्यालय के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बायो टायलेट दिए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शुरुआती इस्तेमाल के बाद किसी ने उन्हें साफ़ करने की जहमत नहीं उठाई और अब उनसे इतनी बदबू आती है कि छात्राएं उनका इस्तेमाल नहीं कर पातीं.

पूर्वी चंपारण (बिहार) के 531 विद्यालय शौचालय विहीन

पूर्वी चंपारण ज़िले के 3,355 विद्यालयों में से केवल 2,824 विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था है. 531 विद्यालय ऐसे हैं, जहां आज भी शौचालय नहीं हैं. इनमें एक उच्च विद्यालय भी है. ज़िला मुख्यालय मोतिहारी स्थित धर्मसमाज उच्च विद्यालय में शौचालय नहीं है. इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि छात्र-छात्राओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और इसे लेकर विभाग एवं प्रशासन कितना गंभीर है. ज़िले में 93 उच्च और 3,262 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं. ग़ौरतलब यह कि इनमें 530 विद्यालय भूमिहीन हैं, जिनके पास न तो भवन है और न शौचालय. हालांकि, उच्च विद्यालयों के पास अपने भवन एवं शौचालय हैं. केवल धर्मसमाज चौक स्थित उच्च विद्यालय इससे वंचित है. उच्च विद्यालयों में शौचालय आदि की व्यवस्था राष्ट्रीय माध्यमिक योजना के अंतर्गत है, वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के तहत. विद्यालयों को भवन, पेयजल एवं शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 2011 में तेजी से काम शुरू किया गया. तब स्थितियां बहुत खराब थीं. 60 फ़ीसद विद्यालयों के पास न तो भूमि थी और न भवन. ऐसे विद्यालयों की सूची बनाकर भूमि उपलब्ध कराने के लिए ज़िला प्रशासन से कहा गया, जबकि भवनों के लिए सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई. सैकड़ों स्थानों पर भूमि हासिल कर भवन एवं शौचालय का निर्माण कराया गया. बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय भी थे, जहां भवन तो था, परंतु शौचालय नहीं थे. ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर शौचालयों का निर्माण कराया गया.

रामगढ़वा प्रखंड के 42, रक्सौल के 52, तुरकौलिया के 40, फेनहारा के 25, पताही के 39, ढाका के 96, बनकटवा के 21, पकड़ी दयाल के 31, केशरिया के 57, पहाड़पुर के 39 और कल्याणपुर के 20 विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन अभी भी 531 विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं. ज़िला शिक्षा पदाधिकारी कुमार सहजानंद का कहना है कि भूमि और भवन न होने के कारण इन विद्यालयों में शौचालय का अभाव है. शौचालय की ज़रूरत और अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन विद्यालयों में शौचालय बनाए गए, वहां छात्रों, खासकर छात्राओं की संख्या में खासी वृद्धि हुई है. जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं हैं, वहां आज भी छात्राएं जाने से कतराती हैं. रखरखाव के कमी के चलते भी कई जगह शौचालयों का इस्तेमाल नहीं हो पाता. लगभग तीस फ़ीसद विद्यालयों में शौचालय रखरखाव के अभाव में बेकार पड़े हैं. कहीं दरवाजा नहीं है, तो कहीं शौचालय गंदे होने के डर से बंद हैं. पानी की समुचित व्यवस्था न होने से भी शौचालय का इस्तेमाल बच्चे नहीं करते.

गया: शौचालय निर्माण में जमकर धांधली

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने की योजना गया ज़िले में असफल हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई इस योजना के तहत गया में अब तक मात्र दो सौ शौचालयों का निर्माण हुआ है. इसमें भी ठेका लेने वाली संस्था ने पेटी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली छोटी कंपनियों एवं छोटे ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया है. मई 2015 तक गया के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए आवश्यकतानुसार अलग-अलग शौचालयों का निर्माण हो जाना चाहिए था, जुलाई 2015 तक काम होने के बाद मात्र दो सौ शौचालय बन सके. गया में शौचालय निर्माण का ठेका दिल्ली की आरईसी कंपनी ने लिया था, जो बिजली का काम करती है. उसने यह ठेका पीडीआईएल नामक कंपनी को स्थानांतरित कर दिया. पीडीआईएल ने भी छोटे-छोटे ठेकेदारों को पेटी कांट्रैक्ट देकर क़रीब 50 शौचालयों का निर्माण कराया. एक शौचालय के लिए एक लाख बीस हज़ार रुपये की धनराशि तय की गई है, लेकिन गया में शौचालय निर्माण करने वाले एक पेटी कांट्रैक्टर मुरलीधर कंस्ट्रक्शन के लोगों ने बताया कि काम करा लेने के बाद पीडीआईएल ने प्रति शौचालय मात्र सत्तर हज़ार रुपये का भुगतान किया. पचास हज़ार रुपये प्रति शौचालय किस मद में काट लिए गए, यह पीडीआईएल का कोई अधिकारी नहीं बता रहा है. दूसरी तरफ़ यह भी पता चला है कि शौचालय निर्माण का ठेका लेने वाली मूल कंपनी आईईसी ने पीडीआईएल से पेटी कांट्रैक्ट खत्म कर किसी अन्य कंपनी को अपना ठेका स्थानांतरित कर दिया. उक्त नई कंपनी गया में अब तक 150 फाइबर शौचालयों का निर्माण करा चुकी है, जिसकी लागत प्रति शौचालय दो लाख पचीस हज़ार रुपये आ रही है. पहले पक्का एवं छत वाला शौचालय मात्र एक लाख बीस हज़ार रुपये में बनता था, जो दरअसल पेटी ठेकेदारों द्वारा पचास हज़ार रुपये में बना दिया जाता था. अब फाइबर शौचालय बनने और लागत दोगुनी होने से सरकारी एजेंसी एवं ठेकेदारों के बीच घालमेल का संदेह लोगों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है. गया के 24 प्रखंडों के क़रीब तीन हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में कम से कम पांच हज़ार शौचालयों का निर्माण होना है. लेकिन, ठेका आएदिन दूसरे के हाथों स्थानांतरित किए जाने से शौचालयों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. सच कहा जाए, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण की योजना गया में पूरी तरह असफल रही है.

सीतामढ़ी: ज़मीन के अभाव में नहीं बने 92 शौचालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप देश में स्वच्छता का वातावरण निर्मित नहीं हो पा रहा है. सड़क, रेलवे स्टेशन, बाज़ार से लेकर चौक-चौराहों तक अब भी गंदगी का अंबार नज़र आता है. मोदी ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने की नीयत से प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान का श्रीगणेश किया था, जिसके तहत सीतामढ़ी को तक़रीबन चार करोड़ 29 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए. बिहार शिक्षा परियोजना की अभियंत्रण इकाई के अनुसार, सीतामढ़ी में 636 शौचालयों का निर्माण होना था, लेकिन अब तक 544 स्कूलों में ही शौचालय बन सके. 92 शौचालयों का निर्माण अभी बाकी है. शेष बचे शौचालयों के संबंध में बताया गया कि नवसृजित विद्यालयों के पास भूमि न होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका. क़रीब एक लाख 58 हज़ार रुपये प्रति की दर से बनने वाले उक्त शौचालयों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो पाएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है.

उत्तराखंड की हालत बदतर

उत्तराखंड में शौचालय निर्माण के नाम पर जमकर धांधली हुई. कई स्कूलों में पुराने शौचालयों की रंगाई-पुताई करके खानापूर्ति कर दी गई. देहरादून अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड एवं मंडी समिति के मध्य स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दो सौ से अधिक छात्र पढ़ते हैं. यह जनपद का सबसे पुराना विद्यालय है. यहां भी शौचालय के नाम पर खानापूर्ति की गई. इस विद्यालय से चार सौ मीटर की दूरी पर स्थित कन्या विद्यालय की हालत तो और भी बदतर मिली. इस विद्यालय में बीस वर्ष पूर्व बने शौचालय की दीवार पर बापू के चश्मे का चित्र उतार कर अभियान की इतिश्री कर ली गई. उत्तरकाशी एवं चमोली के दर्जन भर से अधिक विद्यालयों की बदहाली सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है. ■

(बिहार से राकेश कुमार, वाल्मीकि कुमार एवं सुनील सौरभ, उत्तर प्रदेश से प्रभात रंजन दीन और उत्तराखंड से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट)

feedback@chauthiduniya.com

लखनऊ के आसपास के शौचालयों की स्थिति

वर्ष 2010 के सरकारी आंकड़े बता रहे थे कि हरिद्वार से जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है, इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है. कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक पहुंचते–पहुंचते गंगा की हालत यह हो जाती है कि इसका पानी पीना तो दूर, नहाने लायक़ भी नहीं रह जाता. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) एक जांच प्रक्रिया है, जिससे पानी की गुणवत्ता और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है. गंगाजल के बीओडी जांच के मुताबिक़, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस में बीओडी की मात्रा 3.20 मिलीग्राम/लीटर से लेकर 16.5 मिलीग्राम/लीटर तक है, जबकि यह मात्रा 3.0 मिलीग्राम/लीटर से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.

यश भारती या पद्म पुरस्कार पाए यूपी के लोगों को मिलेंगे 50 हज़ार रुपये माहवार

बौद्धिकों के आगे पेंशन का चारा

प्रभात रंजन दीन

पुरस्कार लौटाने की नव–बौद्धिक–राजनीतिक दौड़ में लगे साहित्यकारों के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेहद कारगर चारा फेंका है. उत्तर प्रदेश में हर साल मिलने वाले यश भारती पुरस्कार पाने वाली सत्ता–चयनित हस्तियों को अब 50 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन भी मिलेगी. उत्तर प्रदेश सरकार का बाकायदा कैबिनेट के जरिए लिया गया यह निर्णय सांकेतिक चुनौती है कि अब किसी साहित्यकार या अन्य शख्सियत में दम है तो वह पुरस्कार लौटा कर दिखाए. इस युवा मुख्यमंत्री ने सस्ती राजनीति पर उतरे पकी उम्र के तथाकथित साहित्यकारों को उत्कृष्ठ कोटि की राजनीति करने की बौद्धिक–सीख दी है. पेंशन पाने वालों की जमात में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियां भी शामिल होंगी. अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को भी यह संदेश दे दिया कि जो उन्हें पहले कर देना चाहिए था, वह उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिखाया. यश भारती पुरस्कार से सम्मानित महाकवि नीरज ने पुरस्कार लौटाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों पर करारा प्रहार किया है और इसे निकृष्ट स्तर की राजनीति बताया है.

मुनव्वर राणा को पीएमओ से बुलावा

साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले उत्तर प्रदेश के शायर मुनव्वर राणा को प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया है. मुनव्वर राणा की अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी. स्पष्ट है कि इस मुलाकात में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए जाने को लेकर ही बात होगी. मुनव्वर राणा ने कहा है कि वे लेखकों की मन:स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे. उन्होंने अन्य लेखकों को भी बुलाए जाने की जरूरत पर जोर दिया.

बच्चन परिवार ने पेंशन की राशि लोकसेवा के लिए दी

उत्तर प्रदेश सरकार के यश भारती सम्मान से सम्मानित बच्चन परिवार ने 50 हजार रुपये पेंशन की राशि को लोक सेवा में लगाने की अखिलेश सरकार से अपील की है. कवि हरिवंश राय बच्चन, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन को यश भारती सम्मान से नवाजा जा चुका है. इस तरह बच्चन परिवार ने दो लाख रुपये माहवार की पेंशन राशि जरूरतमंदों के लिए खर्च करने की पेशकश की है.

उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को प्रदेश के कई बुद्धिजीवी पुरस्कारशुदा लोगों के हाथ लगा जैकपॉट बता रहे हैं. वे कहते हैं कि साहित्यकारों द्वारा सम्मान लौटाए जाने के बीच ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती और केंद्र के पद्म पुरस्कार पाने वालों को 50 हजार रुपये की मासिक पेंशन देकर उनके हाथ में जैकपॉट थमा दिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद खुद अखिलेश यादव ने मीडिया के समक्ष आकर इस निर्णय की जानकारी दी. मुख्यमंत्री से यह पूछा भी गया कि अगर कोई व्यक्ति यश भारती वापस कर दे तो भी क्या पेंशन मिलती रहेगी? मुख्यमंत्री ने बड़े सधे अंदाज में कहा कि अब ऐसी स्थिति समाजवादियों के समक्ष या सपा सरकार के समक्ष कभी नहीं आएगी. मंत्रिपरिषद में इस सिलसिले में पारित की गयी नियमावली के तहत ऐसे लोग जिनकी जन्मभूमि या कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही है और जिन्हें यश भारती और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें यह मासिक पेंशन मिलेगी. हालांकि 21 अक्टूबर को देर रात उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खास विज्ञप्ति जारी कर पेंशन की घोषणा के साथ एक शर्त संलग्न करने का ऐलान किया. नए संलग्नक के मुताबिक पेंशन उसी व्यक्ति को मिलेगी जो जरूरतमंद होंगे और इसके लिए अलग से आवेदन करेंगे.

1994 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही शुरू किए गए यश भारती सम्मान के तहत विभिन्न विधाओं की तकरीबन डेढ़ सौ शख्सियतों को अबतक सम्मानित किया जा चुका है. इनमें हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, कैफी आजमी, सोम ठाकुर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, राज बब्बर, शबाना आजमी, राजपाल यादव, जसपाल राणा, शकील अहमद, मोहम्मद कैफ, विनोद मेहता, रवींद्र जैन, अनूप जलोटा, जिम्मी शेरगिल, कैलाश खेर, राहत अली खान साबरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजन–साजन मिश्र समेत कई मशहूर हस्तियां और कई प्रायोजित हस्तियां शामिल हैं.

वर्ष 2007 में मायावती के कार्यकाल में यश भारती पुरस्कार को बंद कर दिया गया था. समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार आने के बाद वर्ष 2013 से इसे फिर से शुरू किया गया. 2013 में 15 व्यक्तियों को यश भारती सम्मान दिया गया था. वर्ष 2013–14 के लिए 22 व्यक्तियों को और वर्ष 2014–15 के लिए 34 हस्तियों को यह सम्मान दिया गया. यश भारती सम्मान के तहत पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है. जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक लाख रुपये का चेक और ताम्र पत्र दिया जाता है. साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 से ही हुई थी. बहरहाल, यश भारती सम्मान और पद्म पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्वों को 50 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का फैसला ऐसे समय में आया जब साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने की हर तरफ निंदा हो रही है. उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. यहां तक कि यश भारती सम्मान से सम्मानित महाकवि गोपाल दीस नीरज ने भी बेबाकी से कहा कि जो साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं, वे राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं. उनका ऐसा करना बिल्कुल गलत है. नीरज ने कहा, कुछ साहित्यंकार मोदी के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं. इन सहित्यकारों को कांग्रेस के राज में पुरस्कार मिला था और अब कांग्रेस ही इनसे ये पुरस्कार लौटाने का काम करा रही है. इससे कांग्रेस की ही बदनामी हो रही है. नीरज ने सम्मान लौटाने वाले उन साहित्यकारों से यह भी पूछा कि उन्होंने पुरस्कार की रकम क्यों नहीं लौटाई? नीरज बोले कि पुरस्कार लौटाने वालों में से कुछ ही लोगों ने राशि लौटाई है. अन्य सभी क्यों नहीं लौटा देते? पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार झूठ बोल रहे हैं. साहित्य की उपासना करना सत्य की उपासना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. साहित्यकारों को चाहिए कि यदि उन्हें किसी मामले का विरोध करना है तो वे कविता लिखें, कथा लिखें. गोपाल दास नीरज को पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है. उन्हें सर्वश्रेख़ गीत लेखन के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. नीरज ने कहा, मैंने भी इमरजेंसी के दौरान सत्ता का विरोध किया था, लेकिन उस वक्त मैंने कविताएं और गीत लिखे थे. इससे समाज को एक संदेश दिया था. नीरज ने कहा कि गोमांस पर विवाद नहीं होना चाहिए. भारतीय संस्कृति में गाय को माता माना गया है. कृष्ण गाय चराते थे. मां के दूध के अलावा गाय ही है जिसका दूध बच्चे से बड़ों तक को फायदा पहुंचाता है. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए. सारे विवाद ही समाप्त हो जाएंगे.

सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोते जाने पर पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों ने कहा कि देश का मुंह काला हो गया. इस पर नीरज ने कहा, मैं कहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों किया, जिससे कालिख पोती गई.

महाकवि नीरज और महाआलोचक नामवर सिंह समेत देश की तमाम नामचीन साहित्यिक–सांस्कृतिक हस्तियों के खुल कर सामने आ जाने से पुरस्कार–वापसी प्रतियोगिता बैक–फुट पर आती दिख रही है. पिछले दिनों नामवर सिंह ने स्पष्ट कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार गलत कर रहे हैं और यह कोई बौद्धिक कृत्य नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

शफ़ीक आलम

गंगा आज भी मैली है

पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी मामले के प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारे के लिए गठित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गंगा सफाई को लेकर केंद्र सरकार से सख्त लहज़े में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है. एनजीटी ने सरकार से पूछा कि वह गंगा नदी के 2500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में कोई एक जगह बताये जहां गंगा साफ़ है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी से गंगा को प्रदूषित कर रहीं औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. बहरहाल न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 5000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च करने के बाद भी गंगा की हालत बद से बदतर होती जा रही है. गंगा सफाई के प्रति सरकार के सुस्त रवैये की आलोचना करते हुए एनजीटी ने कहा कि गंगा की सफाई के सिलसिले में कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है.

इसमें कोई शक नहीं कि गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा है. गंगा न केवल एक नदी का नाम है बल्कि एक संस्कृति और तहजीब का भी नाम है. इस नदी से करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु, आशा और निराशा, ख़ुशी और गम का सिलसिला जुड़ा हुआ है. करोड़ों लोगों की यह आस्था है कि इस में एक डुबकी लगाने मात्र से उसके जन्म–जन्मान्तर का कल्याण हो जाता है. लेकिन फ़िलहाल इस नदी का वजूद खतरे में हैं. ज़ाहिर है यदि नदी का वजूद खतरे में है तो इसके किनारे रहने वाले लोग भी खतरे में हैं. यह खतरा कितना संगीन है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. हज़ारों साल से जीवनदायिनी साबित होती आ रही गंगा का पानी अब पीने योग्य तो दूर, नहाने और सिंचाई के योग्य भी नहीं बचा है. कन्नौज से लेकर कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक जहां एक तरफ गंगा के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक रसायनों की मात्रा बढ़ती जा रही है. बड़े–बड़े बांध और गंगा के किनारे बसे चमड़ा एवं रासायनिक कल–कारखानों और शहरों से निकलने वाला कचरा गंगा के पानी को ज़हर बना चुका है. ऐसा नहीं है की गंगा की सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी. और उसके बाद से कई योजनायें और भी आईं मौजूदा केंद्र सरकार ने भी नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की है. लेकिन हज़ारों करोड़ रुपये की इन योजनाओं के बावजूद गंगा मैली की मैली ही बनी हुई है.

चौथी दुनिया ने वर्ष 2010 में पिछले 25 सालों के दौरान दो गंगा एक्शन प्लान के प्रभाव का जायजा लिया था. उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों के मुताबिक गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण के केवल दो वर्षों 2005–2009 के दौरान गंगा की सफ़ाई के नाम पर 1600 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए थे. गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में 452 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह माना था कि गंगा एक्शन प्लान–1 अपने मक़सद में सफल नहीं हो सका, इसलिए 1993 में गंगा एक्शन प्लान–2 शुरू किया गया. इसके बावजूद गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही रहा. फ़िलहाल केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्ष 2014–15 के लिए 1500 करोड़ रुपये और 2015–16 के लिए 2100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. लेकिन एनजीटी की टिप्पणी के मुताबिक यथा स्थित बनी हुई है. ऐसे में इस आशंका को बल मिलता है कि गंगा की सफाई के नाम पर बनी परियोजनाओं की राशि का कहीं बंदरबांट तो नहीं हो रहा है?

वर्ष 2010 के सरकारी आंकड़े बता रहे थे कि हरिद्वार से जैसे ही गंगा आगे बढ़ती है, इसके पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटनी शुरू हो जाती है. कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक पहुंचते–पहुंचते गंगा की हालत यह हो जाती है कि इसका पानी पीना तो दूर, नहाने लायक़ भी नहीं रह जाता. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) एक जांच प्रक्रिया है, जिससे पानी की गुणवत्ता और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है. गंगाजल के बीओडी जांच के मुताबिक़, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस में बीओडी की मात्रा 3.20 मिलीग्राम/लीटर से लेकर 16.5 मिलीग्राम/लीटर तक है, जबकि यह मात्रा 3.0 मिलीग्राम/लीटर से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसका अर्थ है कि उपरोक्त जगहों पर गंगास्नान आपके जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. गंगा में प्रदूषण की जो हालत वर्ष 2010 में थी वही हालत अब भी बरक़रार है. जिन शहरों का ज़िक्र ऊपर किया गया है उन शहरों में आज भी गंगा का पानी खतरनाक हद तक दूषित है. उदहारण के लिए अप्रैल 2015 में वाराणसी में गंगा के पानी की जांच के बाद यह पाया गया कि यहां गंगा जब दाखिल होती है तो उसमें बीओडी की मात्र लगभग 3 मिलीग्राम/लीटर थी और जब यहां से बाहर निकली तो यह मात्र लगभग 5 मिलीग्राम/लीटर थी. एक रिपोर्ट के मुताबिक 6000 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) कचरे में 80 प्रतिशत कचरा अशोधित रूप में ही गंगा में छोड़ा जाता है. अकेले कानपुर में 78 से ज़्यादा ऐसे चमड़ा उद्योग हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण निर्देशों का पालन नहीं करते और रोज़ाना हज़ारों लीटर कचरा गंगा में बहा देते हैं. हालांकि एनजीटी ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि अगर चमड़ा उद्योग से नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है तो वह इसे बंद करने या कहीं और स्थानांतरण का आदेश दे सकते हैं.

गोमुख से हरिद्वार तक ही कॉलिफोर्म बैक्टीरिया की मात्रा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकतम सीमा 500 पीएन/100 मिली लीटर से ऊपर है यानि यह पानी पीने योग्य नहीं है. अब अगर गंगा की शुरुआत में ही ऐसी स्थिति है तो फिर इसे आगे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगल के प्रदूषण का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है. इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के 2012 के एक शोध के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को कैंसर का मर्ज़ होने का खतरा अधिक है. इसलिए गंगा की सफाई न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि यहां बसने वाले जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है.

बहरहाल, गंगा की सफाई को लेकर लचर सरकारी रवैया, जो गंगा एक्शन प्लान के ज़माने में था, अब भी बरक़रार है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने चुनाव भाषण के दौरान ही गंगा की सफाई पर विशेष बल दिया था. उसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की है. इस परियोजना को शुरू हुए भी एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई परिवर्तन होते नहीं दिख रहा है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती कहती हैं कि गंगा के प्रदूषण मुक्ति के संकेत अक्टूबर 2016 के बाद से मिलने शुरू होंगे. ज़ाहिर है जहां पिछली योजनायें कई वर्षों में जिस काम को पूरा नहीं कर पाईं तो केवल एक साल में किसी बड़े नतीजे की अपेक्षा करना थोड़ी ज्यादती होगी. लेकिन कार्य में प्रगति दिखनी चाहिए इसलिए एनजीटी को पहल करते हुए उत्तर भारत की इस जीवन रेखा गंगा नदी को चरणबद्ध तरीके से नया जीवन देने और इसकी पुरानी पवित्रता बहाल करने की पहल करनी पड़ रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में क़ानून-व्यवस्था हमेशा से एक अहम मुद्दा रही है. पिछले चुनाव के दौरान और उसके बाद भी राज्य में सक्रिय तक़रीबन हर राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को इतने ज़ोर-शोर से उठाया कि उसे देखते हुए इस बार कम से कम यह उम्मीद थी कि सभी नहीं, तो अधिकतर दल, खास तौर पर बड़े दल इसे नापसंद करते हुए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे. लेकिन, सच्चाई इसके ठीक उलट है. इस दलदल में सभी पार्टियां गर्दन तक डूबी हैं, चाहे वह सुशासन का दावा करने वाली हो, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली हो या फिर दूसरी पार्टियों को जंगलराज का पर्याय बताने वाली.

जीत किसी की हो, हारेगी जनता

आदित्य नारायण पाण्डेय

बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राज्य के सियासी गलियारों में राजनीतिक गरमाहट चरम पर है. बात बिहार की राजनीति पर हो और बाहुबलियों का जिक्र न आए, तो कोई भी चुनावी चर्चा अधूरी मानी जाएगी. विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, बिहार से हमेशा सदन में बाहुबलियों का प्रवेश होता रहा है. अपने ऊंचे रसूख, दहशत और आपराधिक क्रियाकलापों के दम पर वे पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जीतते रहे हैं, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद वे देश सेवा की आड़ में हमेशा अपनी सेवा करने में लगे रहते हैं. बिहार में आपराधिक प्रवृत्ति वाले दबंग राजनेताओं की एक पूरी खेप है. बिहार में बाहुबलियों के लिए किसी भी राजनीतिक दल से टिकट लेना न सिर्फ़ अपेक्षाकृत आसान है, बल्कि वे अपने खौफ और छवि के बल पर जीत की गारंटी भी देते हैं. यही वजह है कि सभी दल ऐसे उम्मीदवारों को हाथों-हाथ लेते हैं. जेल में बंद बाहुबली अपने क्षेत्र से अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतार देते हैं. इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है. चुनाव मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सभी दलों के बीच आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार मैदान में उतारने को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है. भाजपा नीतीश के नेतृत्व वाले महा-गठबंधन पर जंगलराज वापस लाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है, वहीं खुद भाजपा नेता अपनी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रहे हैं. बिहार में अपराधियों का राजनीतिक इतिहास काफी पुराना रहा है. शुरुआती दौर में रणवीर सेना और एमसीसी ने ऐसे लोगों को आश्रय दिया, बाद में यह राजनीतिक दलों के लिए एक फैशन बन गया.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीन चरणों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें उनके आपराधिक, वित्तीय एवं अन्य विवरणों का विश्लेषण किया गया है. एडीआर ने अपराध की चार श्रेणियां तय की हैं, जैसे आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले, हत्या से संबंधित मामले एवं हत्या के प्रयास आदि. बिहार इलेक्शन वॉच और एडीआर ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीन चरणों में चुनाव लड़ रहे सभी 1847 उम्मीदवारों के शपथ-पत्रों का विश्लेषण किया है, जिनमें से 531 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर पर आपराधिक और 402 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण एवं महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार आदि.

बिहार में क़ानून-व्यवस्था हमेशा से एक अहम मुद्दा रही है. पिछले चुनाव के दौरान और उसके बाद भी राज्य में सक्रिय तक़रीबन हर राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को इतने ज़ोर-शोर से उठाया कि उसे देखते हुए इस बार कम से कम यह उम्मीद थी कि सभी नहीं, तो अधिकतर दल, खास तौर पर बड़े दल इसे नापसंद करते हुए आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देंगे. लेकिन, सच्चाई इसके ठीक उलट है. इस दलदल में सभी पार्टियां गर्दन तक डूबी हैं, चाहे वह सुशासन का दावा करने वाली हो, पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली हो या फिर दूसरी पार्टियों को जंगलराज का पर्याय बताने वाली. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उम्मीदवारों द्वारा स्वघोषित आपराधिक मामलों पर एक निगाह डालना ही काफी है. जनता को अपना वोट देने का जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार उसे अपने उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का भी है. मतदाता के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि जो लोग चुनाव मैदान में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीन चरणों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें उनके आपराधिक, वित्तीय एवं अन्य विवरणों का विश्लेषण किया गया है. एडीआर ने अपराध की चार श्रेणियां तय की हैं, जैसे आपराधिक मामले, गंभीर आपराधिक मामले, हत्या से संबंधित मामले एवं हत्या के प्रयास आदि. बिहार इलेक्शन वॉच और एडीआर ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीन चरणों में चुनाव लड़ रहे सभी 1847 उम्मीदवारों के शपथ-पत्रों का विश्लेषण किया है, जिनमें से 531 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर पर आपराधिक और 402 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण एवं महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार आदि.

अगर तीन चरणों के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और उनकी दलगत स्थिति का जायजा लिया जाए, तो यह साफ़ हो जाता है कि पिछली विधानसभा की तरह आने वाली विधानसभा भी अपराधियों से मुक्त नहीं होगी. विधानसभा में आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या में बढ़ोत्तरी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. पिछले चुनाव की भांति इस बार भी आपराधिक छवि वाले बहुत सारे उम्मीदवार साफ़ छवि के उम्मीदवारों को हराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनकी जीत वास्तव में जनता की पराजय होगी. राजनीतिक दलों पर करोड़पतियों से पैसे लेकर टिकट देने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं. यह चुनाव भी ऐसे आरोपों से मुक्त नहीं है. इसमें बड़ी-छोटी सभी पार्टियां शामिल हैं. हाल में भाजपा सांसद आरके सिंह ने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों चरणों के 1847 उम्मीदवारों में से पहले चरण के 25, दूसरे चरण के दो और तीसरे चरण के 23 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं. अगर दलगत स्थिति देखी जाए, तो भाजपा के 77 में से 22 (28 प्रतिशत), जदयू के 55 में से 13 (23 प्रतिशत), राजद के 55 में से 16 (29 प्रतिशत), कांग्रेस के 21 में से छह (28 प्रतिशत) और लोजपा के 23 में से आठ (34 प्रतिशत) उम्मीदवार करोड़पति हैं. यही नहीं, ऐसे भी कई उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपनी आय एक करोड़ रुपये से अधिक घोषित की, लेकिन उन्होंने अपना आयकर रिटर्न पेश नहीं किया. विक्रम विधानसभा क्षेत्र से आईएनडी से चुनाव लड़ रहे रमेश शर्मा 928 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राह विधानसभा क्षेत्र से आईएनडी के ही उम्मीदवार डॉ. कुमार इंद्रदेव हैं, जिनकी संपत्ति 111 करोड़ रुपये है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पर्दे के पीछे के योद्धा

दिव्या त्रिपाठी

बहुत पुरानी कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है. बिहार विधानसभा चुनाव भी प्रत्याशियों के लिए किसी जंग से कम नहीं है, जिसे जीतने के लिए प्रत्येक दल हरसंभव प्रयास कर रहा है. चुनाव का शंखनाद होते ही सभी दलों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तंत्र काम में लग जाते हैं. इनमें कई ऐसे चेहरे होते हैं, जो जंग में शामिल तो रहते हैं, लेकिन कभी दिखाई नहीं देते. दरअसल, वे पर्दे के पीछे रहकर चुनाव जीतने के लिए जोर-आजमाइश करते रहते हैं और पर्दे के बाहर रहने वाले चेहरों की क़दम-क़दम पर मदद करते हैं.एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए कितने लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, उसका जायजा लेने की कोशिश हमने की.

फोन की घन-घन-घन बजती घंटी, कंप्यूटर के की-बोर्ड पर चहलक़दमी करती उंगलियां और पार्टी के झंडे-बैनर पाने-बांटने की जद्दोजहद... कुछ ऐसा ही नजारा प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यालय में देखने को मिला. कई लोग एक कमरे में तो मौजूद हैं, लेकिन बातचीत बहुत कम हो रही है. सभी अपने काम में ऐसे लगे हैं, मानो कोई मिशन चल रहा हो. पूछे जाने पर पता चला कि यह वार रूम है. अब एक चलन-सा हो गया है, वार रूम बनाने का. वार रूम में चुनाव से संबंधित आने वाली सभी छोटी-बड़ी जानकारियों का विश्लेषण कर आउटपुट निकाला जाता है. समय के साथ प्रचार-प्रसार के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है. चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्येक राजनीतिक दल में चुनाव अभियान समिति का गठन किया जाता है, महत्वपूर्ण लोगों की टीमें गठित की जाती हैं और अनुभव के आधार पर प्रत्येक नेता-कार्यकर्ता को ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है. वार रूम के सदस्य क्षेत्र में तो नहीं जाते, लेकिन चुनाव की हर गतिविधि का वे बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जिस पर आगे की रणनीति तैयार होती है. आधुनिक तकनीक ने शहरों ही नहीं, गांवों तक अपनी पैठ बना ली है. प्रत्याशी को कौन-सा मुद्दा उठाना है, कैसे प्रचार करना है और कब कहां जाना है आदि सारे कार्यों को वार रूम और विभिन्न टीमों के सदस्य ही अंजाम देते हैं.

कांग्रेस ने अपना वार रूम सदाकत आश्रम में बनाया है. वार रूम के संचालक प्रदीप चौधरी ने बताया कि उनकी टीम बंद कमरे से चुनाव का संचालन करती है. वार रूम के अंदर दो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, पहला लॉजिस्टिक और दूसरा कम्युनिकेशन. यहां दोनों को अलग-अलग रखा गया है. लॉजिस्टिक के अंदर कंट्रोल रूम होता है और कम्युनिकेशन के अंदर रिसर्च, सोशल मीडिया, जनरल मीडिया और आईटी. प्रदीप कहते हैं, पोस्टर-बैनर से लेकर को-ऑर्डिनेशन तक सारा कार्य बहुत मुश्किल हो गया है, अब बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसिजर से गुज़रना पड़ता है. चुनाव आयोग से अनुमति लेने, पोस्टर-बैनर लगवाने से लेकर प्रत्याशियों के हर गतिविधियों पर हमारी टीम काम करती है. उम्मीदवार की दिक्कतों को लेकर चुनाव आयोग से बात करना, स्टार प्रचारक को कब आना है, उन्हें क्या बोलना है आदि तय करने की सारी ज़िम्मेदारी हमारी है. तक़रीबन सौ लोग रोज इसी काम में लगते हैं. हर ज़िले में एक आईटी सेल है, जहां तीन-चार लोग उम्मीदवारों के लिए सोशल मीडिया पर काम करते हैं. फेसबुक और व्हाट्स-ऐप के ज़रिये प्रत्याशियों के संदेश जनता तक पहुंचाए जाते हैं. बैनर किसे लगाना है, हेलिकॉप्टर का प्रबंध कैसे होगा समेत प्रचार-प्रसार की सारी व्यवस्था हमें देखनी होती है. हमारी टीम को दूसरे दलों की सारी गतिविधियों पर भी ध्यान रखना पड़ता है. सुबह नौ बजे से लेकर रात नौ बजे तक और कभी-कभी इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, काम निपटाने में. प्रदीप दिल्ली से आकर यह सारा काम देख रहे हैं. वह कहते हैं कि टीम के बीच को-आर्डिनेशन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है. नेशनल मीडिया प्रभारी एवं महासचिव चंदन यादव ने कहा कि फिल्मों में हीरो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में जान डालने के लिए कई लोग पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं, ठीक वही कार्य आज वार रूम का है. प्रत्याशी जनता के सामने होते हैं और उनकी रणनीति यहां तैयार की जाती है. 2010 तक प्रचार इतनी गहराई से नहीं किया जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ गया है. खासकर युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है.

भारतीय जनता पार्टी का वार रूम प्रदेश कार्यालय के अंदर है, जहां किसी का आना-जाना प्रतिबंधित है. भाजपा की चुनावी रणनीति बिल्कुल अलग और गुप्त होती है. उसकी चुनाव अभियान समिति में तक़रीबन 50-60 लोग हैं और वार रूम में लगभग सौ लोग दिन-रात काम कर रहे हैं. चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष सूरज नंदन कुशवाहा बताते हैं कि समिति में बहुत सारे सेल हैं, जो चुनाव से संबंधित विभिन्न कार्य देखते हैं. प्रोग्राम सेल में कार्यक्रम बनते हैं, हेलिकॉप्टर सेल हेलिकॉप्टर संबंधी काम देखता है, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के लिए अलग-अलग सेल हैं. चुनाव आयोग सेल चुनाव आयोग संबंधी कार्य देखता है, मीडिया सेल मीडिया के लोगों के संपर्क में रहता है. एक सेल आने-जाने वाली ईमेल देखता है, विज्ञापनों के लिए अलग सेल है. लगभग 60 हज़ार बूथ कमेटियां ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं. भाजपा की रणनीति दूसरे दलों से अलग है. कुशवाहा कहते हैं, हमारे काम के तरीके में काफी अंतर है. जो भी लोग यहां कंप्यूटरों पर बैठे हैं, वे सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं. सारे लोग रात दस बजे तक काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को उनकी रुचि के हिसाब से काम दिया जाता है.

सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का वार रूम पहले 7, स्ट्रेड रोड में हुआ करता था, जिसे अब बदल दिया गया है. प्रशांत किशोर जदयू के वार रूम के चीफ बनकर पूरे चुनावी क्रियाकलाप की देख-रेख कर रहे हैं. उनकी टीम में 10 आईआईटी एवं आईआईएम प्रोफेशनल हैं, जो चुनाव से संबंधित हर छोटे-बड़े काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है. जदयू के लिए यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, यह वार रूम की गतिविधियां देखकर सहज ही पता चल जाता है. राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का चुनाव संचालन पार्टी के कार्यालय से हो रहा है, जहां पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की निगरानी में सारे काम संपादित किए जाते हैं. चाहे वह सोशल मीडिया का काम हो या फिर चुनाव क्षेत्र का, सभी जगह लालू प्रसाद के अपने क़रीबी लोग लगे हुए हैं. चुनावी सभाओं में क्या बोलना है, क्या संदेश देना है, यह सब खुद लालू यादव तय करते हैं. आज हर छोटे-बड़े राजनीतिक दल के पास एक वार रूम है, जहां उसकी चुनावी रणनीति तैयार की जाती है. वार रूम में दिन-रात मेहनत करने वालों को आम जनता नहीं जान पाती, जो भूख-प्यास और परिवार की चिंता छोड़कर सिर्फ़ इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वयं सहायता समूह

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का आग़ाज़ मोरारका फाउंडेशन ने वर्ष 1993 में किया था. पहले स्वयं सहायता समूह का गठन नवलगढ़ के निकट घोड़ीवारा खुर्द में हुआ था. समूहों के गठन के लिए ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण मोरारका फाउंडेशन ने नवलगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कराया. सर्वेक्षण की मदद से क्षेत्र की निर्धन महिलाओं की समस्याओं के बारे काफी जानकारी हासिल हुई. शुरू में दस गांवों में 50 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए. वर्ष 2000 में मोरारका फाउंडेशन ने नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की सहायता से 35 गांवों में 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया.

सशक्तिकरण की ओर बढ़ते क़दम

वर्ष 2012 में ज्योति स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया. मोरारका फाउंडेशन ने महिलाओं को इस समूह में शामिल होने की प्रेरणा दी. नतीजतन, 13 महिलाएं इस समूह की सदस्य बन गईं, जिनमें मुकुंदगढ़ निवासी सरोजा भी शामिल थीं. सरोजा ने समूह के ज़रिये बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लिया. उन पैसों से उन्होंने अपने पति को सब्जी का ठेला लगवाया और पांच हज़ार रुपये से अपने लिए सिलाई मशीन खरीदी और घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया.

राजलक्ष्मी मल्ल

एकता और संगठन से बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं. नवलगढ़ ज़िले की ग्रामीण महिलाएं इसी मूलमंत्र का अनुसरण कर आत्मविश्वास और सच्ची लगन के साथ स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही हैं. मोरारका फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से उनका सशक्तिकरण हो रहा है. इलाके की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये सफलता के नए मुकाम हासिल कर रही हैं. ऐसी ही एक महिला हैं नारसिंघानी गांव की प्रभाती देवी, जो पूर्व में पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद आज एक सफल डेयरी संचालक हैं. आज वह क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं. प्रभाती देवी ने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार में शिक्षा का घोर अभाव था. उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते थे. यह कहानी सिर्फ़ प्रभाती देवी की नहीं है, बल्कि समूह की ज़्यादातर महिलाओं के पति उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते थे. प्रभाती देवी ने बताया कि मोरारका फाउंडेशन ने उनके गांव की सावित्री देवी के घर पर लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई, जिसमें वह भी मौजूद थीं. तब उन्हें पता चला कि समूह द्वारा महिलाओं को ऋण दिया जाता है. बैठक के बाद मोरारका फाउंडेशन के प्रतिनिधि ने उन्हें विस्तार पूर्वक स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया-समझाया.

प्रभाती देवी बताती हैं कि मार्च 2003 में उन्हें स्वयं सहायता समूह की ओर से 25,000 रुपये का ऋण मिला, जिससे उन्होंने एक गाय खरीदी. गाय का दूध बेचने से हुई आमदनी से उन्होंने समूह का ऋण अदा कर दिया और कुछ पैसे भी बचा लिए. इसके बाद सितंबर 2009 में उन्होंने बैंक से 50,000 रुपये का ऋण लिया, जिससे कई बकरियां खरीदीं और फिर उन बकरियों का दूध बेचकर बैंक का ऋण चुकाने के साथ-साथ बचत भी की. इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया. सितंबर 2013 में उन्होंने 50,000 रुपये बैंक से और 50,000 रुपये आपसी लेन-देन के ज़रिये बतौर ऋण लिया. इन पैसों से उन्होंने गाय-बकरियों के लिए छप्पर बनवाए, चारा खरीदा और अपनी चार बीघा ज़मीन पर ट्यूबवेल लगवाया, जिससे गाय-बकरियों के घास-चारा उगाने की व्यवस्था की. आज प्रभाती देवी गाय-बकरियों का दूध और उनके बच्चे बेचकर प्रतिमाह 5,000 रुपये की बैंक किस्त चुका रही हैं तथा अपने घर का खर्च भी वहन कर रही हैं. दिन-प्रतिदिन घर की आर्थिक स्थिति में सुधार देखकर अब उनके पति भी कामकाज में हाथ बंटा रहे हैं. इसी तरह प्रेम स्वयं सहायता समूह की सदस्य प्रेम देवी ने टिफिन सप्लाई करके अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारी. उनके इस काम में एक दर्जन से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार मिला है. यह समूह टिफिन बनाकर स्कूलों एवं हॉस्टलों में सप्लाई करता है. यह टिफिन सेंटर शुरू करने में मोरारका फाउंडेशन ने काफी मदद की.

ग़ौरतलब है कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का आग़ाज़ मोरारका फाउंडेशन ने वर्ष 1993 में किया था. पहले स्वयं सहायता समूह का गठन नवलगढ़ के निकट घोड़ीवारा खुर्द में हुआ था. समूहों के गठन के लिए ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण मोरारका फाउंडेशन ने नवलगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कराया. सर्वेक्षण की मदद से क्षेत्र की निर्धन महिलाओं की समस्याओं के बारे काफी जानकारी हासिल हुई. शुरू में दस गांवों में 50 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए. वर्ष 2000 में मोरारका फाउंडेशन ने नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की सहायता से 35 गांवों में 100 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया. इसके बाद वर्ष 2003 में केयर आर्गनाइजेशन के साथ काम करते हुए 200 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया. समूह की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट, जूतियां, दरी, गलीचा, लाख की चूड़ियां, अचार, पापड़, मंगोड़ी, कपड़े के बैग एवं पायदान बनाने और सिलाई-कढ़ाई, बूंदी बांधने का प्रशिक्षण दिया गया. इससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया. वर्ष 2004 में 50 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को यूनिसेफ की सहायता से छोटे-छोटे कामों का प्रशिक्षण दिया गया.

मोरारका फाउंडेशन का लक्ष्य है कि इस काम 100 गांवों और 15 हज़ार परिवारों तक पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वयं सहायता समूह का लाभ मिल सके. मुकुंदगढ़ निवासी पूनम देवी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. वह बताती हैं कि उन्हें अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के लिए पांच हज़ार रुपये की आवश्यकता थी. अगर वह किसी साहूकार से ऋण लेने जातीं, तो उन्हें समय पर पूरा पैसा न मिलता. यदि मिल भी जाता, तो उसका सूद चुकाते-चुकाते सालों गुज़र जाते और मूल रक़म जस की तस रह जाती. समूह के माध्यम से उन्हें बैंक से तुरंत ज़रूरत भर पैसा मिल गया और उसका ब्याज भी बहुत कम था, जिसे अदा करना उनके लिए मुश्किल नहीं था. ींलिहाज़ा, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके ऋण अदा कर दिया. इसी गांव की रामा देवी बताती हैं कि उनके पति बीमार रहते हैं. वह काम कर सकने में अक्षम हैं, जिसकी वजह से घर की आर्थिक स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही थी. इसी बीच उन्हें मोरारका फाउंडेशन की मदद से चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला और वह उसकी सदस्य बन गईं. फिर उन्हें समूह ने बैंक से पांच हज़ार रुपये का ऋण दिलाया और उन्होंने उन पैसों से किराने की दुकान खोल ली. अब किराने की दुकान से उन्हें इतनी आमदनी हो जाती है कि वह बैंक का ऋण भी अदा कर रही हैं और घर का खर्च भी ठीक से चल रहा है. इसी तरह बलवंतपुरा निवासी संतोष बताती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. उनका तीन वर्षीय बेटा भी अक्सर बीमार रहता था. उनकी यह हालत देखते हुए 2009 में सलासर स्वयं सहायता समूह की बैठक में उन्हें बुलाया गया, जहां मोरारका फाउंडेशन की विनोद देवी ने स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया-समझाया. बात संतोष की समझ में आई और वह समूह की सदस्य बन गईं.

वर्ष 2012 में ज्योति स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया. मोरारका फाउंडेशन ने महिलाओं को इस समूह में शामिल होने की प्रेरणा दी. नतीजतन, 13 महिलाएं इस समूह की सदस्य बन गईं, जिनमें मुकुंदगढ़ निवासी सरोजा भी शामिल थीं. सरोजा ने समूह के ज़रिये बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लिया. उन पैसों से उन्होंने अपने पति को सब्जी का ठेला लगवाया और पांच हज़ार रुपये से अपने लिए सिलाई मशीन खरीदी और घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया. सरोजा कहती हैं कि वह और उनके पति बेरोज़गार थे, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद उन दोनों को रोज़गार मिल गया. अब दोनों की कमाई से दिन अच्छे गुज़र रहे हैं. सरोजा कहती हैं कि मोरारका फाउंडेशन ने उन्हें दूसरों की गुलामी से निजात दिलाई. सरोजा जैसी कई महिलाएं हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह की मदद से बैंक से ऋण लेकर छोटे-छोटे काम शुरू किए और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाकर आज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चमत्कारिक करियर का दिलचस्प दौर - 2

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

नरुला की पूर्व कंपनी एएआई की देल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 26 फ़ीसद हिस्सेदारी है. इंडियन एक्सप्रेस से नरुला यह स्वीकारते हुए कि वह वैष्णवी के एक निदेशक हैं, कहते हैं कि हम लॉबिंग का काम नहीं करते, बल्कि टाटा समूह के लिए जनसंपर्क का काम संभालते हैं. नरुला ने कहा कि उन्होंने जीएमआर के लिए काम नहीं किया है, इसलिए हितों के टकराव जैसी कोई बात नहीं है. नीरा ने एक और नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम था, नोएसिस स्ट्रैटिजिक कंसलटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्य काम था नीतिगत मामले संभालना. इस कंपनी में दो पूर्व नौकरशाह थे. पूर्व वित्त सचिव सीएम वासुदेव और ट्राई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप बैजल इसके संस्थापक निदेशक बने.

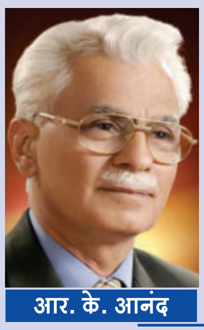

आर. के. आनंद

नीरा राडिया को यह पता होता था कि कब, किससे, कैसे काम कराना है. उसने अपने इस कौशल को पहले भी दिखाया था, जब उसने सहारा के यूके बोस एवं राव धीरज सिंह को अपने साथ मिलाया था और अनंत कुमार का इस्तेमाल किया था. यानी उसे यह अच्छी तरह से मालूम था कि किस वक्त, किससे, कैसे काम निकलवाना है. बाद में उसने (इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक) एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन एसके नरुला, जो जनवरी 2004 में सेवानिवृत्त हुए थे, को भी हायर किया. नरुला एक साल बाद वैष्णवी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बने. वैष्णवी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा के अलावा कई अन्य कंपनियों का काम संभालना शुरू किया, जिनमें यूनिटेक लिमिटेड, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और जीएमआर आदि के नाम शामिल हैं.

देल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में जीएमआर समूह की 54 फ़ीसद हिस्सेदारी है. उसने काफी कड़ी अंतरराष्ट्रीय बिडिंग (बोली) प्रक्रिया के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास का काम हासिल किया था. नरुला की पूर्व कंपनी एएआई की देल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में 26 फ़ीसद हिस्सेदारी है. इंडियन एक्सप्रेस से नरुला यह स्वीकारते हुए कि वह वैष्णवी के एक निदेशक हैं, कहते हैं कि हम लॉबिंग का काम नहीं करते, बल्कि टाटा समूह के लिए जनसंपर्क का काम संभालते हैं. नरुला ने कहा कि उन्होंने जीएमआर के लिए काम नहीं किया है, इसलिए हितों के टकराव जैसी कोई बात नहीं है. नीरा ने एक और नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम था, नोएसिस स्ट्रैटिजिक कंसलटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्य काम था नीतिगत मामले संभालना. इस कंपनी में दो पूर्व नौकरशाह थे. पूर्व वित्त सचिव सीएम वासुदेव और ट्राई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप बैजल इसके संस्थापक निदेशक बने. अपनी वेबसाइट पर नोएसिस कहती है कि उसकी टीम में सार्वजनिक एवं नियामक संस्थाओं से जुड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय एवं

ओमान सरकार ने नोएसिस को अपने यहां टेलिकॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हायर किया था. बैजल, जो भारत सरकार में विनिवेश सचिव रह चुके थे, ट्राई के एक हाई-फाई सदस्य डीपीएस सेठ को 2008 में वैष्णवी में लेकर आए. सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि नीरा के साथ डीआईपीपी के पूर्व सचिव अजय दुआ, पूर्व विमानन सचिव एएच जंग और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के पूर्व सचिव वी सुब्रह्मण्यम भी काम कर रहे थे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, वित्तीय, निवेश, नियामक और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाते रहे हैं. इस कंपनी ने टाटा टेलिसर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन, वेदांता समूह और ओमान सरकार के लिए काम किया.

सूत्र बताते हैं कि ओमान सरकार ने नोएसिस को अपने यहां टेलिकॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हायर किया था. बैजल, जो भारत सरकार में विनिवेश सचिव रह चुके थे, ट्राई के एक हाई-फाई सदस्य डीपीएस सेठ को 2008 में वैष्णवी में लेकर आए. सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि नीरा के साथ डीआईपीपी के पूर्व सचिव अजय दुआ, पूर्व विमानन सचिव एएच जंग और नवीन ऊर्जा मंत्रालय के पूर्व सचिव वी सुब्रह्मण्यम भी काम कर रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों ने 2009 में वैष्णवी के साथ काम करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद छोड़कर चले गए. इन लोगों ने नीरा को दिमाग देने का काम किया, ताकि वह टेलिकॉम, पावर और एविएशन के क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल कर सके. 2007 में टाटा ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ 240 मिलियन डॉलर का समझौता किया. इसके तहत टीसीएस बीएसएनएल को तकनीकी सहायता देती थी. बैजल तब ट्राई के चेयरमैन थे, जब टाटा और रिलायंस को वायरलेस फोन को पूर्णत: मोबाइल सेवा में बदलने की अनुमति मिली. राडिया के अन्य क्लाइंट्स यूनिटेक वायरलेस और स्वान टेलिकॉम (2-जी मामले में जांच के दायरे में) को ए राजा के मंत्री रहते हुए करोड़ों रुपये के 2-जी स्पेक्ट्रम मिले थे.

क्या नीरा की उड़ान बहुत ऊंची थी? अब नीरा के साथ क्या होगा? क्या उसे भारतीय क़ानून के तहत सजा मिलेगी? इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है. लेकिन, एक बात निश्चित है कि भारत में अभी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो जनमानस है और लोग जिस तरीके से नौकरशाह, लॉबिस्ट एवं कॉरपोरेट के गठजोड़ के ख़िलाफ़ गुस्से में हैं, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा. वह राडिया टेप ही था, जिससे लोगों को इस देश में चल रहे इस पूरे खेल का पता चला. इसके लिए हमें नीरा को धन्यवाद देना चाहिए कि यह काला सच उसकी वजह से हम सबके सामने आ सका. नीरा के साथ क्या होता है, इस वक्त यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खुलासे (राडिया टेप) के बाद अब लोग उससे बात करने से कतरा रहे हैं.

जारी...

(मशहूर वकील आर. के. आनंद क्लोज एनकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

www.kamalmorarka.com

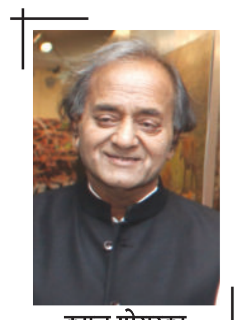

कमल मोरारका

संविधान में उल्लेखित शब्द सेकुलर का मज़ाक बनाया जा रहा है. मैं सेक्युलर शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा. संविधान क़ानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार देता है, बिना जाति, धर्म, नस्ल और समुदाय में भेदभाव के. क्या हम अभी भी ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं? यह पहला सवाल है, जिस पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को निर्णय करना चाहिए. अभी भी वे मानते हैं कि हिंदुओं का प्रभुत्व है और बाकी सब उनके अधीन हैं. उन्हें ऐसा बोलने का साहस दिखाना चाहिए.

भारत की सबसे प्रासंगिक किताब संविधान है

बिहार विधानसभा चुनाव, दलित परिवार के बच्चों की हत्या, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार, महंगाई और गोमांस खाना चाहिए या नहीं, ये सारे मुद्दे पिछले दिनों अख़बारों की सुर्खियों में छाए हुए थे. इन मुद्दों को एक-एक करके देखते हैं. पहले महंगाई की बात. यह हम सबके लिए एक सबक है कि महंगाई को चुनाव के समय बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ताकि किसी को बाद में पछताना पड़े, जैसा कि आज भाजपा के साथ हो रहा है. सभी ने देखा है, ऐसी तस्वीरें भी हैं कि कैसे हेमा मालिनी एवं भाजपा की अन्य महिला नेताओं ने आटा, सब्जी, दल की महंगी क़ीमतों के मसले पर विरोध किया था. आज जिस तरह से इन वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ी हैं, वह भाजपा के लिए शर्म की वजह है. ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती. सरकार ने छापा मारकर 35 हज़ार टन आयातित दाल बरामद की है. इसका अर्थ है कि इससे पहले तक सरकारी तंत्र निष्क्रिय था. चूंकि भाजपा व्यापारी वर्ग का समर्थन करती है, इसलिए जब भाजपा सत्ता में होगी, तो नौकरशाही उसके ख़िलाफ़ कड़े क़दम नहीं उठाएगी. लेकिन, देश में वास्तव में दाल की कमी हो गई है और पहले भी ऐसा रहा है. इसके लिए एक उचित योजना बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर साल यह समस्या सामने आती है. दाल की कमी की समस्या प्याज या अन्य सब्जियों की तरह नहीं है. यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि दाल शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है और उसकी उपलब्धता वास्तव में एक कठिन बात हो गई है. दाल की महंगाई प्रमुखता से सामने आई है. यह दो सौ रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. जितनी जल्दी गंभीर किस्म के नौकरशाह और मंत्री समूह इस मसले पर अपना दिमाग लगाकर इसका समाधान निकालें, उतना अच्छा होगा.

दूसरा बिंदु है कि संविधान अभी दबाव की स्थिति में है. संविधान में उल्लेखित शब्द सेकुलर का मज़ाक बनाया जा रहा है. मैं सेक्युलर शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा. संविधान क़ानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार देता है, बिना जाति, धर्म, नस्ल और समुदाय में भेदभाव के. क्या हम अभी भी ऐसा कर पा रहे हैं या नहीं? यह पहला सवाल है, जिस पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को निर्णय करना चाहिए. अभी भी वे मानते है कि हिंदुओं का प्रभुत्व है और बाकी सब उनके अधीन हैं. उन्हें ऐसा बोलने का साहस दिखाना चाहिए. उन्हें इस पर बहस शुरू करनी चाहिए, इसे एक संवैधानिक बहस बनने देना चाहिए. जैसे कि मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए और बिहार विधानसभा चुनाव में यह बयान गंभीरता से लिया गया. दरअसल, उनके दिमाग़ में एक ऐसा खेल चल रहा है, जिसके ज़रिये वे संविधान पर होने वाली बहस दोबारा शुरू करना चाहते हैं. ज़ाहिर है, वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे. लेकिन, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास एक मजबूत संविधान है. इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि उन्होंने एक से अधिक अवसरों पर यह कहा है कि भारत के लिए अगर कोई किताब प्रासंगिक है, तो वह है संविधान. अन्य सारी किताबें किसी खास धर्म के लिए हैं, लेकिन संविधान सबके लिए है. अब अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि संविधान की प्रभुता बनी रहे, तो उन्हें इसके लिए उपाय भी करने होंगे. उन्हें लोगों को यह बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि किसी को किसी खास दिन मांस नहीं खाना चाहिए और किसी को बीफ नहीं खाना चाहिए. यह सब संविधान में नहीं है. मांस-बीफ खाना किसी के लिए भी व्यक्तिगत मुद्दा है, आप इसे सार्वजनिक मुद्दा नहीं बना सकते. इस तरह का विमश ख़त्म करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए. खाना-पीना, टीवी-सिनेमा देखना, कपड़े पहनना आदि सरकार के लिए मुद्दा नहीं हैं.

इस चुनाव के कुछ दिलचस्प पहलू हैं. एक तो यह कि दस वर्षों के शासन के बाद भी नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एक भी आरोप नहीं है. जांच और सुबूत की बात तो छोड़िए, एक आरोप तक नहीं है. यहां तक कि भाजपा भी पूरी आक्रामकता के साथ भी सिर्फ़ यह आरोप लगा पाने की स्थिति में है कि जबसे नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं, तबसे बिहार में विकास नहीं हुआ है. ठीक है, यह एक विचार है, लेकिन नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ वह कोई आरोप नहीं लगा सकी है. यह आज की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक शख़्स दस वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और उसके ख़िलाफ़ कोई आरोप न हो, जैसा कि आजकल देखने को नहीं मिलता. यह अकेली ऐसी बात है, जो उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनने की योग्यता देती है.

इसी तरह मोदी सरकार एक और बड़ी ग़लती कर रही है. दिल्ली सरकार और शासन के मसले पर वह संविधान को दबावपूर्ण स्थिति में लाने का काम कर रही है. दिल्ली में पुलिस और भूमि का मसला उपराज्यपाल के अधीन है, लेकिन जिस तरीके से उनके द्वारा मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वह सर्वथा अनुचित है. मुख्यमंत्री पर इतना दबाव डालने का प्रयास हो रहा है, ताकि वह सब छोड़कर निकल जाएं. पुलिस कमिश्नर क्या होता है? वह हज़ारों आईपीएस अधिकारियों में से एक होता है. और, वह हर दिन एक मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है! वह अपने संबंधित मंत्री की शह मिले बिना ऐसा नहीं कर सकता. और, पूरी दिल्ली जानती है कि वह शख़्स कौन है? यह कोई अच्छी मिसाल नहीं पेश की जा रही है. यह सब आपातकाल के दौरान हुआ था. श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और उसके बाद देश को 19 महीनों तक नौकरशाहों ने चलाया. उसके बाद फिर क्या हुआ? देश और प्रशासन को नौकरशाहों से चलवा कर राजनीतिक प्रणाली हटाया नहीं जा सकती, क्योंकि भारत में लोकतंत्र जीवंत और परिपक्व है. मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को इस सबके निहितार्थ की जानकारी है या नहीं, लेकिन यह गृह मंत्रालय और गृह सचिव की ज़िम्मेदारी है कि वे इसे ठीक करें. एक पुलिस कमिश्नर को अनुशासनहीन होकर इस तरह बयानबाजी की अनुमति नहीं दी सकती और न देनी चाहिए. इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान दबावपूर्ण स्थिति में है. आरएसएस केंद्र सरकार को लड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है और केंद्र सरकार दिल्ली की राज्य सरकार को लड़खड़ाने की कोशिश कर रही है. यह सब बंद होना चाहिए.

अब सवाल आता है बिहार विधानसभा चुनाव का. चुनाव जारी है. जनता सर्वोच्च है. जो होना है, वह होगा. लेकिन, जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार अच्छा कर रहे हैं और जीतने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. इस चुनाव के कुछ दिलचस्प पहलू हैं. एक तो यह कि दस वर्षों के शासन के बाद भी नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ एक भी आरोप नहीं है. जांच और सुबूत की बात तो छोड़िए, एक आरोप तक नहीं है. यहां तक कि भाजपा भी पूरी आक्रामकता के साथ भी सिर्फ़ यह आरोप लगा पाने की स्थिति में है कि जबसे नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं, तबसे बिहार में विकास नहीं हुआ है. ठीक है, यह एक विचार है, लेकिन नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ वह कोई आरोप नहीं लगा सकी है. यह आज की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक शख़्स दस वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और उसके ख़िलाफ़ कोई आरोप न हो, जैसा कि आजकल देखने को नहीं मिलता. यह अकेली ऐसी बात है, जो उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनने की योग्यता देती है.

दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि हर कोई कहता है कि आधुनिक विमर्श में जाति की बात नहीं होनी चाहिए. टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि बिहार के युवा बोल रहे हैं कि शिक्षित लोगों के बीच अब विकास की बात है और जाति की कोई जगह नहीं है. लेकिन, सच्चाई यह है कि जाति अभी भी एक बड़ा फैक्टर है. यह परिपक्व होने का समय है. भारत में जातिवाद ग़रीबी से जुड़ा हुआ है. आप कह सकते हैं कि सवर्ण जातियों में भी ग़रीब लोग हैं और कुछ दलित भी अमीर हैं, लेकिन यह भी सच है कि सवर्णों की तुलना में पिछड़े वर्ग के लोग अधिक ग़रीब हैं. इसलिए समय के साथ जब तक सामाजिक तौर पर बदलाव नहीं आएगा, तब तक जाति एक फैक्टर रहेगा. जातिवाद ख़त्म करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि सकारात्मक रुख अपनाना या ग़रीबों के लिए ऐसे प्रावधान करना, ताकि वे आगे बढ़ चुके लोगों के बराबर पहुंच सकें. जब तक यह नहीं होता, जाति एक फैक्टर बना रहेगा. देखते हैं कि बिहार में क्या होता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

फूलन को आत्मसमर्पण करने से किसने रोका-अंतिम

सरकार की मंशा पर उठे सवाल

जो लोग घनश्याम से मिल चुके हैं, उनके अनुसार, वह बड़े-बड़े बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी रखता है. उसकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण गिरोह के लोग उसे बाबा कहते हैं. उसकी सर्वाधिक श्रद्धा अपने गांव से तीन किलोमीटर दूर पहुज नदी के किनारे बीहड़ में स्थित भैरव जी पर है. वह अक्सर वहां पूजा करता है. हाल ही में उसने वहां एक विशाल घंटा चढ़ाया था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने अपना गुस्सा भैरव तक से निकाला. वे मंदिर के पुजारी को प्रताड़ित कर घंटा ले गए. घनश्याम का ही एक ऐसा गिरोह है, जिसमें एक दंपति भी है. ये हैं पठान एवं मुन्नी बाई. इस दंपति को अपनी आठ वर्ष की मासूम बच्ची से बिछोह स्वीकार कर अपने बागी जीवन की क़ीमत चुकानी पड़ी है. वे उस अबोध बालिका का निकाह कर बीहड़ में कूद गए. पिछले दिनों जब एक-दूसरे से बिछुड़ी मां-बेटी मिलीं, तो दोनों बिलख-बिलख कर रोने लगीं. इस दंपति को गिरोह के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है. यानी वे अब पति-पत्नी संबंधों का निर्वाह नहीं करते, अलग-अलग सोते हैं.

हनुमानगढ़ी के निवासियों के अनुसार, 30 वर्षीय मुन्नी देवी घनश्याम गिरोह की सबसे शातिर डकैत है तथा घनश्याम के बाद गिरोह में उसी का सबसे अच्छा निशाना है. मुन्नी देवी फायरिंग करने में तेज होने के साथ ही एक हिम्मत वाली औरत है तथा पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह घनश्याम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती है. घनश्याम ने उसे एक राइफल दे रखी है. घनश्याम ने लोगों को बताया कि पिछले साल स्योंढा डांग में रतनगढ़ के मंदिर के पास मध्य प्रदेश पुलिस से उसकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी. तब नवरात्रि चल रही थी. मात्र तीन कारतूस ही रह गए थे. संकट में उसने देवी का स्मरण किया. तभी अचानक एक आदमी आया और उसे 11 पेटी कारतूस दे गया. घनश्याम ने न तो उस आदमी को पहले कभी देखा था, न आज तक वह दोबारा दिखाई दिया. उसने कारतूसों के पैसे तक नहीं लिए. घनश्याम का मानना है कि मां भगवती ने स्वयं उसकी रक्षा की थी. तभी से घनश्याम पूर्णत: भक्त हो गया तथा उसने भगवान के भजन-पूजन में ही शेष जीवन व्यतीत करने की कसम खा रखी है.

एक राज्य में समर्पण को बढ़ावा देकर खर्च और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा आतंक का विस्तार कम करने की कोशिशें हो रही हैं, तो पास के ही दूसरे राज्य में दमन तथा आतंक का सहारा लेकर बड़ी संख्या में डाकू बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है, जबकि दोनों ही प्रदेशों में इंका सरकारें हैं. उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री वही हों और मुख्यमंत्री ऐसी कमज़ोर आवाज़ में बोलते हैं, जैसे वह प्रशासन के कैदी हों.

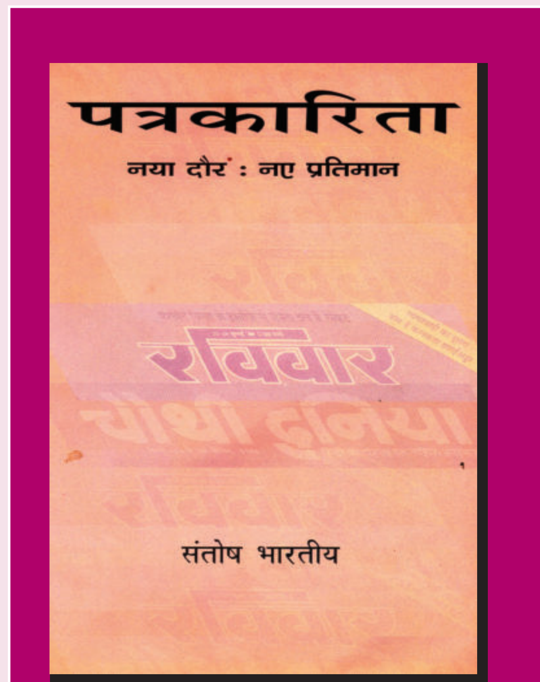

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

लेकिन, क्या घनश्याम की यह छोटी-सी इच्छा पूरी हो सकेगी? फूलन भी डकैत की क्रूर और खानाबदोश ज़िंदगी जीना नहीं चाहती. दोनों अपने अपराधों के लिए जेल की सजा काटकर सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं. लेकिन, शायद उत्तर प्रदेश सरकार यह नहीं चाहती. उसने अपना तथाकथित डकैत उन्मूलन अभियान फिर चालू कर दिया है. इसका मतलब है और अधिक मुठभेड़ें तथा इससे भी ज़्यादा, मुठभेड़ों के नाम पर और अधिक आतंक. इसके अलावा यह सवाल भी उठता है कि मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणालियां इतनी भिन्न क्यों हैं? एक राज्य में समर्पण को बढ़ावा देकर खर्च और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा आतंक का विस्तार कम करने की कोशिशें हो रही हैं, तो पास के ही दूसरे राज्य में दमन तथा आतंक का सहारा लेकर बड़ी संख्या में डाकू बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है, जबकि दोनों ही प्रदेशों में इंका सरकारें हैं. उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री वही हों और मुख्यमंत्री ऐसी कमज़ोर आवाज़ में बोलते हैं, जैसे वह प्रशासन के कैदी हों. डाकुओं के मामले में मध्य प्रदेश का प्रशासन जिस राजनीतिक दृढ़ता का परिचय दे रहा है, उसकी कमी श्रीपति मिश्र में स्पष्ट दिखाई दे रही है. यह सब आख़िर कब तक चलेगा?

फूलन के आत्मसमर्पण की शर्तें

17 नवंबर को रामपुरा (जालौन) में आत्मसमर्पण से पूर्व फूलन व घनश्याम ने लिखित रूप से जो 14 शर्तें उत्तर प्रदेश पुलिस के पास भिजवाई थीं, वे इस प्रकार हैं:-

1. मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के समक्ष ही आत्मसमर्पण कराया जाए.
2. समर्पण करने वाले बागियों को न तो मुठभेड़ दिखाकर मारा जाए तथा न ही फांसी दी जाए.
3. 1970 में समर्पण करने वाले बागियों तथा मलखान सिंह को जो सुविधाएं सरकार दे रही है, वह उन्हें भी दी जाएं.
4. जेल में उन्हें बी दर्जा दिया जाए.
5. हम लोगों को उरई जेल में ही रखा जाए.
6. हम लोगों के सारे मुक़दमों की सुनवाई उरई में ही की जाए.
7. हमें खुली जेल में रखा जाए.
8. हमारे परिवार की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए.
9. हमारे परिवारजनों तथा जिसको हम बताएं, उन्हें बंदूकों का लाइसेंस दिया जाए.
10. मुक़दमों की सुनवाई के दौरान जेल से बाहर लाने-ले जाने में हमें हथकड़ियां न लगाई जाएं.
11. बागियों की जिस भूमि पर अवैध कब्जे हो गए हैं, वह वापस दिलाई जाए तथा ग्राम सभा की भूमि अलग से दिलवाई जाए.
12. हम जब भी चाहें, हमें पैरोल पर घर आने की कड़ी सुरक्षा सहित छुट्टी दी जाए.
13. बागियों के बच्चों को शिक्षा तथा अन्य शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
14. श्री भैरव जी के मंदिर तथा हनुमानगढ़ी की समस्त ज़मीन पर किए गए कब्जों को समाप्त कराकर सारी ज़मीन मंदिर के ट्रस्ट के नाम लिखी जाए.

घनश्याम ने इन 14 शर्तों के अलावा पुलिस के समक्ष एक मौखिक शर्त यह भी रखी थी कि उसके आत्मसमर्पण के समय पत्रकारों को ज़रूर बुलाया जाए. ■

(05 दिसंबर, 1982)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

क़ादर ख़ान, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव

"फिल्मों की दुनिया या कला की दुनिया ऐसी है, जिसमें माना जाता है कि संवेदनशीलता होती है, पर यह संवेदनशीलता नकली होती है. इसीलिए जब कोई प्रसिद्धि के शिखर से हटता है, तब उसे पता चलता है कि वह किन बेरहम लोगों के बीच काम करता रहा है. अभिनेता रहमान इसके दूसरे उदाहरण हैं, अभिनेत्री विमी इसकी तीसरी उदाहरण हैं और ऐसे उदाहरणों की शृंखला भरी पड़ी है. साधना हमारे बीच में हैं, अमिता हमारे बीच में हैं, नंदा गुमनामी के अंधेरे में चली गईं और जो पुराने अभिनेता-अभिनेत्री दृश्य से हट गए, न फिल्मी मीडिया ने और न फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कभी उनकी सुधि ली."

क़ादर ख़ान 78 वर्ष के हो गए. क़ादर ख़ान हिंदुस्तान के उन चंद अभिनेताओं में हैं, जिन्होंने कॉमेडी रोल शानदार तरीके से निभाए. उन्होंने चरित्र अभिनेता के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई और वह फिल्मों में विलेन भी रहे. क़ादर ख़ान ने चार सौ से ज़्यादा फिल्मों की पटकथा लिखी, संवाद लिखे और उन्होंने छह सौ से ज़्यादा फिल्मों में काम किया. क़ादर ख़ान अपने आप में एक्टिंग का स्कूल हैं. क़ादर ख़ान की फिल्में देखकर आज के बहुत सारे अभिनेता अपनी अभिनय शैली विकसित करते हैं.

क़ादर ख़ान ने फिल्म होगया दिमाग़ का दही के ज़रिये दस वर्षों के बाद फिल्मों में वापसी की. क़ादर ख़ान ने दस वर्ष पहले फिल्में इसलिए छोड़ दी थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह टाइप्ड हो गए हैं. उन्हें प्रकाश मेहरा एवं मनमोहन देसाई जैसे फिल्मकारों ने न केवल गढ़ा, बल्कि उनकी प्रतिभा भी निखारी. इन दोनों महान निर्माता-निर्देशकों के जाने के बाद क़ादर ख़ान जीवनयापन के लिए अवश्य फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन उनका मन अपने काम से कभी भरा नहीं. क़ादर ख़ान को दक्षिण के निर्माताओं ने भी अपनी फिल्मों में सबसे ज़्यादा जगह दी और दक्षिण में बनने वाली सभी हिंदी फिल्मों के वह अभिन्न अंग हुआ करते थे.

क़ादर ख़ान ने अमिताभ बच्चन, गोविंदा एवं जॉनी लीवर को कॉमेडी के ऐसे टिप्स दिए, जो उनकी ज़िंदगी और उनके अभिनय में सौ प्रतिशत मील के पत्थर बन गए. क़ादर ख़ान साहब का ख़ुद का मानना है कि उन्हें और असरानी को मिलाकर कॉमेडी की जिस विधा का जन्म होता है, वही असल कॉमेडी है. वह द्विअर्थी भौंड़े संवादों को पसंद नहीं करते, वह उछल-कूद कर लोगों को हंसाना सही नहीं मानते. बल्कि उनका मानना है कि कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए, जिसके संवाद, व्यंग्य और रोल अदा करने वाले कलाकार का चेहरा देखकर लोग हंस पड़ें. इसीलिए आज के कॉमिक रोल करने वाले अभिनेताओं की वह आलोचना नहीं करते, लेकिन उन्हें इस बात का दु:ख अवश्य होता है कि अब कॉमेडी अपने शास्त्रीय स्वरूप में हमारे सामने नहीं आ पा रही है.

कादर ख़ान साहब ज़िंदगी के दस वर्षों तक कॉमेडी फिल्मों से दूर रहने के बाद जब वापस आए, तो उनके सामने अनुभवों का एक ख़जाना था. लोगों ने मान लिया कि क़ादर ख़ान ख़त्म हो गए हैं और उन्होंने क़ादर ख़ान से बातचीत करना बंद कर दिया. शायद यह दुनिया का दस्तूर है. जब आदमी अपने शिखर पर नहीं होता है, प्रसिद्धि से नीचे हट जाता है, चाहे वह नीचे हटना उसका खुद का चुना हुआ क्यों न हो, लोग उसके पास नहीं जाते. यह चलन हर जगह है, लेकिन फिल्मी दुनिया में यह चलन बेरहमी की हद तक है. जो लोग क़ादर ख़ान की प्रसिद्धि के शिखर के समय उनकी एक नज़र के लिए तरस जाते थे और जिन्होंने क़ादर ख़ान की वजह से अपनी ज़िंदगी में सफलताएं देखीं, वही लोग क़ादर ख़ान से काफी बुरी तरह मुंह मोड़ गए. यह दर्द क़ादर ख़ान साहब के मन में बसा हुआ है. बीमारी के दिनों में उन्हें सिर्फ़ अमिताभ बच्चन कभी-कभी फोन करके उनका हाल-चाल पूछ लेते थे.

फिल्मों की दुनिया या कला की दुनिया ऐसी है, जिसमें माना जाता है कि संवेदनशीलता होती है, पर यह संवेदनशीलता नकली होती है. इसीलिए जब कोई प्रसिद्धि के शिखर से हटता है, तब उसे पता चलता है कि वह किन बेरहम लोगों के बीच काम करता रहा है. अभिनेता रहमान इसके दूसरे उदाहरण हैं, अभिनेत्री विमी इसकी तीसरी उदाहरण हैं और ऐसे उदाहरणों की शृंखला भरी पड़ी है. साधना हमारे बीच में हैं, अमिता हमारे बीच में हैं, नंदा गुमनामी के अंधेरे में चली गईं और जो पुराने अभिनेता-अभिनेत्री दृश्य से हट गए, न फिल्मी मीडिया ने और न फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कभी उनकी सुधि ली. क़ादर ख़ान साहब कई वर्षों से बीमार हैं. उनके दिमाग़ में घुस गया कि अब उनका रोल इस दुनिया में ख़त्म हो गया है. वह एक बड़े नामी अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए, जहां नर्स ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनके घुटनों में चोट आ गई और वह व्हील चेयर पर आ गए. उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, तो वह व्हील चेयर पर ही हज कर आए और अपने में सिमट गए. ऐसे समय में फिल्म होगया दिमाग़ का दही के निर्माताओं ने उन्हें निराशा के इस भंवर से निकालने का फ़ैसला किया. सारी दुनिया में उनका इलाज हुआ, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ. लेकिन जब पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से संपर्क किया गया, तो आचार्य बालकृष्ण ने बांहें पसार कर क़ादर ख़ान साहब के स्वागत की बात कही और उन्होंने क़ादर ख़ान साहब को पतंजलि योगपीठ में आने, रहने और इलाज कराने का आमंत्रण दिया. क़ादर ख़ान साहब 14 अक्टूबर को पतंजलि योगपीठ गए और बाबा रामदेव ने ट्वीट किया कि क़ादर ख़ान साहब हमारे यहां आए हैं और हमें उन्हें ठीक करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. उन्होंने उसी ट्वीट में आशा प्रकट की कि क़ादर ख़ान साहब निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे.

क़ादर ख़ान साहब ज़िंदगी के दस वर्षों तक कॉमेडी फिल्मों से दूर रहने के बाद जब वापस आए, तो उनके सामने अनुभवों का एक ख़जाना था. लोगों ने मान लिया कि क़ादर ख़ान ख़त्म हो गए हैं और उन्होंने क़ादर ख़ान से बातचीत करना बंद कर दिया. शायद यह दुनिया का दस्तूर है. जब आदमी अपने शिखर पर नहीं होता है, प्रसिद्धि से नीचे हट जाता है, चाहे वह नीचे हटना उसका खुद का चुना हुआ क्यों न हो, लोग उसके पास नहीं जाते.

ये लाइनें मैं दशहरे के दिन लिख रहा हूं और यही क़ादर ख़ान के जन्म का दिन भी है, 22 अक्टूबर. मैं पतंजलि योगपीठ में क़ादर ख़ान साहब के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देने गया था. क़ादर ख़ान साहब ने हाथ पकड़ कर जिस भावुकता के साथ बातें कीं, उसे देखकर मुझे लगा कि चमत्कार क्या होता है. अगर इसे देखना हो, तो क़ादर ख़ान साहब को देखना चाहिए. वह क़ादर ख़ान साहब, जो फुस-फुसा कर बात करते थे, जिनकी आवाज़ गायब हो गई थी. आचार्य बालकृष्ण जी ने जब पहली बार क़ादर ख़ान साहब को देखा था, वह 14 अक्टूबर का दिन था. उस दिन क़ादर ख़ान साहब ने पहली इच्छा व्यक्त की थी कि क्या आप मेरी आवाज़ वापस दे सकते हैं? मैं उस समय वहां मौजूद था और आचार्य बालकृष्ण ने कहा, अवश्य. और, आज 22 अक्टूबर को क़ादर ख़ान साहब की आवाज़ वापस लौट चुकी है. क़ादर ख़ान साहब व्हील चेयर से हिल भी नहीं पाते थे, लेकिन आज हमने देखा कि उन्होंने अपने सहयोगी पंकज का हाथ पकड़ कर आसानी से अपने क़दम बढ़ाए. पहली बार क़ादर ख़ान साहब के मन में यह विश्वास पैदा हुआ कि मुझे जीना है और अभी फिल्में करनी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि उनका बचा हुआ जीवन वह आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव को समर्पित करते हैं. यह इलाज का चमत्कार है, यह योग का चमत्कार है, आयुर्वेद का चमत्कार है या आचार्य बालकृष्ण की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का चमत्कार है, पता नहीं, लेकिन क़ादर ख़ान साहब निराशा के भंवर से बाहर निकल आए हैं.

क़ादर ख़ान साहब विश्वास और अविश्वास के बीच में झूलते हुए पतंजलि आए थे और 27 अक्टूबर को जब वह मुंबई के लिए निकले, तो आशा से ओतप्रोत एक अलग इंसान दिखे. क़ादर ख़ान साहब को कला की दुनिया में वापस भेजने के लिए आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव को जितनी बधाई दी जाए, कम है. ■

editor@chauthiduniya.com

अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल

मेघनाद देसाई

तत्काल तर्कवादियों की हत्याएं सबसे अधिक चिंताजनक हैं. कातिलों को पकड़ने के लिए न तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकारों (जहां उक्त हत्याएं हुईं) ने कोई दिलचस्पी दिखाई. दूसरी तरफ़ मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है कि क़ानून व्यवस्था को राज्यों की ज़िम्मेदारी बनाना उनकी ज़िंदगी को वोट बैंक के जाल में फंसाना है. उन्हें यह भी मालूम है कि ज़रूरत के समय पुलिस हमेशा देर से पहुंचेगी. यानी अगर आपका वोट बैंक बड़ा नहीं है, तो आप सुरक्षित भी नहीं हैं. उदारवादी अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को चाहिए कि वे किसी भी सरकार पर भरोसा न करें. लोगों को आपातकाल का ज़माना याद होगा या उसी तरह तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी को मालूम होगा कि वोट बैंक के लिए सेक्युलर पार्टियां भी उनके लिए उतनी ही बुरी बन गई थीं.

सुधींद्र कुलकर्णी उदारवादियों के हीरो बन गए हैं. अच्छे और बुरे के एकतरफ़ा भारतीय राजनीतिक संवाद में केवल वामपंथ ही सेक्युलर या उदारवादी हो सकता है. दक्षिणपंथ के साथ खड़े होकर आप न तो उदारवादी रहते हैं और न बुद्धिजीवी. लेकिन, सुधींद्र कुलकर्णी ने उक्त सारी धारणाएं तोड़ दीं. उन्होंने स्वयं को हर रंग में रंगा है. जवानी के दिनों में वह माकपा से जुड़े थे, बाद में भाजपा में शामिल हुए. दक्षिणपंथ से जुड़ाव के बावजूद उन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं. जब नरेंद्र मोदी को भाजपा का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था, तो उन्होंने उसका खुलकर विरोध किया था. फ़िलहाल शिवसेना (जिसकी असहिष्णुता का अपना अलग नज़रिया है) द्वारा उन पर वास्तविक और प्रतीकात्मक, दोनों तरह से हमले हो रहे हैं.

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मतभेद और असहमति को प्रोत्साहित करना चाहिए. हाल के दिनों में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं द्वारा पुरस्कार लौटना स्वागत योग्य है. इससे पता चलता है कि अकादमी वास्तव में करती क्या है. सोवियत तर्ज़ के सांस्कृतिक संस्थान भारत ने अपने तरीके से अपनाए हैं. नेहरू ने अकादमियों की स्वायत्तता का विश्वास दिलाया था और एक परोपकारी तानाशाह की तरह उन्होंने खुद को ऐसी संस्थाओं का अध्यक्ष बनाया था. उनके बाद यह प्रथा समाप्त हो गई और अकादमियां नौकरशाही की तर्ज़ पर चलने लगीं. किसी भी उदारवादी लोकतंत्र में लेखकों एवं कलाकारों की स्व-शासित संस्थाएं होनी चाहिए. वे मान्यता के लिए सरकारी शब्द का प्रयोग कर लें, लेकिन उन्हें सरकारी फंड हासिल करने से परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में मान्यता के लिए रॉयल शब्द का प्रयोग होता है. यदि एक बार आपने सरकारी पैसों का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आप सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं. और, जब एक बिल्कुल अलग तरह की सरकार आ जाती है, जैसा कि भारत में हुआ, तो बहुत सारे लोग असहज महसूस करने लगते हैं. यह स्वागत योग्य है कि उन्होंने विरोध दर्ज कराया, जिसकी वजह से बहस की गुंजाइश बनी.

साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की वजह से दो मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें प्रमुख है दादरी में स्थानीय हिंदू भीड़ द्वारा अखलाक की हत्या. जहां तक मुसलमानों की हत्याओं का सवाल है, तो यह बहुत ही भयानक घटना थी. यह असहिष्णुता की पराकाष्ठा है. किसी की धार्मिक पहचान को लेकर किसी तरह की बहस के लिए कोई जगह नहीं है. अखलाक की हत्या गाय का गोश्त खाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एक मुसलमान होने की वजह से हुई थी, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमानों को अलग-थलग करने के लिए है. यह अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों ने तक़रीबन एक हज़ार साल तक भारत पर हुकूमत की. लेकिन, यदि दिल्ली सल्तनत, मुग़ल शासनकाल और उनके राज्य के भौगोलिक विस्तार के लिहाज से देखा जाए, तो यह ग़लत साबित होगा, क्योंकि किसी भी हिंदू या मुस्लिम शासक ने पूरे भारत पर हुकूमत नहीं की, दक्षिण भारत एवं असम अक्सर इससे बाहर रहे. इस नज़रिये के विपरीत सेक्युलर नज़रिये के हामियों ने भी मुस्लिम मुद्दे को ही केंद्र में रखकर इतिहास की रचना की. उन्होंने सहिष्णु मुस्लिम सम्राटों एवं उनके द्वारा स्थापित संभ्रांत संस्कृति की हिमायत की, लेकिन इन दोनों विचारधाराओं के लिए दक्षिण भारत और असम अलग देश थे. इसलिए हमें एक ऐसा नज़रिया चाहिए, जो पूरे भारत को अपने अंदर समाहित कर सके.

दरअसल, तत्काल तर्कवादियों की हत्याएं सबसे अधिक चिंताजनक हैं. कातिलों को पकड़ने के लिए न तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकारों (जहां उक्त हत्याएं हुईं) ने कोई दिलचस्पी दिखाई. दूसरी तरफ़ मुसलमानों को अच्छी तरह मालूम है कि क़ानून व्यवस्था को राज्यों की ज़िम्मेदारी बनाना उनकी ज़िंदगी को वोट बैंक के जाल में फंसाना है. उन्हें यह भी मालूम है कि ज़रूरत के समय पुलिस हमेशा देर से पहुंचेगी. यानी अगर आपका वोट बैंक बड़ा नहीं है, तो आप सुरक्षित भी नहीं हैं. उदारवादी अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को चाहिए कि वे किसी भी सरकार पर भरोसा न करें. लोगों को आपातकाल का ज़माना याद होगा या उसी तरह तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी को मालूम होगा कि वोट बैंक के लिए सेक्युलर पार्टियां भी उनके लिए उतनी ही बुरी बन गई थीं. लिहाज़ा यह कहा जा सकता है कि केवल सिविल सोसायटी अभिव्यक्ति की आज़ादी की ज़मानत दे सकती है, राजनीतिक दलों से उम्मीद करना बेकार है. ■

feedback@chauthiduniya.com

खुरासानी अजवाइन कफघ्न, श्वास-हर, हृदयावसादक और कामावसादक है. शामक होने से वस्तिशोधक, अश्मरी, हस्ति मेह आदि विकारों में तथा शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, रज:कृच्छ्रता, प्रदर तथा अनियमित मासिकधर्म में यह लाभकर है. अतिकामवासना को शांत करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं. खुरासानी अजवाइन निद्राजनक तथा अल्प मूत्रल होती है. थोड़ी मात्रा में प्रयोग करने से यह हृदय की गति को धीमाकर उसे बल देता है. लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन हृदय के लिए हानिकारक होता है. इसकी अवसादक क्रिया मस्तिष्क, जननेन्द्रियों और आंतों पर मुख्य रूप से होती है.

अजवाइन खुरासानी

खुरासानी अजवाइन भारतवर्ष में कश्मीर से गढ़वाल तक 2700-3000 मी की ऊंचाई तक पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के खेतों में यह उगाई जाती है. अरबी और फारसी में जिसे बज़्रुल बन्ज कहते हैं तथा जिसे खुरासान या पर्सिया (ईरान) से भारतवर्ष के वैद्यगण औषधि कार्य हेतु मंगाया करते थे. उसे अजवायन की एक जाति मान कर ही उसका नाम खुरासानी अजवायन या पारसीक यवानी रख दिया गया.

बाह्यस्वरूप

खुरासानी अजवाइन का पौधा अजवाइन के पौधों से कुछ बड़ा, वर्षायु या द्विवर्षायु होता है. इसकी मूल तंतुयुक्त तथा तना गोल, सीधा और पुष्ट होता है. इसके पत्र लंबे-चौड़े, भिन्न-भिन्न प्रमाण के, किनारे कटे हुए, हरे रंग के रोमश होते हैं. शाखाओं पर भी रोम होते हैं. पुष्प गुच्छ पीताभ हरे रंग से बैंगनी रंग की रेखाओं से युक्त होते हैं. इसके फल छोटे-छोटे, 1.3 सेमी व्यास के होते हैं. फलों के प्रत्येक कोष में लाल मिर्च जैसे चपटे वृक्काकार अजवाइन से दुगने श्यामवर्ण के बीज होते हैं.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

1. खुरासानी अजवाइन कफघ्न, श्वास-हर, हृदयावसादक और कामावसादक है. शामक होने से वस्तिशोधक, अश्मरी, हस्ति मेह आदि विकारों में तथा शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, रज:कृच्छ्रता, प्रदर तथा अनियमित मासिकधर्म में यह लाभकर है. अतिकामवासना को शांत करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं. खुरासानी अजवाइन निद्राजनक तथा अल्प मूत्रल होती है. थोड़ी मात्रा में प्रयोग करने से यह हृदय की गति को धीमाकर उसे बल देता है. लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन हृदय के लिए हानिकारक होता है. इसकी अवसादक क्रिया मस्तिष्क, जननेन्द्रियों और आंतों पर मुख्य रूप से होती है.

2. पत्र एवं बीज-तिक्त, प्रशामक, तापजनक, मादक, वेदनाहर, शोथरोधी, कृमिरोधी, आमाशयिक सक्रियता वर्धक, हृदयबलकारक, कपनिस्सारक, उद्वेष्टरोधी, केशघ्न, तारिका विस्फारक, बलकारक, प्रत्यूर्जतारोधी, सूक्ष्मजीवाणुरोधी तथा वेदनाहर होता है.

3. पत्र-सार एवं मूलार्क-आक्षेप, मनोविभ्रंश, हिक्का आंत्रगत क्षोभ, फुफ्फुस-क्षोभ, जननांगगत-क्षोभ, मानसिक उत्तेजना, स्नायुशूल, हत्पीड़ा तथा उद्वेष्टयुक्त कास में हितकर है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग:

1. खालित्य- खुरासानी अजवाइन के बीच स्वरस का सिर पर लेप करने से गंजेपन में लाभ होता है.

नेत्र रोग:

1. जलस्राव-2-3 ग्राम खुरासानी अजवाइन के बीजों को कूटकर रात को 100 मिली पानी में भिगो दें. प्रात: पानी से आंख को धोने से आंख से पानी गिरना तथा अन्य नेत्ररोगों में लाभ होता है.

2. खुरासानी अजवाइन के पत्तों को गर्म करके आंख के ऊपर बांधकर रखने से आंखों की सूजन व पीड़ा में लाभ होता है.

कर्ण रोग:

1. कर्णशूल- खुरासानी अजवाइन से पके तिल के तैल को कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान का दर्द मिटता है.

2. खुरासानी अजवाइन के पुष्प स्वरस को कान में डालने से कान के दर्द में लाभ होता है.

मुख रोग:

1. दंतशूल- खुरासानी अजवाइन के पत्रक्वाथ का कवल एवं गण्डूष धारण करने से दांत के दर्द तथा मसूड़ों से होने वाले रक्तस्राव में लाभ होता है.

वृक्ष रोग:

1. श्वास- 5 मिली पत्र-स्वरस में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वास कष्ट तथा कुक्कुर कास में लाभ होता है.

उदय रोग:

1. उदर शूल-खुरासानी अजवाइन में गुड़ मिलाकर गोली बना के देने से पेट की पीड़ा मिटती है. इसके 1-2 ग्राम चूर्ण में 250 ग्राम मिग्रा काला नमक मिलाकर खिलाने से भी लाभ होता है.

2. 2-4 बूंद खुरासानी अजवाइन तैल को एक ग्राम सोंठ चूर्ण में मिलाकर खाने से तथा ऊपर से 15-20 मिली गर्म सौंफ का अर्क पिलाने से उदर पीड़ा शांत हो जाती है अथवा इसके 10-20 मिली क्वाथ में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिलाएं .

3. कृमि-विकार- जिस रोगी के पेट में कीड़े हों, वह सुबह ही 5 ग्राम गुड़ खाकर, कुछ समय बाद खुरासानी अजवाइन के 1-2 ग्राम चूर्ण को बासी पानी के साथ सेवन करें. इससे आंतों में स्थित कीड़े बाहर निकल जाते हैं.

यकृत्प्लीहा रोग:

1. यकृत् पीड़ा- खुरासानी अजवाइन के तेल को छाती तथा उदर पर लेप करने से पुरानी यकृत् की पीड़ा तथा छाती के दर्द में बहुत लाभ होता है.

2. शराब के साथ खुरासानी अजवाइन पीसकर उदर के ऊपर लेप करने ये यकृत् शूल और शोथ का शमन होता है.

वृक्कवस्ति रोग:

1. मूत्र रोग: 15-20 बूंद बीज सत्त को दिन में 3-4 बार देने से मूत्रेन्द्रिय सम्बन्धी पीड़ा, पथरी इत्यादि रोगों में मूत्र विरेचन होकर शांति मिलती है.

प्रजननसंस्थान रोग:

1. गर्भाशय की पीड़ा- गर्भाशय की पीड़ा मिटाने के लिए खुरासानी अजवाइन की बत्ती बनाकर योनि में रखनी चाहिए.

2. स्तनशोथ- खुरासानी अजवाइन के पत्रों को पीसकर लेप करने से स्तन की सूजन में लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग:

1. सन्धिवात- खुरासानी अजवाइन के बीज को तिल के तैल में सिद्ध कर मालिश करने से सन्धिवात, गृध्रसी, कमर दर्द इत्यादि रोगों में लाभ पहुंचता है.

2. आमवात- खुरासानी अजवाइन के पत्र एवं बीज से सिद्ध तैल का लेप करने से तथा सूजन-युक्त स्थान पर पत्र कल्क का पुल्टिस बांधने से आमवात तथा वातरक्तजन्य शोथ एवं शूल में लाभ होता है.

त्वचा रोग:

1. दद्रु- राल, टंकण, गंधक तथा खुरासानी यवानी से बनी वटी के जल के साथ घिस कर लेप करने से दाद में लाभ होता है.

मानस रोग:

1. आवेश रोग-20-25 मिली जल में 5-10 बूंद खुरासानी अजवाइन बीज तैल को मिलाकर पिलाने से स्त्रियों का हिस्टीरिया रोग तथा शूल में लाभ होता है.

प्रयोज्यांग: पत्र, पुष्प एवं बीज

मात्रा: बीज चूर्ण 200-400 मिग्रा, जल सार 3-6 बूंद, शुष्क सार 15-60 मिग्रा, मूलार्क-3-6 बूंद. केवल चिकित्सक के परामर्शानुसार ही सेवन करें.

विषाक्तता:

1. अतिमात्रा में प्रयोग करने से भ्रम, गले की सूजन, उन्माद, सन्यास तथा शरीर में खून की कमी एवं शिथिलका उत्पन्न होती है.

2. इसको अतिमात्रा में प्रयोग करने से हृद् अतालता, प्रलाप, मूत्र त्याग में कठिनता, त्वक् रक्तिमा, भ्रम, तंद्रा , तारिकाविस्फारक, कब्ज हृत्क्षिप्रता, दृष्टिविकार एवं मुखशोष हो सकता है.

3. इसका सेवन आंत्रवृद्धि, आंत्रावरोध, अधिमन्थ एवं फुफ्फुसशोथ में निषिद्ध है.

4. अतिमात्रा में सेवन करने से उत्पन्न होने वाले विकारों की चिकित्सा- आमाशय प्रक्षालन करके गोदुग्ध या अजादुग्ध का सेवन कराएं. ■

आचार्य बालकृष्ण

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

भ्रष्टाचार को ऐसे दूर करें

अगर आप भ्रष्टाचार का पता लगाना चाहते हैं, अगर आपको किसी सूचना की दरकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इस भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस अंक में हम इससे संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

भ्रष्टाचार से सम्बंधित शिकायतों की स्थिति

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक ....से .... के बीच प्राप्त की गई शिकायतों का संक्षिप्त विवरण, क्या शिकायत गुमनाम थी, शिकायत की तिथि, उन अधिकारियों या प्राधिकरण का पूरा विवरण (नाम, पद तथा संपर्क का पता आदि) जिसके ख़िलाफ शिकायत की गई है.

2. उपर्युक्त में से कौन सी शिकायतें तुरन्त ख़ारिज़ कर दी गई तथा कौन सी आगे की जांच के लिए स्वीकार की गईं. केस के अनुसार शुरूआती जांच की तिथि या ख़ारिज करने का संक्षिप्त कारण का विवरण भी दें.

3. आगे की जांच के लिए स्वीकार की गई शिकायतों में से कितने मामलों में जांच बन्द हो चुकी है? प्रत्येक के बन्द होने का संक्षिप्त विवरण दें.

4. विभिन्न कानून, नियम, निर्देश, प्रकिया, मैन्युअल आदि के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद कितने समय बाद जांच पूरी हो जाती है. कृपया ऐसे दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं, जिसमें शिकायत प्राप्ति से लेकर उस पर कार्रवाई और दण्डारोपण तक के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का वर्णन हो.

5. दिनांक.............से अब तक आयोग को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उनमें से कितनी तत्काल ख़ारिज कर दी गईं तथा कौन-कौन सी आगे की जांच के लिए रखी गईं? जांच के लिए रखी गईं शिकायतों में से कितनी शिकायतों की छानबीन में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार

RIGHT TO INFORMATION

अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयाविधि के अन्तर्गत हस्तानतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

भले ही नेपाल भारत का कई दशकों से सहयोगी रहा है, लेकिन भारत को यह समझना होगा कि यह समस्या नेपाल की जनता की है. इसका समाधान भी उन्हें और वहां की सरकार को करना है. ऐसे में भारत को उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए. भारत नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक रहा है. भारत की कोशिशों से ही नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और माओवादी एक साथ आकर लोकतांत्रिक संविधान बनाने केलिए तैयार हुए थे. भारत नेपाल के साथ सिर्फ सीमा ही नहीं, संस्कृति भी साझा करता है. भारत की चिंता खास कर मधेशियों और जनजातीय लोगों केअधिकारों के हनन को लेकर है.

भारत-नेपाल सीमा पर नाकाबंदी

नेपाल कहीं चीन की गोद में न बैठ जाए

चौथी दुनिया ब्यूरो

नेपाल में 20 सितंबर को नए संविधान के लागू होने के बाद भारत से उसके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. ऐसे में, सवाल उठ रहे हैं क्या नेपाल पर चीन का असर बढ़ेगा. नेपाल को भारत का सबसे करीबी देश माना जाता रहा है, लेकिन जबसे नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई है, तब से वहां भारत के प्रति अविश्वास की भावना प्रबल होती चली गई. इस मौके का फायदा चीन ने बखूबी उठाया और वहां अपनी जड़ें मजबूत करने का हर संभव प्रयास किया. वह अपनी कोशिशों में काफी हद तक सफल भी रहा. हालांकि, भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन किया था, लेकिन उसका यह निर्णय उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है. वाम दलों के वहां की सत्ता में आने के बाद माओवादियों का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा हो गया. भारत ने इसे साधने की हर संभव कोशिश की लेकिन परिस्थितियां लगातार भारत के विपरीत ही होती चली गईं. संविधान के विरोध में मधेशियों के आंदोलन की वजह से भारत से नेपाल होने वाले सामान की आवाजाही पर रोक लग गई है. इससे वहां की जनता परेशान हो गई है. इसके बाद वहां की स्थानीय मीडिया में खबरें आ रही हैं कि चीन नेपाल की आपात मदद करने की तैयारी में है. ऐसे में नेपाल में एक समुदाय भारत का विरोधी है और दूसरा चीन का.

नए संविधान लागू होने के बाद भारतीय मूल के मधेशी नेपाल में दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं. हालांकि मधेशी अपने अधिकारों को लेकर संविधान के लागू होने से पहले ही आंदोलन कर रहे थे. उनका मानना है कि नए संविधान में मधेशियों के अधिकारों को नज़र अंदाज किया गया. भारत सरकार ने भी मधेशियों की मांग को जायज ठहराते हुए नेपाल सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया. मधेशियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए संविधान के लागू होने के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष दूत के रूप में विदेश सचिव एस जयशंकर को काठमांडू भेजा. नेपाल पहुंचे जयशंकर ने नेपाल के नेताओं से मिलकर कहा कि जब तक मधेशियों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक उन्हें संविधान के लागू होने की घोषणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने भारत के अनुरोध को नकारते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और संविधान को लागू कर दिया.

इसके बाद तराई इलाके में संविधान को लेकर विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. ऐसे में भारत-नेपाल सीमा से किसी भी तरह के सामान की आवाजाही पर रोक लग गई. भारत से किसी भी तरह का सामान नेपाल नहीं जा पा रहा है. नेपाल पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर अनाज व अन्य उत्पादों के लिए भारत पर निर्भर है, ऐसे में वहां त्यौहारों के समय आवश्यक पेट्रोल और रसोई गैस सहित कई उत्पादों की कमी हो गई, जिसका सीधा असर पूरे देश के लोगों के रोजमर्रा के काम पर पड़ने लगा है. समस्या को बढ़ता देख नेपाल के नवनियुक्त उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा भारत के दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाक़ात की. नई दिल्ली आए थापा ने अपने देश के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में सुषमा को बताया और वहां चल रहे गतिरोध का जल्दी ही हल निकालने की आशा जताई. उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार तराई में सक्रिय मधेशी संगठनों से चर्चा को राजी हो गई है. यही नहीं सरकार ने मधेशी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित भी किया है. उन्होंने इस बातचीत के लिए भारत से मदद भी मांगी, जिस पर भारत ने कहा कि वह हर संभव मदद के लिए तैयार है. भारत ने थापा से कहा कि नेपाल तराई क्षेत्र सहित देश की मौजूदा चुनौतियों से जितनी जल्दी संभव हो जिम्मेदारी-पूर्वक निपटे. थापा ने भारत की ओर से होने वाली आपूर्ति, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों में अवरोध पर चिंता जताई, जिस पर सुषमा स्वराज ने उनसे कहा कि कमी या बंदी नेपाली पक्ष के असंतुष्ट तबके द्वारा पैदा किए गए अवरोधों के कारण है. लेकिन सोशल मीडिया में इसे नेपाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारत द्वारा लगाया गया अघोषित आर्थिक प्रतिबंध बताया जा रहा है. इस वजह से नेपाल में भारत विरोधी स्वर प्रबल होते जा रहे हैं. इसके पीछे भी चीन का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है. भारत सरकार ने भी भारत विरोधी भावनायें भड़काने वालों पर लगाम लगाने का अनुरोध भी कमल थापा से किया है.

नए संविधान लागू होने के बाद भारतीय मूल के मधेशी नेपाल में दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं. हालांकि मधेशी अपने अधिकारों को लेकर संविधान के लागू होने से पहले ही आंदोलन कर रहे थे. उनका मानना है कि नए संविधान में मधेशियों के अधिकारों को नज़र अंदाज किया गया. भारत सरकार ने भी मधेशियों की मांग को जायज ठहराते हुए नेपाल सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया.

भले ही नेपाल भारत का कई दशकों से सहयोगी रहा है, लेकिन भारत को यह समझना होगा कि यह समस्या नेपाल की जनता की है. इसका समाधान भी उन्हें और वहां की सरकार को करना है. ऐसे में भारत को उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए. भारत नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना का समर्थक रहा है. भारत की कोशिशों से ही नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और माओवादी एक साथ आकर लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए तैयार हुए थे. भारत नेपाल के साथ सिर्फ सीमा ही नहीं, संस्कृति भी साझा करता है. भारत की चिंता खास कर मधेशियों और जनजातीय लोगों के अधिकारों के हनन को लेकर है. मधेशी भारतीय मूल के हैं और वे भारत की सीमा से लगे इलाकों में रहते हैं. बिहार के सीमावर्ती इलाकों से मधेशियों के घनिष्ट संबंध हैं. दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध भी होते हैं. ऐसे में यदि दक्षिणी नेपाल में हिंसा का दौर शुरू होगा, तो इसका उत्तर भारत पर भी व्यापक असर हो सकता है. जिसका अप्रत्यक्ष रूप से फायदा चीन को होगा.

नाकेबंदी की खबरों की इतना ज्यादा असर हुआ कि भारत सरकार को यह बयान देना पड़ा कि किसी प्रकार की आर्थिक नाके-बंदी नहीं की गई है, महज सुरक्षा कारणों से कुछ वाहनों को सीमा पर रोक दिया गया था. कुल मिलाकर मौजूदा दौर में भारत को अपनी ओर से कोई भी कदम बहुत सोच-समझ कर उठाना होगा, न कि उत्तेजना में. विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि भारत सरकार बिहार विधानसभा चुनावों तक नेपाल में संविधान की घोषणा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि यदि बिहार में भाजपा जीत जाकर आएगी, तो उसे मधेश को सामने रख कर कई प्रावधानों को संविधान में शामिल करवाने में आसानी हो सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

मधेशियों के अलावा महिला समूह इस बात को लेकर संविधान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई नेपाली महिला किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ विवाह करती है तो उसकी संतान को नेपाल की नागरिकता तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसका पति नेपाली नागरिक नहीं बन जाता. वहीं दूसरी तरफ यदि बच्चों का पिता नेपाली है तो मां के नेपाली नागरिक होते बगैर ही उनके बच्चों को नेपाल की नागरिकता मिल जाएगी. पूर्व के तराई इलाके में रहने वाले मधेशी समुदाय के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है. पीढ़ियों से दोनों तरफ के लोगों के बीच पारिवारिक संबंध हैं. इनका आरोप है कि इनके साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है और इन्हें स्वाकार्यता नहीं मिली है. नागरिकता के इस प्रावधान की वजह से उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी. इस प्रावधान का असर उनके सामाजिक संबंधों पर पड़ेगा.

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब तक भारत इस बात पर पुनर्विचार नहीं करेगा कि उसे नेपाल के अंदरूनी मसलों में कहां तक हस्तक्षेप करना है, तब तक यह समस्या बनी रहेगी. भारत की ओर से अनौपचारिक नाके-बंदी से नेपाल के पहाड़ी और मधेसी दोनों मुश्किल में हैं. भारत-नेपाल सीमा पर अघोषित आर्थिक नाके-बंदी के चलते नेपाल में ईंधन संकट गहरा गया है. नेपाल जिस तरह के संकट में अभी फंसा है, उसके पास इसका कोई तात्कालिक समाधान नहीं है. नेपाल के कुछ अधिकारियों के अनुसार भारत से समझौता होने की स्थिति में भी नेपाल चीन के रास्ते ज़रूरी सामानों को आयात करने की योजना पर आगे बढ़ेगा. वह भविष्य में इस तरह की परेशानी में नहीं फंसना चाहता है. नेपाल सरकार आगे क्या फैसला करती है और किस राह पर चलती है, इस पर भारत सरकार का आगे का रुख़ निर्भर करता है. लेकिन भारत किसी भी परिस्थिति में एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहेगा. ■

navinonline2003@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

ख़ून से नहाती थी बाथरी

एलिजाबेथ बाथरी स्लोवेनिया के अपने महल में रहती थी और वही सारी घटनाओं को अंजाम दिया करती थी. एलिजाबेथ बाथरी का दिमाग़ी फितूर था कि यदि वह कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान करेगी, तो वह हमेशा जवान बनी रहेगी.

दुनिया की सबसे खूंखार महिला सीरियल किलर में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वह एलिजाबेथ बाथरी का है. आज भी एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे ख़तरनाक और वहशी सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है. सन् 1585 से लेकर सन् 1610 तक एलिजाबेथ बाथरी ने अपनी जवानी को हमेशा के लिए जवा रखने के लिये 600 से भी ज्यादा महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया. लोवानिया के चास्चिस शहर में एलिजाबेथ बाथरी हंगारी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बाथरी परिवार से ताल्लुक रखती थीं. एलिजाबेथ बाथरी की शादी फ्रेंक नैडेस्डी नाम के एक शख्स से हुई थी और वह तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का राष्ट्रीय हीरो था. जब तक फ्रेंक नैडेस्डी जिंदा था, तब तक एलिजाबेथ बाथरी लड़कियों को बेहरहमी से मारकर उनके खून से स्नान करती थी. एलिजाबेथ बाथरी स्लोवेनिया के अपने महल में रहती थी और वही सारी घटनाओं को अंजाम दिया करती थी. एलिजाबेथ बाथरी का दिमाग़ी फितूर था कि यदि वह कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान करेगी, तो वह हमेशा जवान बनी रहेगी. उसके इसी फितूर ने उसे दुनिया की नंबर एक सीरियल किलर बना दिया था. उसके इस घिनौने अपराध में उसके तीन नौकर भी हमेशा उसका साथ देते थे. चूंकि एलिज़ाबेथ बाथरी एक रसूखदार परिवार से आती थी इसलिये वह आसपास के गांवों की ग़रीब लड़कियों को पैसों का झांसा देकर उन्हें पहले अपने महल में बुलाती और फिर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देती. महल में आई लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता, उनकी बुरी तरह पिटाई की जाती और अंत में उन्हें मार दिया जाता था. एलिजाबेथ बाथरी के जुल्म का आलम यह था कि वह कई बार लड़कियों के चेहरे या शरीर के दूसरे अंगो का मांस दांतों से काटकर निकाल लेती थी और अंत में उसके नौकर लड़कियों के खून को उस टब में इकट्ठा कर देते थे, जिसमें एलिजाबेथ बाथरी स्नान करती थीं. शुरुआत एलिजाबेथ ग़रीब परिवार की लड़कियों को ही अपना निशाना बनाती थी, लेकिन जब इलाके में उसे लड़कियों की तादाद घटती नज़र आई तो उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरु कर दिया. कभी-कभी एलिजाबेथ चुंगल से कुछ लड़कियां निकलकर भागने में कामयाब भी हो जाती थीं. सन् 1610 में जब गांव वालों को एलिजाबेथ के इन कारनामों का पता चला तो उन्होंने हंगारी के राजा से इसकी शिकायत की. परिणामस्वरूप हंगारी के राजा ने सत्य की जांच के लिए अपने लोगों का एक दल भेजा. जांच के दौरान महल में लड़कियों की कई सड़ी हुई लाशें तथा कई ज़िंदा लड़किया बेड़ियों में जकड़ी हुई मिलीं. एलिजाबेथ के चुंगल से बच निकली लड़कियों के बयान के आधार पर जांच दल ने एलिजाबेथ के साथ उसके तीनों नौकरों को गिरफ्तार कर लिया. तीनों नौकरों को तो मौत की सजा दे दी गई पर एलिजाबेथ बाथरी को उसके खानदानी रसूख की वजह से मौत की तो नहीं दी गई, लेकिन उसे उसी के महल के एक कमरे में हमेशा के लिए क़ैद कर दिया गया. इसके चार साल बाद 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ की मौत हो गई.इस तरह से खतरनाक सीरियल किलर एलिजाबेथ बाथरी के घिनौने अपराधों का अंत हुआ. 25 साल की हैवानियत के दौरान उसने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन यह संख्या 300 से लेकर 650 के आसपास बताई जाती है. कहा जाता है कि आयरलैंड के उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने एलिजाबेथ बाथरी के विषय से प्रेरित हेकर 1897 में ड्रैकुला उपन्यास लिखा था. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

नवाज़ शरीफ को जॉन केरी की फटकार

आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर भरी सभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कड़ी फटकार झेलने पड़ी. उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने डांटा. दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए थे. वहां उन्होंने आतंकवाद और कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पाक स्थित लश्कर-ए-तैयबा और अफ़ग़ानिस्तान स्थित हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उन्हें सबके सामने फटकार लगाई. तो एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वहीं पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया. कैरी की ओर से नवाज को यूं सबके सामने डांट पड़ती देख पाकिस्तानी पत्रकार समी अब्राहम ने इसका विरोध किया. समी ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री को मीडिया के सामने नवाज शरीफ की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए. हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार का यह कदम उनके ख़िलाफ गया और अमेरिका में उनका विरोध हुआ.

आतंकवाद पर नकेल कसने को लेकर कैरी ने पहले भी शरीफ से कहा था कि वह हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार आतंकी संगठन पर कड़ी कार्रवाई करें. हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. ■

राष्ट्रपति पद की दौड़ में नहीं शामिल होंगे बिडेन

अमरीका के उप-राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा कि वह 2016 में होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी केउम्मीदवार की दौड़ में शामिल नहीं होंगे. जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने यह फ़ैसला इस साल की शुरुआत में उनके बेटे बीयू की कैंसर की वजह से हुई मौत की वजह से लिया. बेटे की मौत के शोक की वजह से उनके पास प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है. उन्होंने कहा वह उम्मीदवार नहीं होंगे लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव के प्रचार में सक्रिय रहेंगे. बिडेन ने जब यह ऐलान किया तब राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस केरोज़ गार्डन में उनकेसाथ मौजूद थे. बिडेन कहा कि डेमोक्रेट्स के लिए बराक ओबामा की विरासत को पीठ दिखाना एक ग़लती होगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

सबसे अच्छा होगा-सुबह बैठकर कुछ समय बाबा का ध्यान करना, सामान्य रूप से जो पूजा करते हैं, पूजा करना, पर उनको घर के एक सदस्य के रूप में हर बात में प्यार से रखना, जो भी खाते हैं वो मन से खिलाना, जो भी पहनते हैं उनको देना, सुख में उनका ध्यान करना और दुख में भी उनके विषय में सोचना-यह एक अविच्छिन्न पूजा होगी. एक घंटा या 15 मिनट पूजा करने से बहुत कुछ नहीं होता. बाबा को हर समय भाव में रखना ही हर समय की पूजा है-यह सहज पूजा होती है. बाबा को प्यार करना ही बाबा की पूजा है.

साईं वंदना

बाबा ही हमारे ध्येय हैं

सद्गुरु की भगवान की तरह पूजा करने की आवश्यकता नहीं है. जब निराकार ईश्वर को जानते नहीं हो, उन्हें देखा नहीं है, समझा नहीं है तो भाव कहां आएगा?

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

एक आम इंसान को बाबा की पूजा कब और किस विधि के अनुसार करनी चाहिए?

ईश्वर की पूजा इसलिए की जाती है कि हम ईश्वर के समीप जा सकें, क्योंकि हम तो ईश्वर के एक रूप तो हैं और ईश्वर हमारे समीप भी हैं, हमारे अंदर हैं, पर निकट का वह ईश्वर जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं. उनको ज्यादा और धीरे-धीरे एक सम्पूर्ण एवं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें. पूजा और विधि एक मार्ग है उन तक पहुंचने के लिए, ध्येय नहीं. ध्येय को निश्चित कर अपने अंदर जागृत ज्योति को सद्गुरु या ईश्वर की ज्योति से जोड़ने का प्रयत्न करें. जब तक हमारे शरीर एवं मन का आकर्षण पूरी तरह नहीं कट जाएगा, जब तक वह हमको छोड़ेगा नहीं, तब तक उस ज्योति की पूरी किरण नहीं आएगी. ज्योति की उस किरण पर जैसे परदे पड़े हुए हैं-मन, शरीर, अहंकार आदि के. इसलिए पूजा जो भी हो-चाहे जप किया जाए, चाहे साई सच्चरित्र का पाठ किया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, वह सब हमें इसलिए करना चाहिए कि हमें बाबा ही चाहिए ना कि पूजा विधि. पूजा विधि एक मार्ग है, पर बाबा ही हमारे ध्येय हैं. कई व्यक्ति कोई भी प्रचलित सामाजिक पूजा-विधि के बिना भी ईश्वर को पा गए हैं. सबसे अच्छा होगा-सुबह बैठकर कुछ समय बाबा का ध्यान करना, सामान्य रूप से जो पूजा करते हैं, पूजा करना, पर उनको घर के एक सदस्य के रूप में हर बात में प्यार से रखना, जो भी खाते हैं वो मन से खिलाना, जो भी पहनते हैं उनको देना, सुख में उनका ध्यान करना और दुख में भी उनके विषय में सोचना-यह एक अविच्छिन्न पूजा होगी. एक घंटा या 15 मिनट पूजा करने से बहुत कुछ नहीं होता. बाबा को हर समय भाव में रखना ही हर समय की पूजा है-यह सहज पूजा होती है. बाबा को प्यार करना ही बाबा की पूजा है.

अगर कोई ज्यादा पूजा करना चाहे, तो घर में सुबह पूजा करनी अच्छी रहेगी. सुबह पूजा आरती के साथ करें, बाबा को प्रसाद, फूल पत्ते आदि पारंपरिक रीति से चढ़ाएं. रात को सोने से पहले बाबा की इसी प्रकार पूजा करके विभूति लगाकर और खाकर सो जाएं. यह पारंपरिक पूजा है.

क्या सद्गुरु की पूजा भगवान की तरह करनी चाहिए?

सद्गुरु की भगवान की तरह पूजा करने की आवश्यकता नहीं है. जब निराकार ईश्वर को जानते नहीं हो, उन्हें देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो भाव कहां आएगा? सद्गुरु सगुण ब्रह्म या ईश्वर हैं. भाव-हीन पूजा का कुछ मायने नहीं है. अपने भीतर जो भाव हैं, उसी में पूजा करें. पिता के लिए जो पिता-भाव है, माता के लिए जो माता-भाव है, जो भी भाव आप में प्रबल है, उसी भाव से सद्गुरु को पुकारिए. सद्गुरु में सभी भावों का समन्वय होता है.

अकिंचन भाव की श्रेष्ठता

सद्गुरु की उपासना किस भाव से करनी चाहिए?

अकिंचन भाव से. अकिंचन भाव से ही सद्गुरु आकर्षित होते हैं. तभी सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है. इसीलिए उन्हें दीन-बंधु कहा गया है. उनकी उपासना दास, बंधु, सखा भाव आदि से भी हो सकती है. किन्तु दास भाव श्रेष्ठतम होता है, क्योंकि इसमें अकिंचन भाव होता है. जिसमें जितना ही अकिंचन भाव होगा, वह उतना ही दीन एवं अहंकार रहित होगा और फिर गुरु की कृपा उसी रूप में उसे प्राप्त होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

धर्म

ऐतिहासिक है सूर्य का पश्चिमाभिमुख मंदिर

बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित देव का सूर्य मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केन्द्र है.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

इस मंदिर को दुनिया का इकलौता पश्चिमाभिमुख सूर्यमंदिर होने का गौरव हासिल है. इसे अभूतपूर्व स्थापत्य कला, शिल्प एवं कलात्मक भव्यता का अद्भुत नमूना कहा जाता है. कहा जाता है कि इस मंदिर को कोई साधारण शिल्पी ने नहीं बल्कि इसका निर्माण खुद देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया है. काले और भूरे पत्थरों की अति सुंदर कृति जिस तरह ओडिशा के पूरी के जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्यमंदिर का है, ठीक उसी से मिलता-जुलता शिल्प इस मंदिर का भी है. कहा जाता है कि यह मंदिर अति प्राचीन है, जिसे इलापुत्र राजा ऐल ने त्रेतायुग के 12 लाख 16 हजार वर्ष बीत जाने के बाद निर्माण आरंभ कराया था. इस मंदिर में 7 रथों से सूर्य की उत्कीर्ण प्रस्तर मूर्तियां अपने तीनों रूपों उदयाचल-प्रातः सूर्य, मध्याचल-मध्य सूर्य और अस्ताचल सूर्य-अस्त सूर्य के रूप में विद्यमान हैं. पूरी दुनिया में देव का ही मंदिर एकमात्र ऐसा सूर्यमंदिर है, जो पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है.

इस बारे में यह माना जाता है कि भगवान भास्कर का यह मंदिर सदियों से लोगों को मनोवांछित फल देने वाला पवित्र धर्मस्थल रहा है. यूं तो सालों भर देश के विभिन्न जगहों से यहां आकर लोग मनौतियां मांगते हैं और सूर्य देव द्वारा इसकी पूर्ति होने पर अर्घ्य देने आते हैं. लेकिन छठ पूजा के दौरान यहां दर्शन-पूजन की अपनी एक विशिष्ट धार्मिक महता है. इस सूर्य मंदिर में प्रत्येक वर्ष तीस लाख से अधिक लोग दर्शन-पूजन के लिए आते हैं. देव सुर्य कुंड तालाब में स्नान करने से कुष्ठ और सफेद दाग जैसे रोगों के दूर होने की बात चिकित्सा विज्ञानियों के गले भले ही नहीं उतरने वाली है, लेकिन देव स्थित सूर्य कुण्ड के प्रति इस तरह की आस्था अत्यंत ही बलवान है. इसके पीछे कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं. जिसमें सूर्य पुराण से सर्वाधिक प्रचारित जनश्रुति के अनुसार राजा ऐल के शरीर का श्वेत दाग प्राचीन समय में इसी तालाब में स्नान करने से दूर हुआ था और उसके बाद उन्होंने यहां सूर्यमंदिर का निर्माण करवाया था. सूर्य को साक्षात देव माना जाता है, जबकि विज्ञान भी सूर्य को उर्जा के स्त्रोत के रूप में स्वीकार करता है. वहां के पुंजारी का कहना है कि मनुष्य के शरीर के मालिक सूर्य हैं और भगवान सूर्य के पवित्र सूर्य कुंड में स्नान के बाद अर्घ्य देने से शरीर से सम्बंधित सारे रोग दूर होते हैं. यही कारण है की प्रत्येक वर्ष लाखों लोग यहां आते हैं और इस सूर्यकुंड तालाब में स्नान करते हैं. ■

प्रेरक कहानी

एकाग्रता से सफलता

बहुत पुरानी बात है, एक वन था, जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे. वहां एक बहुत बड़ा और उंचा पेड़ था. एक बार वन के सभी मेंढको की सभा हुई और उन्होनें एक प्रतियोगिता रखी. जिसमें जो मेंढक सबसे जल्दी पेड़ पे चढ़ कर चोटी पर पहुंचेगा उसे वन का राजा चुना जाएगा.

अगले दिन सारे वन के मेंढक एक जगह एकत्रित हुए और सभी बारी बारी पेड़ पर चड़ने की तैयारी करने लगे, पर पेड़ उतना बड़ा था कि सारे मेंढक उपर चढ़ने से घबरा रहे थे. बारी बारी सभी मेढक ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या देखते हैं कि सारे मेंढक थक कर चूर होने लगते हैं और कुछ तो थककर वापस नीचे आने लगते हैं. कुछ मेंढक नीचे आकर ऊपर वालों को आवाज़ लगाते हैं कि वापस आ जाओ, क्योंकि पेड़ की चोटी पर पहुंचना असंभव है.

सारे मेंढक नीचे आ जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा मेंढक लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था. सारे मेंढक उसे भी नीचे उतर आने को बोलने लगे, लेकिन वह लगता ऊपर चढ़ता गया और छोटी पर पहुंच गया. जब वह नीचे वापस आया तो सबने उससे सफलता का रहस्या पूछना चाहा. वह कुछ भी नहीं बोला भीड़ में से किसी ने बताया कि वह बहरा है.

तो मित्रों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है, जब हम कुछ अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें पीछे खींचते हैं . हममें से बहुत सारे धैर्य छोड़ देते हैं, लेकिन जो बिना रुके एकाग्रता से आगे बढ़ता है वो अंत में सफल हो जाते हैं. एकाग्रता, समर्पण और आत्मानुशासन के बिना या तो आप असफल हो जाएंगे, या अपने क्षमता से कहीं कम सफलता पा सकेंगे. ■

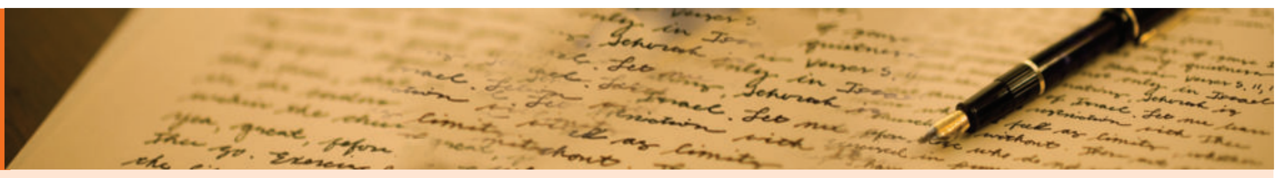

पाठकों की दुनिया

महंगाई की मार

भारत के चुनावों में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बनती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव. नरेन्द्र मोदी भी महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भाजपा सत्ता पर काबिज हुई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान महंगाई के मुद्दे को खुब जोर शोर से उठाया था. अब मोदी प्रधानमंत्री हैं और भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई अपने चरम सीमा पर है. अब न ही नरेन्द्र मोदी इस पर कुछ बोलते हैं और न ही भाजपा इस पर बोलने को तैयार है. सब्जी की तो बात छोड़ दीजिए, प्याज 80 रुपये किलो तक बिकी है और दाल 200 रुपये किलो तक बिकी है. भाजपा का लोकसभा चुनाव के दौरान एक नारा था बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार. लेकिन मोदी सरकार के सवा साल होने के बाद अब दिल से यही आवाज आती है कि बहुत हुई महंगाई की मार अब नहीं चाहिए ऐसी सरकार.

- सुप्रिया सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

विरोध का तरीका उचित नहीं है

सांप्रादयिकता और देश में बढ़ रहे दंगों से आहत होकर बहुत से जाने-माने साहित्यकार अपने पुरस्कार और उसके साथ मिलने वाली रकम को भी लौटा रहे हैं. साहित्याकारों का कहना है कि वह देश में बढ़ते धार्मिक सहिष्णुता पर प्रधानमंत्री के चुप्पी से आहत हैं. शायर और कवि मुन्नवर राणा ने एक निजी चैनल की बहस में ही अपना पुरस्कार और एक लाख रुपये का चेक लौटा दिया. लेकिन साहित्यकारों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. पहले भी इससे बड़ी-बड़ी घटनाएं हुईं हैं. तब साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार क्यों नहीं लौटाए? साहित्याकारों को अगर विरोध ही करना था, तो वो और तीखे लिखते या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते. क्या साहित्यकारों की कलम इतनी कमजोर हो गई है कि वो सरकार के खिलाफ लिखने की जगह अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं. साहित्यकारों के विरोध का जो तरीका है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता.

- रुपेश शुक्ला, *द्वारका, नई दिल्ली.*

जनता के साथ धोखा

कवर स्टोरी-बिहार विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों ने जनता के साथ धोखा किया(19 अक्टूबर-25 अक्टूबर, 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मनीष कुमार ने बिलकुल सही कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जनता के साथ धोखा किया. मैं मनीष कुमार से सहमत हूं कि राजनीतिक दलों ने अवसरवादिता, दिशाहीन संवाद, भद्दी टिप्पणियां, विचारहीनता, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, स्वार्थ, धनबल और अपराधीकरण आदि की सारी सीमाएं लांघ दी हैं. कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, जो बिहार की जनता के दुखों को दूर करने की, पलायन रोकने की, महंगाई दूर करने की, नौजवानों को रोजगार देने की बात करता हो. राजनीतिक दल केवल बिहार में गोमांस, जातिवाद, कौन शैतान है, कौन क्या है केवल इस पर बात कर रहे हैं. राजनीतिक दलों को चाहिए कि यह सब छोड़कर जनता की हितों की बात करें.

-पुष्पा कुमारी, *बक्सर, बिहार.*

नेताओं की भाषा

जब तोप मुकाबिल हो-बिहार चुनाव निराश कर रहा है(19 अक्टूबर-25 अक्टूबर, 2015) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि यह अवश्य लगता है कि बिहार विधानसभा का यह चुनाव भाषा की सारी मर्यादाओं को लगभग लांघ चुका है और जब तक यह चुनाव समाप्त होगा, तब तक राजनीति के कैंपेन की एक नई भाषा लिख चुका होगा. बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपनी विपक्षी पार्टियों और विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो शर्मनाक है. कोई किसी को शैतान कह रहा है, तो किसी को नरभक्षी कह रहा है. इस चुनाव में नेता प्रत्येक दिन एक नई गाली खोजकर लाते हैं और अपने विपक्ष के नेताओं के लिए उसका प्रयोग करते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, जो बिहार ही नहीं देश के लिए भी घातक है. राजनेताओं में शालीनता होनी चाहिए.

-मयूर सिन्हा, *दरभंगा, बिहार.*

संयम बरते नेता

आलेख-चुनाव नहीं, देश बड़ा होता है(19 अक्टूबर-25 अक्टूबर, 2015) पढ़ा. काफी अच्छा लगा. कमल मोरारका ने बिल्कुल सही कहा है कि चुनाव नहीं देश बड़ा होता है. बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने प्रचार का जो हथकंडा अपनाया है, वो घटिया है. राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव बीत जाएगा, लेकिन उनके द्वारा कहे गए शब्द मिटेंगे नहीं. नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान संयम बरतने की जरूरत है, उनको मालूम नहीं है कि उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का देश पर बुरा असर पड़ेगा. यह भी सही है कि देश में घटित घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के संदेश के पालन की बात कहकर मामला ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि देश के राजनीतिक माहौल को सांप्रदायिक बनाने और उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है. आशा है कि राजनीतिक दल अपनी हरकतों से बाज आएंगे.

-नवनीत कुश्वाहा, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

अकादमी में पारदर्शिता का अभाव

अनंत विजय

जितने लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए हैं उनमें से ज्यादातर वामपंथी हैं और ये पूरा मामला कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है. यह कहना है साहित्य अकादमी से सम्मानित बुजुर्ग लेखक गोविंद मिश्र का. इसके बाद हम गौर करें अरुण कमल के वक्तव्य पर जहां वो कहते हैं – साहित्य सभी तरह के पुरस्कारों, सम्मानों और सुविधाओं का प्रतिकार करता है. इसलिए पुरस्कार आदि वापस करना हमारा मुख्य मुद्दा है ही नहीं. मैंने अपने जीवन में अपने सिद्धांतों को त्याग कर कभी भी पुरस्कार, सम्मान और लाभ अर्जित नहीं किया. अशोक वाजपेयी जैसे लेखक जो लगातार सत्ता विरोधी लेखकों को कमतर करके आंकते रहे हैं उनकी दृष्टि अभी भी साफ नहीं हो पाई है. साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित एक और लेखक वरिष्ठ कवि लीलाधर जगूड़ी मानते हैं कि कुछ लेखकों के साहित्य अकादमी पुरस्कार को लौटाने को लेकर वो कोई दबाव महसूस नहीं करते हैं. उनका कहना है कि साहित्यकार को सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के मुद्दों पर आंदोलन करना चाहिए. वो जोर देकर कहते हैं कि इस बात को सामने आना चाहिए कि लेखक के सरोकार क्या हैं? लीलाधर जगूड़ी कहते हैं कि साहित्य अकादमी का काम कानून व्यवस्था को ठीक करना नहीं है. ये तीन वरिष्ठ लेखकों के वक्तव्य हैं जो कि कमोबेश अलग-अलग धारा के हैं. अब इन वक्तव्यों के आलोक में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के पीछे की राजनीति की पड़ताल करते हैं तो वहां सिसायत की एक अलग तरह की रेखा दिखाई देती है. सिसायत केंद्र सरकार के खिलाफ और सियासत साहित्य अकादमी की स्वायत्ता के खिलाफ. साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की शुरुआत उदय प्रकाश ने की. उस वक्त मुद्दा था कालबुर्गी की हत्या के बाद साहित्य अकादमी की संवेदनहीनता. तब यह भी प्रचारित किया गया था कि साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक कालबुर्गी की हत्या के बाद साहित्य अकादमी ने ना तो विरोध जताया और न ही उन्होंने कोई शोक सभा की. कालांतर में यह बात भी झूठ साबित हुई जब यह बात सामने आई कि साहित्य अकादमी ने बैंगलोर में कालबुर्गी की हत्या के बाद एक शोक सभा की थी जिसमें अकादमी के उपाध्यक्ष कंबार समेत कई स्थानीय लेखक मौजूद थे. अब इस बात पर विचार होना चाहिए कि पुरस्कार वापसी अभियान की शुरुआत की जो बुनियाद थी उसमें झूठ की भी एक ईंट थी. उदय प्रकाश के बाद दो धवलकेशी साहित्यकारों– अशोक वाजपेयी और नयनतारा सहगल ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का एलान किया. अबतक साहित्यकारों पर हो रहे हमलों का प्रतिरोध हो रहा था लेकिन इन दो लेखकों ने इसमें बहुलतावादी संस्कृति पर खतरे को भी अपने प्रतिरोध से जोड़ दिया. इन्होंने दादरी हत्याकांड और गोमांस विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए. अशोक वाजपेयी और नयनतारा सहगल के बाद तो करीब दो दर्जन साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का एलान कर दिया. साहित्य अकादमी पर भी दबाव बना और उसके अध्यक्ष ने तेइस अक्टूबर

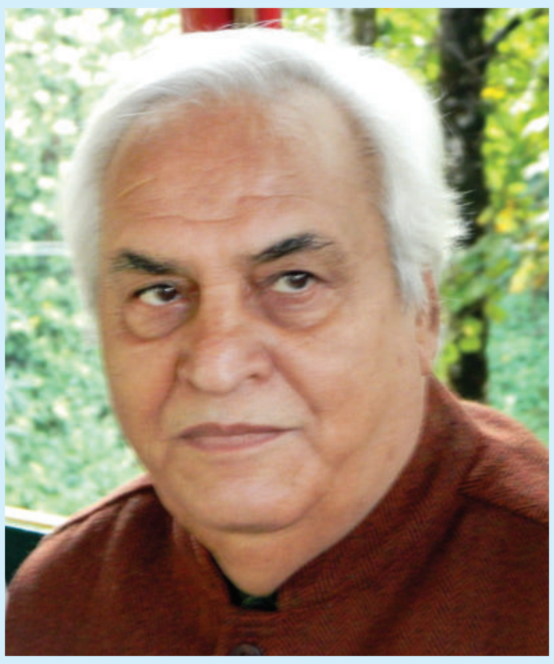

को कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का एलान कर दिया. लेकिन अशोक वाजपेयी और नयनतारा सहगल के केंद्र सरकार को इसमें घसीटने के बाद धीरे-धीरे विरोध करनेवालों की मंशा साफ होने लगी. आज तक वामपंथियों के निशाने पर रहे अशोक वाजपेयी अचानक से उनको अच्छे लगने लगे. लेकिन खेल इतना सीधा नहीं था. इस खेल के पीछे की मुख्य मंशा केंद्र सरकार पर हमले की आड़ में साहित्य अकादमी में अराजकता पैदा करना है. साहित्य अकादमी की इस अराजकता की आड़ में उसके अध्यक्ष को अस्थिर करना भी इसमें शामिल है. अब इस बात का खतरा पैदा हो गया है कि इस स्वायत्त संस्था पर इस अराजकता की आड़ में संस्कृति मंत्रालय दखल दे और इसका हाल भी ललित कला अकादमी जैसा हो. हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा कर प्रतिरोध जता रहे लेखकों से इस बात को लेकर ही विरोध है कि वो परोक्ष रूप से सरकार की मदद कर रहे हैं. वो एक ऐसी जमीन तैयार करके सरकार को दे रहे हैं जो भविष्य में साहित्य अकादमी की स्वायत्ता के लिए खतरा हो सकती है. यह बात इस वजह से कह रहा हूं कि इन लेखकों ने पूर्व में साहित्य अकादमी की गड़बड़ियों पर कभी भी रोष नहीं जताया. पुरस्कारों के लिए लेखकों के चयन में होनेवाली धांधली पर इन्होंने कभी भी एतराज नहीं जताया क्योंकि साहित्य अकादमी में मिल बांट कर खाने की परंपरा चली आ रही है. क्या इन लेखकों के कभी साहित्य अकादमी के संविधान में लंबे समय से चली आ रही खामियों पर कोई सवाल उठाया? क्या पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों ने कभी भी साहित्य अकादमी की सामान्य सभा के सदस्यों के चुनाव में होनेवाली धांधली पर सवाल खड़े किए? क्या कभी इन लेखकों ने साहित्य अकादमी की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने की मांग करते हुए कोई आवाज उठाई? क्या इन लेखकों ने साहित्य अकादमी के लेखकों में हित में काम करने के लिए दबाव बनाने

साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के पीछे की राजनीति की पड़ताल करते हैं तो वहां सिसायत की एक अलग तरह की रेखा दिखाई देती है. सिसायत केंद्र सरकार के खिलाफ और सियासत साहित्य अकादमी की स्वायत्ता के खिलाफ. साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की शुरुआत उदय प्रकाश ने की. उस वक्त मुद्दा था कालबुर्गी की हत्या के बाद साहित्य अकादमी की संवेदनहीनता. तब यह भी प्रचारित किया गया था कि साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखक कालबुर्गी की हत्या के बाद साहित्य अकादमी ने ना तो विरोध जताया और न ही उन्होंने कोई शोक सभा की.

के लिए कुछ किया? हर सवाल का जवाब मिलेगा नहीं. लिहाजा अब जब वो साहित्य अकादमी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो अपेक्षित माहौल नहीं बन पा रहा है.

साहित्य अकादमी के गठन के बाद से ही उसके संविधान में कई गड़बड़ियां हैं. भारत के संविधान में काल और परिस्थिति के हिसाब से करीब सौ संशोधन हो चुके हैं लेकिन अकादमी के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, ये ज्ञात नहीं है. 1954 में जब साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी तो कौशल विकास और शोध प्रमुख उद्देश्य थे. तकरीबन छह दशक के बाद भी साहित्य अकादमी देश की सभी भाषाओं में शोध और कौशल विकास को अपेक्षित स्तर पर नहीं ले जा पाई.

सत्रह दिसंबर दो हजार तेरह को संसद के दोनों सदनों में सीताराम येचुरी की अध्यक्षता वाली एक संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के अलावा इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कामकाज पर टिप्पणियां की गई थी. येचुरी की अगुवाई वाली इस समिति ने माना था कि साहित्य अकादमी के पुरस्कारों में पारदर्शिता का अभाव है. अकादमियों की इन बदइंतजामियों के बारे में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 56 में लिखा–समिति यह दृढ़ता से महसूस करती है कि ऐसी स्थिति को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इन अकादमियों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ करने का यह सही समय है. सांस्कृतिक संस्थानों के कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए. ये समीक्षाएं बाहरी व्यक्तियों और समितियों द्वारा की जानी चाहिए और उन्हें उन वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल किया जाना चाहिए. संसदीय समिति की इस रिपोर्ट के बाद जनवरी 2014 में यूपीए सरकार के दौरान अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक हाई पॉवर कमेटी का गठन किया गया. अकादमियों के कामकाज की समीक्षा के बारे में 1988 में हक्सर कमेटी बनी थी और तकरीबन पच्चीस साल बाद अब सेन कमेटी का गठन हुआ था. इस कमेटी में नामवर सिंह, रतन थियम, सुषमा यादव, ओपी जैन आदि सदस्य थे. इस कमेटी का गठन इन अकादमियों के संविधान और उसके कामकाज में बदलाव को लेकर सुझाव देना था. इस कमेटी ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की. लगभग सवा सौ पृष्ठों की रिपोर्ट में इस कमेटी ने भी माना कि इन अकादमियों में जमकर गड़बड़झाले को अंजाम दिया जा रहा है. इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की उम्र सीमा भी 70 साल हो. उपाध्यक्ष के पद को बेकार मानते हुए उसे खत्म करने और सचिव का कार्यकाल तीन साल करने की सिफारिश की गई है.

इसके अलावा अगर हम साहित्य अकादमी के संविधान पर गौर करें तो सामान्य सभा के चुनाव में जिस तरह से सदस्यों का चुनाव होता है वह माफियागीरी को बढ़ावा देता है. हर भाषा के नुमाइंदे बंटवारा कर लेते हैं और चुनाव हो जाता है. इसी तरह से अगर किसी भाषा का प्रतिनिधि अपने कार्यकाल के बीच में सदस्यता छोड़ता है या उसका निधन हो जाता है तो उसकी जगह खाली रहेगी. ये विसंगति दूर होनी चाहिए और सामान्य सभा के सदस्यों का चुनाव मतपत्र के आधार पर होना चाहिए. इस तरह की पारदर्शिता के बगैर अकादमी ना केवल अपनी साख खोती जा रही है बल्कि स्वायत्तता खत्म करने के लिए सरकार के हाथ में हथियार भी दे रही है. आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान अध्यक्ष और सचिव साहित्य अकादमी को उसके मूल उद्देश्यों की ओर ले जाएं और वहां प्रतिभा का सम्मान हो. सेटिंग-गेटिंग का खेल साहित्य अकादमी में बंद होना चाहिए. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार

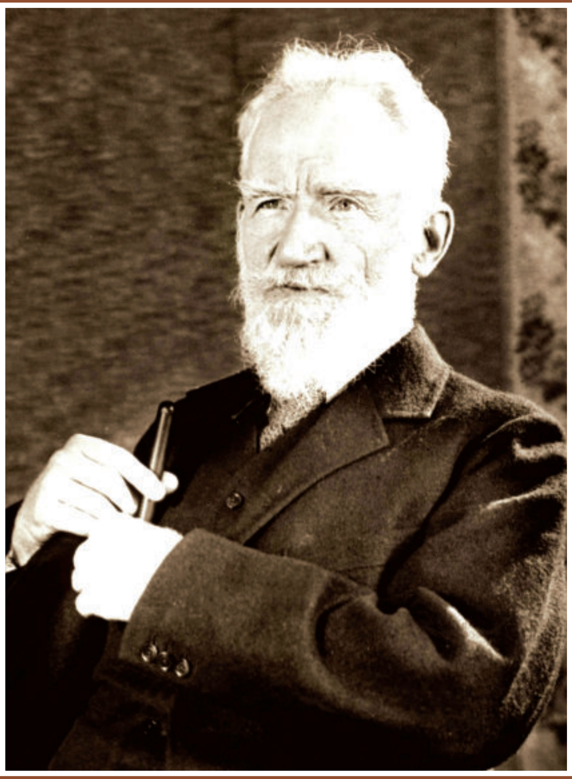

जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी सवार्धिक सफल साहित्यकारों में से एक हैं. उन्होंने अंग्रेजी नाटककार में विलियम शेक्सपियर के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है. शॉ दुनिया एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल और ऑस्कर दोनों ही पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. उन्होंने पिगमिलियन, सैंट जॉन, कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन जैसी श्रेष्ठ कृतियां रचकर खुद को साहित्य की दुनिया में अमर कर लिया. शॉ की साहित्यिक भाषा का एक समय ब्रिटेन में इतना जोर हो गया था कि लोग उनकी रचनाओं की पंक्तियों का प्रयोग आम बोल-चाल की भाषा में करने लगे थे. इसे शॉवियन लैंग्वेज कहते थे. ■

असहिष्णुता का विरोध या कोरी राजनीति

डॉ. चंद्र प्रकाश शर्मा

पहले कर्नाटक में कन्नड़ साहित्यकार प्रोफेसर एमएम कलबर्गी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के दादरी में इखलाक अहमद की हत्या को साहित्यकारों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता माना. इसके विरोध में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने को अपना हथियार बनाया. सबसे पहले साहित्यकार उदय प्रकाश ने प्रो. कलबर्गी की हत्या के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की. इसके बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की भांजी व साहित्यकार नयनतारा सहगल ने यह कहते हुए सम्मान लौटाने की घोषणा की कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि लेखकों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए. इसके बाद तो जैसे पुरस्कार लौटाने वालों की झड़ी लग गई.

विरोध के बीच तमाम संवेदनशील, प्रगतिशील, जनवादी लेखक शायद अब तक हुए दंगों और दादरी की घटना में फर्क करना भूल गए, जहां अब तक हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद महीनों माहौल में खौफ की बू आती रहती है, वहीं दादरी में घटना के तुरंत बाद ही गांव के हर तबके को इस बात का अहसास हो गया था कि कुछ अनर्थ हो गया है. हर तरफ से मदद के लिए हाथ बढ़ने शुरू हो गए. घटना के तुरंत बाद ही न कोई हिंदू बचा और न कोई मुसलमान. रह गए तो सिर्फ उस गांव के आम दुखी बाशिंदे. तकरीबन 300 मुसलमानों की आबादी वाले गांव के हिंदुओं ने अपने सुख-दुख के साथियों को भरोसा दिलाना शुरू किया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. जो हुआ वो भावावेश में हुआ. उन्हें गांव छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद एक मुस्लिम परिवार की दो बेटियों की शादी में हिंदुओं ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई और देखते ही देखते माहौल शांत हो गया.

इस घटना के बाद अलग-अलग पार्टियों के कुछ नेताओं ने इस आग को सुलगाए रखने की नाकाम कोशिश की. रही बची कसर लेखकों ने पूरी कर दी. जब दादरी के गली-कूचे, तालाब-पोखर, हिंदू-मुस्लिम और यहां तक कि जानवर भी उस घटना को भुलाकर सामान्य जीवन जीने लगे थे, तो लेखकों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चला कर और अपने पुरस्कार वापस कर इस

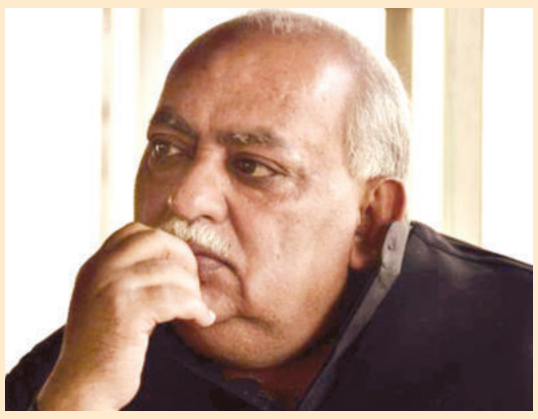

मसले को तूल ही नहीं दिया, देश में नई बहस भी छेड़ दी. हालांकि, सच्चाई यह भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को, कभी भी, किसी भी मसले पर, किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार है. लेखकों ने समाज में बढ़ रही असहिष्णुता का विरोध अपने अंदाज में किया. हालांकि, उनके विरोध को जहां देश भर से समर्थन हासिल हुआ, वहीं उनका विरोध भी हुआ. लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या देश में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई हैं? क्या अब से पहले ऐसा माहौल नहीं बना था, जब लेखकों की संवेदनशीलता के धरातल ने भूकंप के झटके महसूस किए हों?

शायर मुनव्वर राणा का एक न्यूज चैनल कार्यक्रम में सम्मान और एक लाख रुपये का चेक लेकर पहुंचना और फिर लाइव कार्यक्रम में सम्मान वापसी की घोषणा ने कई सवाल खड़े कर दिए. दरअसल, दो दिन पहले तक मुनव्वर राणा जी सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि उनकी कलम अभी थकी नहीं है. वह अपनी कलम के जरिये घटनाओं का विरोध करने की बात करते हुए कहीं ज्यादा तार्किक नजर आ रहे थे. वह खुद सम्मान लौटाने को सही मान रहे थे. फिर अचानक क्या हुआ कि लाइव कार्यक्रम में उन्होंने सम्मान लौटा दिया. इसके अगले ही दिन वह प्रधानमंत्री के कहने पर सम्मान वापस लेने की बात करने लगे. इस पूरे घटनाक्रम से राजनीति की गंध आ रही है.

साहित्यकार महाराष्ट्र में कांग्रेस शासन के दौरान हुई नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, कांग्रेस शासित कर्नाटक में प्रो. कलबर्गी की हत्या और समाजवादी पार्टी शासित उत्तर प्रदेश के दादरी में हुई इखलाक की हत्या का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं. जबकि इन सभी घटनाओं में सबसे पहली जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की बनती है, जिनके विरोध में अब तक किसी साहित्यकार ने एक शब्द भी कहना मुनासिब नहीं समझा है. तो कैसे उन लोगों को गलत साबित किया जा सकता है जो कह रहे हैं कि लेखक, कवि, शायर, साहित्यकार सुनियोजित तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं. मौजूदा हालात में तो साहित्यकारों की मंशा, नियत और उनके लक्ष्य को लेकर सवाल उठना लाजमी है.

अब तक सम्मान लौटाने वाले और साहित्य अकादमी से इस्तीफा देने वाले साहित्यकारों की तादाद तकरीबन तीन दर्जन हो गई है. इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि पिछले कुछ समय में चित्त को अस्थिर कर देने वाली घटनाएं भी हुई हैं और उनका विरोध भी होना चाहिए. लेकिन हमें यह भी विचार करना होगा कि हर घटना के लिए एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है. साथ ही कुछ घटनाओं में मौन साध लेना और कुछ घटनाओं पर मुखर होकर घटना विशेष का चुनाव करना कहां तक ठीक है. सोशल मीडिया और खबर के विभिन्न माध्यमों के दौर में इस तरह का चयन और विरोध साहित्यकारों के लिए आत्मघाती कदम ही साबित होता है और हुआ भी.

पिछले कुछ दिनों में सम्मान लौटाने वाले साहित्यकारों की ऐसी-ऐसी रचनाएं सबसे ज्यादा पढ़ी गई हैं, जो शायद लिखने के बाद उन्होंने खुद भी ज्यादा नहीं पढ़ी होंगी. पहले सम्मान वापसी को लेकर लेखकों की नियत पर सवाल उठे और अब उनकी रचनाओं के स्तर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. आरोप लगे कि साहित्यकार पिक एंड चूज और चूज एंड हिट की नीति अपना रहे हैं. इस सब के बीच विरोध का सभी को हक है. बेशक साहित्यकारों के विरोध पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं और उनका विरोध करने वालों के विरोध पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी को भी किसी का विरोध करने से रोका जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा. हालांकि, साहित्यकारों से उम्मीद थी कि वे विरोध के लिए कहीं ज्यादा सुविचारित, तार्किक तरीका अपनाते. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

दूध को गरम करें, उसमें धीरे धीरे सिट्रिक एसिड डाल कर तब तक चलाएं, जब तक वह फट न जाए. अब पनीर को साफ कपड़े से छान लें और ठंडा होने दें. एक बर्तन में पनीर और चीनी को एक साथ मिला कर 4–5 मिनट तक के लिए रख लें, पर ध्यान रहे कि पनीर का रंग न बदले. फिर इस मिश्रण को एक मिक्सर में ग्राइंड करें, वो भी बिना पानी मिलाए. अब इसमें पिस्ता पाउडर मिलाएं और इसको छोटे–छोटे भागों में बांट लें.

सैर-सपाटा

संदकफू में देखें प्रकृति के अलौकिक नज़ारे

प्रकृति जब अपनी अदाएं बिखेरती है तब वो किसी भी बंदिश को नहीं मानती. यही बात उन प्रकृति प्रेमियों पर भी लागू होती है, जो नज़ारे लेने के लिए इस खूबसूरत धरती की सैर पर निकलते हैं. यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो आप को हिमालय बुला रहा है. जो ऐसे ही कुदरती हुस्न से पटा पड़ा हुआ है. आज हम आपको बताते हैं, संदकफू के बारे में जो पश्चिम बंगाल से सिक्किम तक पसरी सिंगालिला श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. संदकफू समुद्र तल से 3611 मीटर पर है. यहां से पर्यटक धरती के पांच उच्चतम पर्वत शिखर में से चार को एक साथ एक समय में देख सकते हैं. माउण्ट एवरेस्ट, कंचनजंघा, लाहोत्से और मकालू. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है सूरज की पहली लाल किरण, वो इसलिए की जब पहली किरण इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तब अलौकिक नज़ारा होता है. इसी को देखने के लिए सुबह चार बजे से सैलानी हाड़ जमाती ठण्ड में भी जमे रहते हैं. सिर्फ यही नहीं मनयभंजन से संदकफू आने तक प्रकृति आप के लिए अपनी बाहें खोले खड़ी नज़र आती है. ये पूरा का पूरा मार्ग भारत–नेपाल सीमा के साथ चलता है. पूरे रास्ते आप नेपाल व भारत दोनों देशो की सीमाओं को लांघते हैं, पूरा रास्ता आपको किसी परी कथा सरीखा लगेगा. दूर–दूर तक फैली हरियाली सीना ताने खड़े पर्वत शिखर मखमली सड़क एलिस इन वंडरलैंड सरीखी ही है, यहां के लोग मृदुभाषी व सीधे–साधे हैं, जो अपनी संस्कृति धर्म से जुड़े हैं. पूरे इलाके में फैले गोम्पा व बौद्ध मठ इसके गवाह हैं. मनयभंजन से आगे चलने पर चित्रे, तुंबलिंग, कालापोखरी, संदकफू, तक आपको शेरपाओं के लॉज आसानी से मिल जाएंगे जहां कम मूल्य पर ठहरने की जगह और घर जैसा खाना मिलेगा. आप जब भी यहां आएं एक बार तुम्बा देसी बीयर ज़रूर पीएं. सुखाया गया पनीर जो याक के दूध से बनाया जाता है उसे चखे बिना तो आप रह ही नहीं सकते. इसके साथ थुप्पा और नेपाली मोमो ऐसा, जो आपकी भूख और बढ़ा देगा.

कैसे पहुंचें

आपका वास्तविक सफर आरंभ होगा मनयभंजन से. मनयभंजन तक पहुंचने के लिए दो सड़क मार्ग हैं. पहला सीधा जलपाईगुड़ी से, इस रास्ते पर न्यू जलपाईगुड़ी से मनयभंजन की दूरी 90 किमी है. दूसरा है, न्यू जलपाईगुड़ी से घूम शहर जो दार्जीलिंग से 9 किमी पहले है. घूम से मनयभंजन का सफर सिर्फ एक घण्टे का है. साधन के तौर पर जीप है.

कब जाएं

संदकफू इलाका सिंगालिला राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है. 15 जून से 15 सितम्बर तक यह पार्क पर्यटकों के लिए बन्द रहता है. मई और जून में मौसम में गुलाबी ठंडक रहती है. इसके बाद ठण्डक अपना असर दिखाती है. यहां जमकर बर्फ गिरती है, जिसका मजा लिया जा सकता है. मनयभंजन से आपको गाइड मिल जाएंगे, जो एक दिन का 250 से 300 रूपये लेते हैं. ■

फैशन

नई दिल्ली में ऑनलाइन फैशन एप्प मिन्त्रा के लॉन्च के मौके पर अन्य मॉडल्स के साथ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण

करियर

डबिंग और वॉयस ओवर आर्ट में बनाएं करियर

आज कल बहुत सारी विदेशी फिल्में रिलीज़ होती हैं और भारतीय बाजार हॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा है, भारत में अंग्रेजी समझने वालों की संख्या काफी कम है. इसलिए हिंदी डबिंग कलाकार की जरूरत होती है. अंग्रेजी फिल्म ही नहीं, कार्टून, विज्ञापन, गाने और रेडियो के लिए भी डबिंग कलाकार की जरूरत होती है. हिंदी डबिंग और वॉयस–ओवर आर्टिस्ट में क्या है करियर विकल्प?

कार्टून – बच्चों के लिए सबसे मजेदार चीज है कार्टून. आज कल बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं, जो कार्टून बनाती हैं. अब इन कार्टून कलाकारों में जान फूंकती है डबिंग कलाकारों की आवाज.

विज्ञापन – एक कंपनी जब विज्ञापन बनाती है, तो वो उसे केवल एक ही भाषा में बनाती है, लेकिन डबिंग कलाकार उसे अलग–अलग भाषाओं में प्रस्तुत करते हैं.

गाने – जब अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा की फिल्म का अनुवाद करते हैं, तो उस फिल्म के गानों की भी डबिंग करनी पड़ती है. इस कारण फिल्मों में डबिंग कलाकार की ज्यादा जरूरत होती है.

रेडियो– एफएम रेडियो में डबिंग कलाकार का विशिष्ट महत्व है. एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के आवाज निकालता है. अलग–अलग आवाज अलग–अलग परिस्थिति के लिए उपयोग की जाती है और इसी आवाज के कारण श्रोताओं को रेडियो सुनने का मजा आता है. ■

खाना पीना

बंगाल की पारंपरिक मिठाई संदेश

पिस्ता संदेश एक बंगाली मिठाई है, जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा. आप इस मिठाई को कहीं भी और किसी भी त्योहार पर बिना किसी मेहनत के बना सकते हैं. वैसे तो मिठाई हर प्रकार की ही अच्छी लगती है, पर बंगाल की मिठाईयों की तो बात ही कुछ अलग होती है. जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है.

सामग्री - पिसी चीनी, 12 चम्मच पिस्ता पाउडर, 1 लीटर गाय का दूध, 10 पिस्ता, 1/4 सिट्रिक एसिड.

बनाने की विधि- उसको पनी बनाने के लिए दूध को गरम करें, उसमें धीरे धीरे सिट्रिक एसिड डाल कर तब तक चलाएं जब तक वह फट न जाए. फटने के बाद उसे साफ कपड़े से छान लें और ठंडा होने दें. एक बर्तन में पनीर और चीनी को एक साथ मिला कर 4-5 मिनट तक के लिए रख लें, पर ध्यान रहे की उसका रंग न बदले. फिर इस मिश्रण को एक मिक्सर में ग्राइंड करें वो भी बिना पानी मिलाएं. अब इसमें पिस्ता पाउडर मिलाएं और इसको छोटे-छोटे भागों में बांट लें. अब इसको ऊपर से पिस्ते से अपने मन पसंद आकार में सजाएं. पिस्ता संदेश मिठाई तैयार है. ■

क्या है एंड्रॉयड फोन में पैरेंटल कंट्रोल सर्विस

श्याम सुन्दर प्रसाद

आज अगर फोन की बात करें, तो सबसे पहले दिमाग़ में स्मार्टफोन का ख्याल आता है. उसमें भी एंड्रॉयड फोन का नाम सबसे पहले आता है, आज चाहे वो किसी कॉलेज के छात्र हों, कोई बिजनेस मैन हों या फिर कोई सर्विस मैन सभी का पहला विकल्प होता है एंड्रॉडय फोन, क्योंकि एंड्रॉयड ने शुरू से ही प्ले स्टोर के माध्यम से अपने यूजर को फ्री में डाउनलोड होने वाले ढेर सारे गेम्स, कई प्रकार के लाखों एप्लीकेशन डाउनलोड करने की छूट दे रखी है. लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्ले स्टोर पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए बनाया जाता है और यहां दुनिया भर में हर प्रकार के एप्लीकेशन तैयार कर अपलोड किया जाता है, इसमें से कुछ एप्लीकेशन एजुकेशनल होते हैं, तो कुछ आपत्तिजनक भी होते हैं, इनमें एडल्ट कंटेट भी शामिल हो सकते हैं, जो आपके बच्चों के लिए उचित नहीं है. प्ले स्टोर में सर्च करते वक्त कब यह आपके सामने आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अगर आप अपने बच्चों को एंड्रॉयड फोन दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पैरेंटल कंट्रोल्स को यूज करना ना भूलें, इसके माध्यम से आप एडल्ट कंटेट को सर्च करने से रोक सकते हैं.

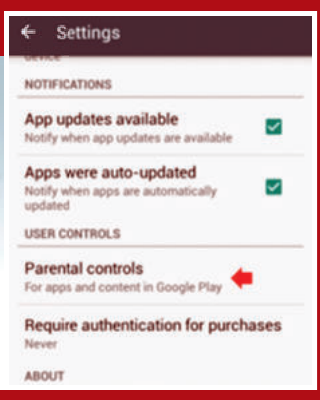

प्ले स्टोर पर पैरेंटल कंट्रोल कैसे यूज करें

इसके लिए सबसे पहले आप एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर केआयकॉन पर क्लिक करें. उसके बाद बाईं ओर स्थित मेन्यू को टच करें. यहां आपको सेटिंग्स की बटन दिखेगी. उसे टच करें. सेंटिग्स में यूजर कंट्रोल नामक हेडिंग को सर्च करें उसमें आपको पैरेंटल कंट्रोल ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करें, यहां आपको ऑन–ऑफ बटन दिखाई देगा, जब आप इसे पहली बार ऑन करेगें तो यहां पर सिस्टम आपको पिन कोड इंटर करने को कहेगा, तो आप यहां कोई भी पिन सेट कर सकते हैं, ऐसा पिन सेट करें, जो आपकेबच्चे या इससे सम्बंधित व्यक्ति को पता न हो, पिन डालने केबाद यह उसे सत्यापित(वैरीफाई) कराएगा और फिर से आपको वही पिन इंटर करना है, जो आपने तुरंत इंटर किया था. उसके बाद पैरेंटल कंट्रोल्स ऑन हो जाएगा. पैरेंटल कंट्रोल्स ऑन होते ही आपको सामने दो ऑप्शन दिखेंगे. पहला एप्स और गेम्स और दूसरा मूवी पहले एप्स और गेम्स पर टैप कीजिए, यहां आपको अलग–अगल रेटिंग कैटेगरी दिखाई देगें जैसे 3+, 7+, 12+ आप जैसे एज कैटेगरी अपने बच्चे के लिए फिक्स करना चाहते हैं, तो उस पर टैप कर दीजिए. ऐसा करने से केवल उसी ऐज कैटेगरी का एप्लीकेशन संबंधित मोबाइल के सर्च में दिखाई देगा. इसी प्रकार आप मूवी की कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सतर्क रह सकते हैं. ■

Smart7973@gmail.com

सहवाग जैसे क्रिकेटर बनते नहीं पैदा होते हैं

सहवाग ने अपने करियर में टीम इंडिया केलिए 104 टेस्ट मैच खेले और 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए. इसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 319 रन है. सहवाग तिहरा शतक बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उनसे किसी को यह कारनामा करने की अपेक्षा नहीं थी लेकिन उन्होंने यह कारनामा दो बार किया. आज भी टीम इंडिया केसबसे बड़े तीन स्कोर सहवाग केही नाम दर्ज है.

तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़. यह कारनामा दो बार किया.

साल 2008 में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ सबसे तेज तिहरा शतक लगाया. (278 गेंदों में 300 रन)

टेस्ट में सबसे तेज 250 रन और वन-डे में दूसरा सर्वाधिक स्कोर (219).

सहवाग दुनिया के उन सिर्फ चार बल्लेबाज़ों में शामिल हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक जड़े. वह दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने दो तिहरे शतक जड़ने के अलावा टेस्ट मैच की एक पारी में पांच विकेट भी झटके हैं.

नवीन चौहान

अटकलों और अफवाहों के दौर के बाद नज़फगढ़ के नवाब और मुल्तान के सुल्तान के नाम से मशहूर भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. अपने 37 वें जन्मदिन के मौक़े पर संन्यास की घोषणा करते हुए सहवाग ने कहा कि भारत के लिए खेलना एक यादगार सफ़र रहा है और मैंने इसे साथी खिलाड़ियों के साथ-साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए और यादगार बनाने की कोशिश की. मुझे लगता है कि ऐसा करने में मैं कुछ हद तक कामयाब रहा. अपने बयान के आखिर में सहवाग ने कहा, मैं उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बीते सालों में क्रिकेट के बारे में मुझे सलाह दी. मैं ज्यादातर सलाहों को न मानने के लिए माफ़ी चाहता हूं. मेरे पास सलाह ना मानने का एक कारण था, मैं अपने तरीक़े से खेल रहा था. निःसंदेह सहवाग ने ऐसा ही किया.

भारतीय क्रिकेट में जब कभी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट ओपनर की बात होगी तो सुनील गावस्कर के बाद वीरेंद्र सहवाग का नाम हमेशा लिया जाएगा. सहवाग ने क्रिकेट के मूलभूत तरीके खासकर ओपनिंग बल्लेबाज़ी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया. उन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में दर्शकों को टी-20 क्रिकेट का मजा दिलाया. सहवाग जैसे खिलाड़ियों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह और उनके जैसे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को नीरसता के दलदल से बाहर खींच लाए और टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व के सवाल को बेनामी साबित कर दिया. यदि आज दुनिया में टेस्ट क्रिकेट का स्वरूप बदला और भारतीय टीम ने पहले के मुक़ाबले ज्यादा सफलता हासिल की उसके श्रेय सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र सहवाग को जाता है. सहवाग के टेस्ट पदार्पण से पहले टीम इंडिया ने 463 टेस्ट मैच खेले थे जिनमें से लगभग 19 प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की थी. लेकिन सहवाग के टीम में रहते जीत प्रतिशत बढ़कर 40 हो गया था. उनके टीम से बाहर होने के बाद यह घटकर लगभग 26 प्रतिशत हो गया. ये आंकड़े बताते हैं कि सहवाग होने के क्या मायने हैं, सहवाग ने टीम इंडिया को किस तरह प्रभावित किया. कहावत भी है वेल बिगिन इज हाफ डन, जब-जब टीम इंडिया को सहवाग ने अच्छी शुरूआत दी, भारतीय टीम ने उन मैचों में अच्छा किया.

भारतीय क्रिकेट जगत में वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पहचान एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में तब बनाई थी जब सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे बल्लेबाजों के सितारे बुलंदी पर थे. सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी के अनोखे अंदाज से प्रशंसकों के बीच अमिट छाप छोड़ी. भले ही सहवाग ने पिछले दो सालों में टीम इंडिया के

लिए कोई मैच नहीं खेला. लेकिन प्रशंसक उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल सके. उन्हें आशा थी कि सहवाग वापसी करने में कामयाब होंगे. एक गेंदबाज तब परेशान होता है. जब कोई बल्लेबाज़ उसकी बेहतरीन गेंद को बाउंड्री का पार पहुंचा दे. यह हुनर वीरेंद्र सहवाग के पास था. सहवाग ने दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए. उन्हें केवल एक तरह की क्रिकेट खेलनी आती थी और वह थी आक्रामक क्रिकेट. जब तक सहवाग पिच पर होते थे तब तक विरोधी कप्तान, गेंदबाज और फील्डर चैन की सांस नहीं ले पाते थे. सहवाग उस तूफान की तरह थे जो विरोधी खेमे को उड़ा ले जाते थे. मैदान पर कैसी भी परिस्थिति हो या कैसी भी पिच. वहां केवल एक चीज स्थिर होती थी और वह था सहवाग के खेल का बेखौफ अंदाज. खेल के इसी अंदाज ने उन्हें एक समय भारतीय क्रिकेट का सिरमौर बना दिया था. यदि सहवाग का बल्ला चल गया तो टीम की जीत निश्चित होती थी. जब तक सहवाग मैदान पर होते थे, तब तक सब कुछ संभव नज़र आता था. लापरवाही भरे शॉट्स खेलना शुरू से ही सहवाग की आदत में शुमार था. वह एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते रहे हैं, जो चल गया तो विरोधी टीम का हारना तय और नहीं चला तो टीम इंडिया पर बोझ. बावजूद इसके टीम ने कप्तान ने उन पर हर बार दांव खेला. वीरेंद्र सहवाग की दिलेरी ही उन्हें सबका कायल बनाती थी. सहवाग पिच पर कभी दबाव में नहीं होते थे. चाहे वह नर्वस नाइंटीज में हों या तिहरे शतक के करीब. वह कभी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेले, उनका मस्तमौला अंदाज ही उन्हें अपनी पीढ़ी के दूसरे खिलाड़ियों से अलग खड़ा करता है.

सहवाग ने अपने करियर में टीम इंडिया के लिए 104 टेस्ट मैच खेले और 49.34 की औसत से 8586 रन बनाए. इसमें 23 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 319 रन है. सहवाग तिहरा शतक बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उनसे किसी को यह कारनामा करने की अपेक्षा नहीं थी लेकिन उन्होंने यह कारनामा दो बार किया. आज भी टीम इंडिया के तीन सबसे बड़े स्कोर सहवाग के नाम दर्ज है. 251 एक दिवसीय मैचों में सहवाग ने 35.05 की औसत से 8273 रन बनाए. वन-डे में उनके नाम 15 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज हैं. सहवाग ने अपने अंतराष्ट्रीय करियर की शुरूआत वर्ष 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली वन-डे से की थी. शुरूआत में उन्हें वन-डे विशेषज्ञ माना जाता था लेकिन साल 2001 के दक्षिण अफ्रीकी दौर पर जाने वाली टीम में तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली ने उन्हें जगह दिलवाई. करियर के पहले टेस्ट में नंबर छह पर बल्लेबाज़ी करने उतरे सहवाग ने शतक जमाकर कप्तान के निर्णय को सही साबित किया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. कुछ समय बाद सहवाग टीम इंडिया के लिए वन-डे और टेस्ट दोनों में पारी की शुरूआत करने लगे. सहवाग एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक अच्छे ऑफ स्पिनर भी थे. उन्होंने अपनी गेंदबाजी की बदौलत कई बार टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला. उन्होंने टेस्ट मैचों में 40 और वन-डे में 96 विकेट लिए. साल 2003 से 2012 के बीच उन्होंने 12 एकदिवसीय, चार टेस्ट और एक टी-20 मैच में टीम इंडिया की कमान भी संभाली.

हालांकि सहवाग ने मैदान पर किसी गेंदबाज को उधेड़े बिना नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने संन्यास के बाद कहा कि मुथैया मुरलीधरन से उन्हें बहुत डर लगता था.सहवाग की तकनीक की क्रिकेट के जानकारों ने आलोचना की, लेकिन सहवाग ने हर बार अपने ऊपर ऊठे सवालों का जवाब अपने बल्ले से दिया. उन्होंने अपने खेल का अंदाज कभी नहीं बदला. उछालभरी पिचों पर स्विंग होती गेंदों पर उनकी कमजोरियां उजागर हो जाती थीं. उन्हें डिफेंसिव क्रिकेट खेलना नहीं आता था. दूसरे खिलाड़ी गेंद को रोककर पुरानी करने में यकीन करते थे और सहवाग गेंद को पीट-पीटकर पुरानी करने में.

सहवाग जैसे धमाकेदार क्रिकेटर की धमाकेदार विदाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें वैसी विदाई नहीं मिल सकी. उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का बेहद निराशाजनक अंत हुआ. मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के बाद उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया. इसके बाद वह टीम में वापसी नहीं कर पाए. जैफरी बायकॉट ने दो साल पहले ही बयान दिया था कि सहवाग अपना अंतिम टेस्ट खेल चुके हैं, वह वापसी नहीं कर पाएंगे. दुःखद यह है कि बायकॉट की भविष्यवाणी सही साबित हुई. सहवाग की आंखें कमजोर हो गई थीं, इस वजह से भी उन्हें खेलने में परेशानी हुई. वह चश्मे के साथ मैदान पर संतुलन नहीं बना सके, उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी राह की सबसे बड़ी बाधा बन गई. सहवाग जैसे क्रिकेटर एक बार पैदा होते हैं. उनके जैसा खिलाड़ी बनाया नहीं जा सकता, जो खेल के नियम बदल सके, उन्हें हमेशा भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर के और सर्वकालिक महान बल्लेबाज के रूप में याद किया जाएगा.■

navinonline2003@gmail.com

ज़हीर ख़ान का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

क़ाबिलियत पर भारी चोटें

तेज गेंदबाज ज़हीर खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज़ ने लंबे समय तक भारतीय आक्रमण की बागडोर संभाली. वह पिछले कुछ समय से फिटनेस की समस्या से जूझ रहे थे. इस वजह से वह लगातार टीम इंडिया से बाहर रहे . खान ने आखिरी टेस्ट फरवरी, 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. वहीं आखिरी वनडे अगस्त, 2012 में श्रीलंका के खिलाफ पल्लीकल में खेला था. इसके बाद वह टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सके. हालांकि इस बीच साल 2015 में उन्होंने आईपीएल में वापसी की, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह धार नहीं दिखी जिसके लिए वह जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में टीम इंडिया की ओर से कुल 92 टेस्ट खेले और 311 विकेट हासिल किए, जबकि 200 वनडे मैचों में 282 विकेट हासिल किए. इसके अलावा 17 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैचों में 17 विकेट लिए. ज़हीर ने भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 610 विकेट चटकाए. उन्होंने केन्या में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला एकदिवसीय मैच खेला था और बांग्लादेश के खिलाफ साल 2000 में अपने टेस्ट करियर की शुरूआत की थी. इसके बाद अगले 14 साल तक वह भारत के मुख्य गेंदबाज़ रहे. इस दौरान उन्होंने भारत को कई टेस्ट जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

भारतीय क्रिकेट टीम में न जाने कितने तेज़ गेंदबाज आए और गए, लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की और विश्व स्तर देश के साथ-साथ अपना नाम भी रोशन किया. यदि कपिल देव भारत के सर्वकालिक महानतम तेज गेंदबाज हैं तो जहीर उनके बाद दूसरे पायदान पर हैं. ज़हीर ख़ान ने उस दौर में भारतीय गेंदबाज़ी की कमान थामी थी जब टीम में तेज गेंदबाजों के अंदर-बाहर जाने का दौर चल रहा था. कोई भी गेंदबाज स्थाई तौर पर टीम में जगह बना पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था. व्यंकटेश प्रसाद जवागल श्रीनाथ और अजीत आगरकर जैसे गेंदबाजों के साथ वह खेले. आशीष नेहरा लेकिन धीरे-धीरे वह भारतीय गेंदबाजी की धुरि बन गए. विकेटों के मामले में ज़हीर भारत के चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं. वह टेस्ट मैचों में भारत के लिए दूसरे सबसे सफल तेज़ गेंदबाज हैं.

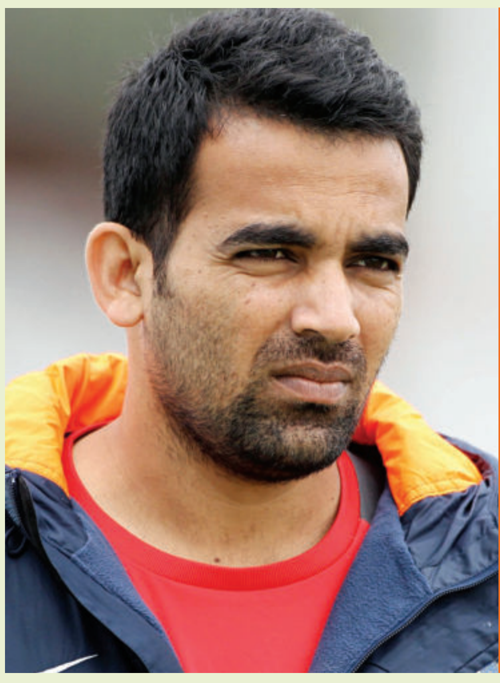

आज लोग महेंद्र सिंह धोनी को छोटे शहर केबड़े सितारे के रूप में जानते हैं, लेकिन छोटे शहर का एक बड़ा सितारा ज़हीर थे, जिन्होंने विनम्र और संयमित रहते हुए, टीम इंडिया के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया. जिस भारतीय टीम को सौरव गांगुली ने खड़ा किया उसका बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा ज़हीर खान थे. शायद ज़हीर को हमेशा 2003 के विश्वकप के फाइनल के पहले ओवर के लिए याद किया जाए, जिसमें गिलक्रिस्ट और हेडेन की जोड़ी ने उनकी लाइन-लेंथ बिगाड़ दी थी.

ज़हीर ख़ान के पास गेंद को दोनों ओर स्विंग कराने की काबीलियत थी. साथ ही उन्हें रिवर्स स्विंग कराने में महारत हासिल थी. उनकी यॉर्कर गेंदों का हर कोई कायल था. लंबे समय बाद भारत को एक ऐसा गेंदबाज मिला, जो उप-महाद्वीप की फ्लैट पिचों पर तेज गेंदबाजी का जादू दिखा रहा है. उनका हर तरह की गेंद में गज़ब का कंट्रोल था. उन्हें यॉर्कर फेंकने में महारथ हासिल थी. जब उन्होंने अपने करियर की पहली प्रतियोगिता में अपने इस हथियार की बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया. तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के बाद उनके खेल में साल-दर साल सुधार होता गया.

महाराष्ट्र के छोटे से शहर श्रीरामपुर के रहने वाले ज़हीर खान इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता ने कहा कि बेटा इंजीनियर तो बहुत हैं तुम तेज गेंदबाज ही बनो. इसके बाद वह मुंबई आए और मुंबई में जूनियर क्रिकेट खेली. उनकी प्रतिभा को सबसे पहले एमआरएफ पेस फाउंडेशन के टीए शेखर ने पहचाना और उन्हें चेन्नई बुलाया. इसके बाद उनके करियर को पर लग गए.चेन्नई में शेखर ने उनकी गेंदबाजी को निखारा. इसके बाद भी जब कभी जहीर को जरूरत पड़ी उन्होंने उनका सहयोग किया. महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मे ज़हीर ख़ान की किस्मत 21 साल की उम्र में बदली, जब उन्हें पहली बार इंटरनेशनल टीम में शामिल करने के लिए नोटिस किया गया. 23 अप्रैल, 2000 को रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच के आखिरी दिन जहीर ने बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए 21 रन देकर 5 विकेट लिए और टीम को जीत दिलाई. उनके इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा और उन्हें टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया.

जहीर को गेंदबाजी के लंबे स्पेल करने में मज़ा आता था. उन्हें टेस्ट क्रिकेट और उसका माहौल पसंद था. एक तेज़ गेंदबाज के लिए अपने को हमेशा चुस्तदुरुस्त रखना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. ज़हीर खान इस चुनौती से पार नहीं पा सके. पहले तो जहीर की गेंदबाजी पर वजन बढ़ने का असर हुआ, इसके बाद चोटों ने उन्हें लगातार परेशान किया. वह टीम से बाहर हो गए. वापसी के लिए वह काउंटी क्रिकेट खेलने गए. साल 2006 में का यह काउंटी सीजन उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ, इंग्लिश काउंटी वार्विकशायर के लिए खेलते हुए उन्होंने सबसे पहले अपना रन-अप छोटा किया और गति के साथ-साथ चालाकी से विकेट लेने में सफलता हासिल की. इंग्लैंड से वह एक चपल और चालाक गेंदबाज बनकर लौटे.

ज़हीर को यह मालूम था कि उनके सामने खड़े बल्लेबाज को किस तरह आउट किया जा सकता है. यह कला हर किसी में नहीं होती,इसके लिए आपका तकनीकि तौर पर दक्ष होना जरूरी है. एक गेंदबाज़ में विकेट लेने की कला होना बेहद आवश्यक होता है. एक महान गेंदबाज की खासियत होती है कि वह ऐसा किस अंदाज में करता है. ज़हीर को यह बहुत अच्छे से मालूम था कि किस बललेबाज़ को किस जगह और कैसी गेंद फेंकनी है. उदाहरण के लिए जहीर खान ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ग्रीह्म स्मिथ को 27 भिडंत में से 14 बार पैवेलियन वापस लौटाया.

आज लोग महेंद्र सिंह धोनी को छोटे शहर के बड़े सितारे के रूप में जानते हैं, लेकिन छोटे शहर का एक बड़ा सितारा ज़हीर थे, जिन्होंने विनम्र और संयमित रहते हुए, टीम इंडिया के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया. जिस भारतीय टीम को सौरव गांगुली ने खड़ा किया उसका बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा ज़हीर खान थे. शायद ज़हीर को हमेशा 2003 के विश्वकप के फाइनल के पहले ओवर के लिए याद किया जाए, जिसमें गिलक्रिस्ट और हेडेन की जोड़ी ने उनकी लाइन-लेंथ बिगाड़ दी थी, उनकी वह आक्रामकता टीम के लिए घातक सिद्ध हुई थी और भारत विश्व चैंपियन बनते-बनते रह गया था. लेकिन 2011 के विश्वकप में उन्होंने जैसी गेंदबाजी की उसे प्रशंसक कभी भूल नहीं पायेंगे. टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में उनके 21 विकेटों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. वह कप्तान के गेंदबाज थे जब कभी कप्तान परेशानी में होते, तब वह गेंद जहीर के हाथों में थमा देते थे. जहीर ने भी अपने कप्तान को कभी निराश नहीं किया, उनकी ओवर दि विकेट से फेंकी अंदर आती यॉर्कर गेंदों को भुला पाना आसान नहीं होगा. वह रिवर्स स्विंग की कला मे माहिर थे. अपनी रिवर्स स्विंग गेंदबाज़ी से वे अपने दौर के दिग्गज बल्लेबाज़ों को भी छकाने में कामयाब रहे. चोटों ने उनके करियर को समय से पहले खत्म कर दिया. बांय हाथ के सर्वश्रेष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज के साथ-साथ विश्व के सर्वकालिक श्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

डीडीएलजे ने पूरे किए दो दशक

यशराज फिल्म्स ने फिल्म के 20 साल पूरे होने पर 20 अक्टूबर को एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, जिसमें इस फिल्म के एक गीत को शाहरुख-काजोल की जोड़ी ने एक बार फिर से जीवित किया है. 20 साल पहले 20 अक्टूबर, 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का जादू आज भी बरकरार है.

बॉलीवुड की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे (डीडीएलजे) ने अपनी सफलता के 20 साल पूरे कर लिए हैं. यशराज फिल्म्स इसका जश्न एक अनोखे अंदाज में मना रहा है. करोड़ों दिलों की धड़कन शाहरुख ख़ान और काजोल भी फिल्म के 20 साल के जश्न में शामिल हैं. मुंबई के मराठा मंदिर में यह फिल्म आज भी लगी है. 20 साल बाद भी इस फिल्म को लेकर लोगों में बड़ा क्रेज है. यशराज फिल्म्स ने फिल्म के 20 साल पूरे होने पर 20 अक्टूबर को एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है, जिसमें इस फिल्म के एक गीत को शाहरुख-काजोल की जोड़ी ने एक बार फिर से जीवित किया है. 20 साल पहले 20 अक्टूबर, 1995 को यह फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का जादू आज भी बरकरार है. शाहरुख और काजोल ने इस फिल्म के एक नए पोस्टर के जरिए इस जादू को एक बार फिर तरोताज़ा किया है. पोस्टर में शाहरुख ख़ान, काजोल को कंधे पर उठाए हुए हैं. दोनों के चेहरे पर खुशी है. फोटो के शीर्षक पर लिखा है कि आखिरी क्षणों में ऐसा करने के लिए निर्देशक रोहित शेट्टी और रेड चिलीज़ को बहुत धन्यवाद. पोस्टर में शाहरुख वही फेडोरा कैप पहने हुए हैं, जो उन्होंने डीडीएलजे में पहनी थी. डीडीएलजे के नाम भारतीय सिनेमा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड दर्ज है. ■

डॉन-3 की स्टारकास्ट में कोई फेरबदल नहीं

निर्माता रितेश सिधवानी का कहना है कि डॉन सीरीज की तीसरी फिल्म में एक बार फिर शाहरुख ख़ान और प्रियंका चोपड़ा नज़र आएंगे. इस सीरीज की पहली दो फिल्मों को फरहान अख्तर ने निर्देशित किया था. फिल्म डॉन-3 से वह फिर वापसी कर रहे हैं. सिधवानी ने कहा कि अभी टीम फिल्म की पटकथा पर काम चल रहा है. अब तक तक फिल्म के कलाकारों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है. उन्होंने ट्विट कर लोगों को बताया कि डॉन-3 और इसके कलाकारों को लेकर कई तरह की चर्चायें चल रही हैं. इसके कलाकारों में फेरबदल का कोई विचार नहीं है. इस सीरीज की पहली फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी, जबकि दूसरी फिल्म 2011 में आई थी. दोनों ही फिल्में बेहद सफल रही थीं. ■

किंग ख़ान डॉक्टरेट से सम्मानित हुए

किंग ख़ान अपने फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकेहैं. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना, मुंबई के अस्पतालों में बच्चों के लिए वार्ड बनवाना और सुनामी में तबाह हुए क्षेत्रों की सहायता के लिए राहत राशि इकट्ठा करना आदि शाहरूख द्वारा किए गए समाजसेवा के कार्यों में शामिल है. शाहरुख ने सम्मान लेते हुए कहा कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से यह सम्मान पाकर और विश्व के महान विचारकों, नेताओं और व्यक्तियों के नक्शेकदम पर चलकर मैं प्रसन्न हूं. दुनिया के सबसे सम्मानीय शैक्षिक संस्थानों में एक को संबोधित करना मेरे लिए गर्व की बात है.

बॉलीवुड स्टार शाहरुख ख़ान को स्कॉटैलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है. उपाधि लेने के बाद शाहरुख ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे इसके कितने हकदार हैं, चूंकि इससे उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए उन्हें लगता है कि वे इसके इतने हकदार तो हैं. उन्होंने कहा कि मुझे कई बार दिन में 18-18 घंटे तक काम करना पड़ता है, पर उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है. आप जब मनोरंजन उद्योग में होते हैं तो लोगों की अपेक्षाओं पर उतरने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है. 49 वर्षीय शाहरुख को यह सम्मान विश्वविद्यालय के कुलपति ने दिया. उन्हें यह सम्मान परोपकार, परहितवाद और मानवतावाद के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान और अभिनेता के रूप में उनकी वैश्विक पहुंच को देखते हुए दिया गया. किंग खान अपने फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना, मुंबई के अस्पतालों में बच्चों के लिए वार्ड बनवाना और सुनामी में तबाह हुए क्षेत्रों की सहायता के लिए राहत राशि इकट्ठा करना शाहरूख द्वारा किए गए समाजसेवा के कार्यों में शामिल है. शाहरुख ने सम्मान लेते हुए कहा कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से यह सम्मान पाकर और विश्व के महान विचारकों, नेताओं और व्यक्तियों के नक्शेकदम पर चलकर मैं प्रसन्न हूं. दुनिया के सबसे सम्मानीय शैक्षिक संस्थानों में से एक को संबोधित करना मेरे लिए गर्व की बात है. शाहरुख ने यहां दिए अपने भाषण में कहा कि अभिनेता आत्ममुग्ध नहीं होते हैं. यदि ऐसा हुआ तो मैं अगले दिन अपने से बिल्कुल अलग किस्म के इंसान की भूमिका नहीं निभा पाऊंगा. आप अलग-अलग दिन अलग-अलग भूमिकाएं करते हैं, ऐसे में आप खुद पर फोकस नहीं कर सकते, आत्ममुग्ध होने की बात तो दूर है. शाहरुख ख़ान ने फिल्मों में महिलाओं की बढ़ती भूमिकाओं के बारे में कहा कि भारत में औरतें अपनी जगह बना रही हैं, लेकिन उन्हें पूरा न्याय अभी नहीं मिल पा रहा है, उनके साथ अब भी भेदभाव होता है. फिल्म उद्योग में उन्हें समान फीस मिलनी चाहिए, पर इसमें वक्त लगेगा. शाहरुख ने बताया कि मैं अपनी कंपनी में हीरोइनों का नाम पहले देता हूं. उन्होंने कहा कि मैं यह मानता हूं कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को कम पैसे मिलते हैं, पर अब स्थितियां बदल रही हैं. फिल्मों को कामयाब बनाने में अभिनेत्रियों की भूमिका उनसे ज्यादा रहती है, वे मेहनत अधिक करती हैं, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुग्धा कहेंगी इश्क ने क्रेजी किया रे

प्यार और मोहब्बत के शहर आगरा की प्रोडक्शन कंपनी नालंदा आरएसजी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड 30 नवंबर को इस सीजन की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल फिल्म इश्क ने क्रेजी किया रे लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म के निर्माता आलोक सिंह, संतोष कटारा एंव राधे श्याम शर्मा हैं. तीनों ही ताज नगरी आगरा के जानी-मानी औद्योगिक सख्शियत हैं.

फिल्म की कहानी लेखक तनवीर ख़ान ने लिखी है. इश्क ने क्रेजी किया रे एक म्युजिकल लव स्टोरी है जिसे निर्देशक नरेश मलहोत्रा ने बड़ी ही खूबसूरती से फिल्माया है. नरेश मलहोत्रा ये दिल्लगी के बाद निर्देशन में वापसी कर रहे हैं. नरेश मलहोत्रा ने इस फिल्म में अपने निर्देशन का जादू दिखाया है. फिल्म का खूबसूरत फिल्मांकन व जादूई संगीत दर्शकों को एक नए संसार में ले जाता है, जहां एक ओर वे इसके जादुई संगीत में खो जायेंगे, वहीं दूसरी ओर फिल्म के मुख्य किरदारों को एक अनोखे झंझावट में फंसा पाएंगे. जहां मुहब्बत और महत्वकांक्षा के बीच एक जंग छिड़ी हुई है, प्रेम की इस जंग में दोनों का क्या होगा, यहीं जानने की चाहत दर्शकों को क्रेजी कर देगा.

फिल्म निर्माताओं के मुताबिक फिल्म का संगीत इस फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू है, जिसे संगीत के दुनिया के दिग्गज संगीतकारों ललित पंडित, मीत ब्रदर्स, अंजन, ऋषि सिंह जैसे नामों ने अपने संगीत से संवारा है. विशेष रुप से मीत ब्रदर्स - अंजन का गाना यंग-यंग लौंडे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है. फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन पीवीआर सिनेमा कर रही है, फिल्म पूरे हिंदुस्तान में आगामी 30 नवंबर को रिलीज हो रही है.

फिल्म में मुख्य कलाकार जानीमानी अभिनेत्री मुग्धा गोडसे व दक्षिण भारतीय अभिनेत्री मधुरिमा हैं. फिल्म में अभिनेता हैं निशांत मलकानी, जिनकी पिछली फिल्मों बेजुबां इश्क व हॉरर स्टोरी ने अच्छी तारिफें बटोरी थीं. असलम खान ने फिल्म के सभी गीतों को कोरियोग्राफ किया है. फिल्म के प्रचार अभियान की सहयोगी कंपनियों में सामाचार पत्र समूह पंजाब केसरी, चौथी दुनिया, फैशन पत्रिका वि-मेन आन टॉप, गुड हेल्थ और फिल्म पत्रिका मायापुरी, आउटडोर कंपनी ब्राइट व मलिक आउटडोर हैं. छायांकन मशहूर कैमरामैन राजू रेजी का है. कॉरपोरेट समन्वय दुष्यंत प्रताप सिंह देख रहे हैं. प्रचार अभियान की कमान प्राग देसाई के हाथों में है. कुल मिलाकर सभी को 30 नवंबर का इंतजार है जब इंडिया बोलेगा इश्क ने क्रेजी किया रे. ■

रितिक ने छोड़ी निखिल की फिल्म!

फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि रितिक रोशन ने निखिल आडवाणी की फिल्म का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है. पहले उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी थी. उनके हां कहते ही निखिल ने अपनी इस फिल्म को कुछ समय के लिए रोक दिया था. हालांकि रितिक ने आधिकारिक तौर पर हामी नहीं भरी थी, इसलिए निखिल ने फिल्म को टालने का मन बनाया है. रितिक ने निखिल से फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी. उन्हें शुरूआत में स्क्रिप्ट भी पसंद आई थी. लेकिन अब रितिक कह रहे हैं कि उनके पास फिल्म के लिए डेट्स नहीं हैं. ऐसे में वह फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं. फिलहाल वह अपने को-प्रोडक्शन की फिल्म एयरलिफ्ट पर फोकस कर रहे हैं. जनवरी तक यह फिल्म शुरू नहीं होगी. हालांकि इसके लिए उन्हें लीड एक्टर की तलाश है. यह भी कहा जा रहा है कि निखिल आडवानी की पिछली दो फिल्में फ्लॉप रही हैं, इसलिए रितिक उनके साथ काम करने से बच रहे हैं. ऐसे भी रितिक एक समय में एक फिल्म मे काम करते हैं. अभी वह आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदड़ो में काम कर रहे हैं, इसके बाद वह कृष्ण आचार्य की फिल्म में जुट जायेंगे. ऐसे में वह अभी किसी नए प्रोजेक्ट के संबंध निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं. ■

बिग-बी ने संगीत सुनते हुए करवाई सर्जरी

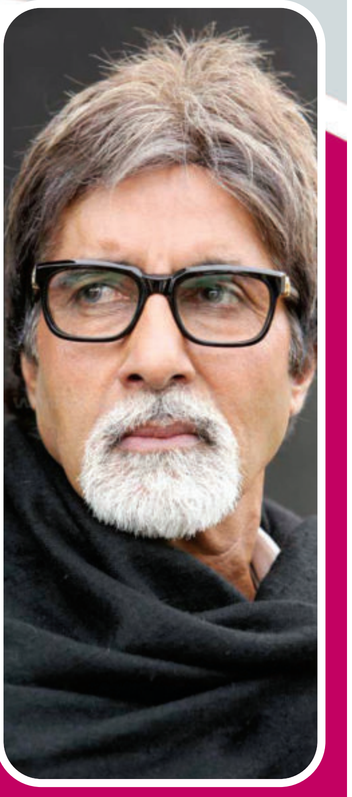

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक नया खुलासा किया है. बिग-बी ने अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने दो बार संगीत सुनते-सुनते सर्जरी करवाई है. वह संगीत को एक अच्छा दर्दनाशक मानते हैं. वह समय-समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं. हाल ही में अपना 73 वां जन्मदिन मनाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कई दिन और रातें मैनें आईसीयू और अस्पताल के बिस्तरों पर गुजारे हैं, संगीत ने हमेशा मेरी रक्षा की है और यह मुझे प्रोत्साहित करता रहा है. मेरे पेट की दो बार सर्जरी हुई और मैं कानों में हेड फोन लगाकर संगीत सुनता रहा. अमिताभ आजकल अपने नए टीवी कार्यक्रम आज की रात है जिंदगी के प्रमोशन में व्यस्त हैं. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
बिहार-झारखंड
02 नवंबर-08 नवंबर, 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

पप्पू पास हुए तो कई होंगे फेल

भाजपा और उसके सहयोगी दलों- हम को छोड़ कर- ने अपना चुनाव अभियान लालू प्रसाद की कठोर से कठोर आलोचना तक ही केन्द्रित रखा और उनकी कथनी-करनी व सरकार को ही निशाना बनाया. भाजपा और एनडीए के चुनाव अभियान का मूल मुद्दा ही जंगलराज-2 रहा. इसका जो भी लाभ मिला हो, पर बिहार की अगड़ी जातियों के लालू-विरोध को इसने काफी हद तक शान पर चढ़ाया. अगड़े सामाजिक समूहों के उत्कट और आक्रामक लालू-विरोध की राजनीति का लाभ भाजपा हासिल करती रही है. इस चुनाव में भी इस नकारात्मक मुद्दे का पूरा लाभ हासिल करने की हरसूरत कोशिश कर रही है.

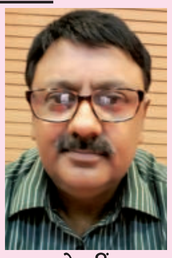

सरोज सिंह

बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में 81 सीटों पर सम्पन्न मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और बिहार में एनडीए के चुनावी कमांडर अमित शाह ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) इनमें लगभग तीन चौथाई सीटों पर जीत रहा है. उनका दावा रहा कि यह गठबंधन इन दो चरणों में 54-58 सीट हसिल करेगा. इसके बरअक्स, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू-राजद-कांग्रेस के महागठबंधन ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई समग्र दावा नहीं किया है. पर, उसके नेता अपने-अपने तौर पर 65-70 सीट तक जीतने का दावा करते रहे हैं. इन दावों के बारे में कुछ कहना बेमानी है, क्योंकि ये राजनेता अपने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की हौसला अफ़ज़ाई के लिए जिस हद तक संभव होता है, वास्तविकता से दूर ही होते हैं. अमित शाह के दावों को इससे अधिक कुछ नहीं माना जा रहा है. पर, इतना तो साफ है कि बिहार का चुनावी परिदृश्य अब तक किसी के लिए भी भ्रांतियों का पिटारा ही है और कोई राजनीतिक ध्रुव अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होने में परेशानी महसूस कर रहा है. इन पंक्तियों के आपके पास पहुंचने तक पचास और सीटों के मतदान हो चुके रहेंगे. अर्थात राज्य के आधे से अधिक मतदाता अपने वोट दे चुके होंगे, पर सूबे के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में किसी सुधार की उम्मीद कम ही दिखती है. ऐसा नहीं लगता है कि बिहार की चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी और सत्ता के दोनों दावेदार-एनडीए और महागठबंधन- किसी तरह से आश्वस्त हो चुके रहेंगे. ऐसी किसी आशवस्ति के लिए राजनीतिक दलों, पंडितों और राज्य के मतदाताओं को अगले दो चरणों की प्रतीक्षा करनी होगी. संभव है, प्रतीक्षा की घड़ी मतगणना तक खिंच जाए.

बिहार की सत्ता की लड़ाई अब अंतिम और महत्वपूर्ण दौड़ में पहुंच गई है. चौथे और पांचवें चरण में तिरहुत, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा प्रमंडलों के जिलों की विधानसभा की 112 सीटों के लिए मतदान होने हैं. इनमें सारण प्रमंडल के कुछ जिले भी हैं. इन चरणों में चुनावी राजनीति के कई फैक्टर की अग्नि-परीक्षा भी होनी है. राजनीतिक दलों के घोषित प्रभाव क्षेत्र के तौर पर क्षेत्रों की पहचान इस चुनाव में कठिन है.

बिहार की सत्ता की लड़ाई अब अंतिम और महत्वपूर्ण दौड़ में पहुंच गई है. चौथे और पांचवें चरण में तिरहुत, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा प्रमंडलों के जिलों की विधानसभा की 112 सीटों के लिए मतदान होने हैं. इनमें सारण प्रमंडल के कुछ जिले भी हैं. इन चरणों में चुनावी राजनीति के कई फैक्टर की अग्नि-परीक्षा भी होनी है. राजनीतिक दलों के घोषित प्रभाव क्षेत्र के तौर पर क्षेत्रों की पहचान इस चुनाव में कठिन है. पिछले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक स्थिति भिन्न थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा था और भाजपा उसमें साझीदार थी. उस चुनाव में नीतीश कुमार (या तत्कालीन एनडीए कहिए) के पक्ष में लहर थी और उन्हें ऐतिहासिक जनादेश मिला था. कुछ वैसा ही माहौल पिछले संसदीय चुनावों में था- बदलाव की चाहत में नरेन्द्र मोदी विकल्प के केन्द्र थे. इन लहरों में

यह कहना कठिन है कि बिहार के किस भू-भाग में किस राजनीतिक दल का कैसा असर है और मतदान की हालत कैसी रहेगी? लेकिन यह माना जा रहा है कि चौथे और पांचवें चरण में जिन इलाकों में मतदान होने हैं, वहां माय का प्रभाव अच्छा खासा है. इन चरणों में पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के विधानसभा क्षेत्रों को उनकी सामाजिक संरचना के ख्याल से लालू प्रसाद के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता रहा है. माना जाता है कि दरभंगा, तिरहुत और सारण प्रमंडलों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोटरों के ध्रुवीकरण की स्थिति में महागठबंधन का पलड़ा ही भारी रहेगा. इस लिहाज़ से अगले चरणों में लालू-नीतीश जोड़ी की राजनीति दांव पर है. उनकी पिछड़ावादी और सम्प्रदाय विरोधी राजनीति की अग्नि-परीक्षा होनी है. एनडीए का नेतृत्व भाजपा कर रही है और सूबे में यह शहरी मध्यवर्ग और ग्रामीण बिहार के सम्पन्न तबके की पार्टी के तौर पर पहचानी जाती है. बिहार में अड़तीस जिले हैं और इनमें से राजधानी पटना की चार सीटों सहित तीस से अधिक जिला मुख्यालयों पर भाजपा का कब्जा है. पटना व जिला मुख्यालयों के निर्वाचन क्षेत्रों पर भाजपा पिछले कई चुनावों से विजयी होती रही है. अर्थात निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के एक तिहाई से अधिक सहस्य शहरी निर्वाचन क्षेत्रों से हैं.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

एक नज़र

सीवान

मतदाताओं की चुप्पी से उम्मीदवारों में बेचैनी

शम्भू प्रसाद अभय feedback@chauthiduniya.com

बिहार विधान सभा चुनाव में सीवान जिले में चौथे चरण में मतदान होना है, जिले के आठों विस सीटों पर सभी दलीय व निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल कर मतदाताओं की गोलबंदी अपने पक्ष में करने का प्रयास तेज कर दिया गया है. उम्मीदवारों द्वारा रातों-दिन एक कर जनसंपर्क चलाया जा रहा है. लेकिन मतदाताओं की चुप्पी ने सभी को परेशान कर रखा है. मतदाताओं द्वारा सभी उम्मीदवारों को भरपूर आश्वासन दिया जा रहा है.

अगर हम जिक्र करें रघुनाथपुर विधान सभा क्षेत्र का तो यहां की लड़ाई काफी रोचक है. पूर्व विधान पार्षद मनोज कुमार सिंह को यहां से भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं राजद की ओर से हरीशंकर यादव व भाकपा माले की ओर से अमरनाथ यादव भी चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, भाजपा द्वारा निवर्तमान विधायक विक्रम कुंवर का टिकट काट कर मनोज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है. यहां विकास व जाति के आधार पर ही मतदान होने की संभावना प्रबल दिख रही है. बुद्धिजीवी लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर का इलाका विकास के मामले में काफी पिछड़ा है, हमलोग इस बार जाति धर्म से हटकर विकास करने वाले उम्मीदवार को वोट करेंगे. इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 265245 है जिसमें पुरुष 140889 व महिला 124346 व अन्य 10 मतदाता शामिल हैं.वहीं महराजगंज विधान सभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से निवर्तमान विधायक डॉ. देवरंजन प्रसाद व जदयू की ओर से हेमनारायण साह, कम्यूनिस्ट के मुंशी सिंह, जनाधिकार मंच में ध्रुव प्रसाद आदि चुनावी मैदान में हैं. यहां कुल मतदाताओं की संख्या 276408 है जिसमें पुरुष 144419 व महिला 131983 व 6 अन्य मतदाता शामिल हैं. समूचे इलाके में राजनीतिक पारा चढ़ चुका है. नेता वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रहे है. यहां भी जनता की खामोशी सभी के माथे पर चिंता की लकीर खिंच रही है. वहीं गोरयाकोठी विधान सभा क्षेत्र में भी राजनीतिक तापमान सातवें आसमान पर है. निवर्तमान विधायक के पुत्र देवेशकांत सिंह को भाजपा गठबंधन द्वारा यहां से उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं राजद द्वारा सत्यदेव सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा भाजपा के बागी अशोक सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा व राजद का भी कब्जा रहा है. विगत चुनाव में भाजपा के भूमेन्द्र नारायण सिंह ने राजद के उम्मीदवार सह पूर्व मंत्री इन्द्रदेव प्रसाद को हराया था. तब से यह सीट भाजपा के कब्जे में थी. अब देखना यह है कि इस सीट पर किसका कब्जा रहता है. यहां कुल मतदाताओं की संख्या 299463 है जिसमें पुरुष मतदाता 156353 व महिला मतदाता 143101 व अन्य मतदाता 9 है. सभी क्षेत्रों में युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. युवा इस बार विकास के नाम पर वोट डालने की मंशा पाल चुके हैं. युवाओं का कहना है कि बहुत हुई जाति-धर्म की राजनीति अब केवल विकास-विकास चलेगा.

जब कोई उम्मीदवार वोट मांगने के लिए गांवों में जा रहा है तो युवा वर्ग गांव के विकास पर सवाल दागा जा रहा है, जिसके चलते नेताजी काफी परेशान हो रहे हैं. इन तीनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़कों की दशा काफी खराब है. सबसे खराब स्थिति किसानों की है, इन लोगों को न तो समय से खाद मिलता है और न ही समय से पानी. किसानों में खासी नाराजगी है.■

दांत में दर्द
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
Carbo - XT Drops
A Colic Drops
Siliplex Syp.
Ofloygyl-OZ Susp.
Acoba Syp.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.

मगध में मतदान

अप्रत्याशित परिणाम की संभावना से धड़कन तेज

बिहार विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के अंतर्गत मगध में हुए मतदान में बढ़े वोट को महागठबंधन और एनडीए अपना-अपना हिस्सा मान रहे हैं और फायदे की बात कर रहे हैं. लेकिन मतदान के बढ़े प्रतिशत से महागठबंधन और एनडीए के कई प्रत्याशियों में बेचैनी है. कयास यह लगाये जा रहे हैं कि वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी से मगध में कम से कम आधे से अधिक सीटों के परिणाम अप्रत्याशित होंगे! एनडीए और महागठबंधन के लिए जो सीटें परंपरागत मानी जाती रही हैं. वैसे विधानसभा क्षेत्रों का परिणाम भी इस बार चौंकाने वाला हो सकता है.

सुशील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

मतदाता जागरूकता की वजह से वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी से जहां चुनाव आयोग गदगद है, वहीं इसने एनडीए और महागठबंधन को मुश्किल में डाल रखा है. वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी से अप्रत्याशित परिणाम की संभावना है, जिस कारण प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गयी हैं. वोट की बढ़ोतरी निर्णायक भूमिका अदा करेगी, ऐसी जनचर्चा है.

विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण के अंतर्गत मगध में हुए मतदान में बढ़े वोट को महागठबंधन और एनडीए अपना-अपना हिस्सा मान रहे हैं और फायदे की बात कर रहे हैं. लेकिन मतदान के बढ़े प्रतिशत से महागठबंधन और एनडीए के कई प्रत्याशियों में बेचैनी है. कयास यह लगाये जा रहे हैं कि वोट प्रतिशत की बढ़ोतरी से मगध में कम से कम आधे से अधिक सीटों के परिणाम अप्रत्याशित होंगे! एनडीए और महागठबंधन के लिए जो सीटें परंपरागत मानी जाती रही हैं, वैसे विधानसभा क्षेत्रों का परिणाम भी इस बार चौंकाने वाला हो सकता है. इस बार के मतदान में महिलाएं और युवाओं की बड़ी भागीदारी ने हर किसी को सोचने को बाध्य कर दिया है. ऐसे कहा जाए, तो 2010 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार के मतदान में औसत रूप से तीन से पांच प्रतिशत ही बढ़ोतरी हुई है. लेकिन लोगों को अनुमान है कि यह वोट प्रतिशत ही मगध के चुनावी परिणाम को उलट-पलट कर सकता है.

> मतदान में बढ़ोतरी पर एनडीए का कहना है कि मतदान केन्द्रों पर इमड़ी भीड़ यह संकेत दे रहा है कि लोग वर्तमान सरकार से आजिज हैं और बदलाव चाहते हैं. बिहार को विकसित देखना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपने साथ हुए ठगी का बदला चुकाने जनता बूथों पर आयी है. दोनों महागठबंधनों ने मगध में 26 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 पर जीत का दावा किया है.

द्वितीय चरण के अंतर्गत मगध के गया जिले में मतदान का औसत प्रतिशत 55.57 रहा, जबकि औरंगाबाद में 52.50, जहानाबाद में 56.94, अरवल में 53.2 तथा प्रथम चरण में नवादा में हुए मतदान का औसत 52 प्रतिशत रहा. जबकि 2010 में मतदान का औसत 47 से लेकर 51 प्रतिशत था.

मतदान में बढ़ोतरी पर एनडीए का कहना है कि मतदान केन्द्रों पर इमड़ी भीड़ यह संकेत दे रही है कि लोग वर्तमान सरकार से आजिज हैं और बदलाव चाहते हैं. बिहार को विकसित देखना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपने साथ हुए ठगी का बदला चुकाने जनता बूथों पर आयी है. दोनों महागठबंधनों ने मगध में 26 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 पर जीत का दावा किया है.

ऐसे मगध में जिन विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसमें गया जिले का अतरी, टिकारी, बाराचट्टी, शेरघाटी, गुरुआ व बोधगया, जहानाबाद का जहानाबाद विस क्षेत्र, अरवल का अरवल व कुर्था, औरंगाबाद का नवीनगर, रफीगंज, ओबरा और गोह तथा नवादा जिले का नवादा व वारसलीगंज शामिल है. इन विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए या महागठबंधन में से किसी ने स्पष्ट तौर निश्चित जीत का दावा नहीं किया है. चुनावी लड़ाई का सबसे दिलचस्प मैदान गया में इमामगंज विधानसभा की भूमि मानी जा रही है. संभावना और आशंका के बीच पूर्व मुख्यमंत्री के यहां से चुनावी जंग में कूदने से सबसे ज्यादा चर्चा किसी विधानसभा की हो रही है, तो वो है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र. यहां भी अप्रत्याशित परिणाम की संभावना है. इमामगंज से विधानसभा अध्यक्ष और जदयू प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी तथा पूर्व मुख्यमंत्री व हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्यूलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आमने-सामने है. ऐसे लोगों का मानना है कि जीतनराम मांझी की जीत निश्चित है. मांझी समर्थकों का कहना है कि इतने अधिक मतों के अंतर से उदय नारायण चौधरी पराजित होंगे कि भविष्य में उनके इमामगंज से चुनाव लड़ने की संभावना पर भी प्रश्न चिन्ह लग जायेगा, क्योंकि जिन वोट बैंक पर इनकी दावेदारी थी, वह आज जीतनराम मांझी के साथ हो गया. यहां सर्वाधिक करीब 60 हजार भुईयां हैं, तो 35 हजार पासवान और 45 हजार कुशवाहा-दांगी. अगड़ी जाति तथा पठान जाति के वोट को भी अपना हिस्सा मानने का दावा मांझी द्वारा किया जा रहा है. ऐसे देखा जाये, तो इदय नारायण चौधरी हमेशा चार सौ से लेकर दो हजार मतों के अंतर से ही चुनाव जीतते रहे हैं, जिस कारण अप्रत्याशित परिणाम की संभावना से इंकार करने का कोई तर्क नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

पप्पू पास हुए तो कई होंगे फेल

इसके बरअक्स, ग्रामीण बिहार के ग्रामांचल में उसका गुणात्मक विकास व विस्तार हुआ. यह भी वास्तविकता है कि तत्कालीन समता पार्टी- जिसका बाद में जद(यू) में विलय हो गया-के साथ होने का इसे लाभ मिला और इसने उसका फायदा भी उठाया. इस चुनाव में इसका भी आकलन हो सकेगा कि गठबंधन की राजनीति का लाभ प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में उसे कितना मिला? लेकिन इन सबों से अधिक भाजपा के लालू विरोधी चुनाव अभियान की परीक्षा होनी है. भाजपा और उसके सहयोगी दलों- हम को छोड़ कर- ने अपना चुनाव अभियान लालू प्रसाद की कठोर से कठोर आलोचना तक ही केन्द्रित रखा और उनकी कथनी-करनी व सरकार को ही निशाना बनाया. भाजपा और एनडीए के चुनाव अभियान का मूल मुद्दा ही जंगलराज-2 रहा. इसका जो भी लाभ मिला हो, पर बिहार की अगड़ी जातियों के लालू-विरोध को इसने काफी हद तक शान पर चढ़ाया. अगड़े सामाजिक समूहों के उत्कट और आक्रामक लालू-विरोध की राजनीति का लाभ भाजपा हासिल करती रही है.

इस चुनाव में भी इस नकारात्मक मुद्दे का पूरा लाभ हासिल करने की हरसूरत कोशिश कर रही है. सो, मतदान के पिछले चरणों की तरह अगले चरणों में भी यह देखना दिलचस्प रहेगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है- भाजपा के इस नकारात्मक अभियान का या लालू-नीतीश की पिछड़ावादी राजनीति का. मतदान के अगले चरणों में वाल्मीकिनगर से लेकर किशनगंज तक दांव पर तो माय (मुस्लिम-यादव) ही है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सबसे बड़ी राजनीतिक पूजी यही है. इस चुनाव में महगठबंधन का सामाजिक आधार यही है. लेकिन इस बार सूबे के सबसे पुराने इस राजनीतिक सामाजिक समीकरण पर जबर्दस्त हमला है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन और उसके प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी इस बार बिहार आए हैं. वह पूर्णिया प्रमंडल की चौबीस सीटों पर प्रत्याशी देना चाहते थे, पर दिया केवल छह सीटों पर.

लेकिन ओवैसी और उनके दल का बिहार आना ही लालू प्रसाद के इस समीकरण के लिए खतरे की गोटी है. इसकी थोड़ी भी सफलता लालू प्रसाद और इस बहाने महगठबंधन को परेशानी में डाल सकती है. यह इसलिए भी परेशानी का सबब बन सकता है कि पूर्णिया प्रमंडल में लालू प्रसाद की अल्पसंख्यक राजनीति संकट के दौर से गुजर रही है. अपने दूसरे बेटे को राजद की उम्मीदवारी नहीं मिलने से तस्लीमुद्दीन नाराज

चल रहे हैं. उस इलाके में तस्लीमुद्दीन की नाराजगी मायने रखती है. फिर, अल्पसंख्यकों में भी जमातबंदी काफी बढ़ती जा रही है और राजद सुप्रीमो के साथ अब कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं रहा जो सभी को उनके साथ जोड़ सके. हालांकि कांग्रेसी सांसद मौलाना असरारुल हक का उपयोग किया जा रहा है, पर अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि वह किस हद तक सफल होंगे. समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा-अर्थात् तीसरे मोर्चा में बिखराव और उसके अंतर्विरोध महागठबंधन के लिए सुखद हो सकता है. पर, जनअधिकार पार्टी (जाप) पर अब भी महागठबंधन की परेशानी का एक बड़ा केन्द्र है. इसके सुप्रीमो राजद से बर्खास्त सांसद पप्पू यादव का पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के दर्जन से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में काफी असर माना जा रहा है. पप्पू यादव फिलवक्त एनडीए के काफी करीब हैं और लालू-नीतीश के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इसी तरह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अब इस मोर्चा से बाहर हो गई है. कटिहार और उससे सटे पूर्णिया जिलों की कुछ सीटों पर इसके नेता सांसद तारिक अनवर की पकड़ अच्छी मानी जाती है. इन क्षेत्रों में एनसीपी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं. इन तत्वों के प्रभावी होने का लाभ एनडीए को मिलना तय है. इन तत्वों को बेअसर बनाना लालू-नीतीश की मौजूदा राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत है. वे लगे भी हैं, पर कितना सफल होते हैं, यह देखना है. हालांकि अब तक के मतदान में वाम मोर्चा के उम्मीदवारों को छोड़ कर अन्य किसी तीसरे प्रत्याशी का राजनीतिक प्रभाव यदा-कदा ही देखा गया है. ऐसा राजनीति के साथ-साथ सामाजिक समूहों की तीखी गोलबंदी के कारण ही हुआ है. पूर्णिया-सहरसा प्रमंडलों के ये क्षेत्र अपवाद नहीं हैं. पर, महागठबंधन के साथ-साथ एनडीए भी अब तक यह अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि दो की लड़ाई में तीसरे की क्या हैसियत रहती है, रहती भी है या नहीं. तिरहुत और दरभंगा प्रमंडलों की स्थिति इससे थोड़ी भिन्न है. इन प्रमंडलों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ओवैसी फैक्टर है न पप्पू फैक्टर. लेकिन बागी उम्मीदवारों की भरमार है. ये बागी प्रत्याशी दोनों गठबंधनों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं. मधुबनी, बाबूबरही, हरलाखी, बहादुरपुर, रुन्नीसैदपुर, गायघाट, औराई, रीगा, सुरसंड, शिवहर, कांटी, रक्सौल, चनपटिया, वाल्मीकिनगर, मोतिहारी आदि दर्जनों सीटों पर बागियों के कारण दोनों गठबंधनों के चुनाव प्रबंधकों की जान सांसत में है.

मतदान के बीच में दुर्गापूजा-दशहरे का त्योहार आ गया है. इससे सूबे में राजनीतिक सरगर्मी थोड़ी कम हुई और लोग-बाग इससे इतर सामाजिक जीवन में लौटने लगे. इसने राजनेताओं को हालात के आकलन-समीक्षा का अवसर भी दिया है. लेकिन यह प्रक्रिया किस हद तक सकारात्मक हो रही है, यह विचार का विषय है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछड़ों को भाजपा के साथ गोलबंद करने की नए सिरे से कोशिश शुरू की है. यह कोशिश उन्होंने दो चरणों के मतदान की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कोशिश शुरू की गई है. उन्होंने पटना के पालीगंज की एक सभा में एक बार फिर कहा कि भाजपा ने देश में सबसे अधिक पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया है, इसीलिए पिछड़ावादी कहलाने का हकदार भाजपा ही है. अमित शाह ने बिहार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ माह पहले ही देश को पहला ओबीसी (पिछड़ा) प्रधानमंत्री देने की बात कह कर विवाद को जन्म दिया था. भाजपा अध्यक्ष संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति की जाति बता कर कुछ तो संदेश देना ही चाहते हैं. यह संदेश क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है. हां, यह देखने की जरूरत है कि अगले चरणों के मतदाता देश, और विदेशों की भी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के इस संदेश को कैसे ग्रहण करती है. कारण, यह संदेश तो मतदान की स्थिति की समीक्षा के बाद चुनाव के दरम्यान दिया गया है, फिर यह अनायास तो नहीं है. तो, ऐसा तो नहीं कि आरक्षण को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का नकारात्मक असर पहले दोनों चरणों के मतदान में दिखा है और अब अमित शाह एक बार अगड़ा-पिछड़ा का मसला उछाल कर लालू-नीतीश को प्रभावहीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी.■

feedback@chauthiduniya.com

चीनी मिल बनी चुनावी मुद्दा

समीर मिश्रा/कुमार गौरव

चुनाव की शुरुआत जब होती है तो राजनीतिक दल द्वारा मुद्दे की खोज प्रारम्भ हो जाती है. राज्य स्तरीय मुद्दा तो पार्टी अपने स्तर से भुनाने का प्रयास करती है लेकिन जब विधान सभा का चुनाव प्रारम्भ होता है तो स्थानीय समस्या को अत्यधिक उजागर करने का प्रयास करती है जिससे मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके. ऐसा ही स्थानीय मुद्दा है- मधुबनी विधान सभा स्थित पण्डौल में लोहट चीनी मिल का. इस चीनी मिल के बन्द होने से स्थानीय किसानों का पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है जो राज्य स्तरीय समस्या है. राज्य के विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने जनता को आश्वासन दिया था कि राज्य में जितने भी पुराने उद्योग हैं इसे खोला जाएगा जिससे राज्य की जनता को रोजगार प्राप्त होगा लेकिन दस वर्षों में ऐसा नहीं किया जा सका. जनता को बार-बार आश्वासन दिया गया कि लोहट चीनी मिल को शीघ्र शुरू किया जायेगा लेकिन यह आश्वासन चुनाव के आने तक नहीं निभाया जा सका. विपक्षी पार्टी के लोग और स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति के अभाव में इस चीनी मिल को नहीं शुरू किया जा सका. इस क्षेत्र के आस-पास के लोगों को विश्वास है कि अगली सरकार इस चीनी मिल को पुन: शुरू कर लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करेगी.

इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने 1914 में लोहट चीनी मिल की स्थापना की थी. इस चीनी मिल में उत्पादित चीनी को विदेशों में भी निर्यात किया जाता था. इस मिल में लगभग 1400 लोगों को रोजगार प्राप्त था. मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर आदि के किसानों के लिए यह मिल वरदान था क्योंकि इन्हें नगदी फसल का नगद लाभ प्राप्त हो जाता था. जब तक मिल चालू रहा यहां किसान अत्यधिक खुश थे लेकिन जैसे ही मिल बंद हुआ किसानों के सिर पर आफत आ गयी.

दशकों से अच्छी हालत में चलने वाली इस उद्योग के पार्ट पुराने और बेकाम होते गए. तत्कालीन राज्य सरकार के उदासीनता के कारण इस उद्योग में आधुनिक पार्ट नहीं लगाये गये जिससे इसकी इत्पादन क्षमता में कमी आने लगी. दूसरी तरफ मिल की समस्याओं को लेकर कामगार यूनियन और सरकारी अधिकारियों में ठन जाने के कारण मिल के उत्पादन क्षमता में कमी आने लगी. इस समस्या के कारण कामगारों और किसानों का मिल पर बकाया बढ़ता गया. मिल के कामगार यूनियन के हड़ताल की वजह से लाखों का कच्चा माल बर्बाद हो गया. मिल पर कामगारों और 19 हजार गन्ना किसानों का लगभग 20 करोड़ से ज्यादा का बकाया है. 1996 से लेकर आज तक मिल बन्द है. कभी राज्य की सत्ता के हिस्सेदारी रही भाजपा और महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद ने भी बन्द पड़ी इस मिल को शुरू करने में कोई रुचि नहीं दिखायी. जिसके कारण 150 एकड़ से ज्यादा में बने कृषि फार्म और लगभग 100 एकड़ से ज्यादा में बने कारखाने और अधिकारियों के आवास कार्यालय खण्डहर में तब्दील हो गये. कई एकड़ भू-भाग पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. मिल के करोड़ों की सम्पत्ति की देख-भाल के लिए जो

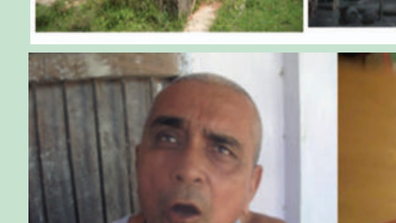

रामदेव महतो

गार्ड तैनात हैं उनमें से कई बीमार हैं तो किसी को कम दिखता है. वहीं मिल के बकाए की भुगतान और मिल के चालू होने के आस में कई कामगार और किसान बीमार हो रुपये के अभाव में असमय काल के गाल में समा गए. वहीं जो बच गए वो रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में चले गये. जो रह गए वे मिल के चालू होने की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं. मिल के शुरू नहीं होने से क्षेत्र के लोगों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है. इसका खामियाजा का भुगतान सत्ताधारी दलों से लेकर हर किसी दल के नेताओं को इस चुनाव में स्थानीय जनता का विरोध सहना पड़ सकता है.

गन्ना किसान भवानन्द झा ने कहा कि अपने खेत में सिर्फ गन्ना की खेती करते थे. इसी खेती से बच्चे की शादी-विवाह और पढ़ाई का खर्चा निकालते थे, लेकिन मिल बन्द हो जाने के बाद स्थिति जर्जर हो गयी. वहीं मिल पर लाखों रुपये का बकाया है जो अभी तक नहीं मिला है. मिल में फिटर के पद पर कार्यरत राजकुमार यादव ने कहा कि 1996 से लेकर आज तक चीनी मिल के शुरू होने के इंतजार में हूं. आर्थिक तंगी की वजह से इनकी बेटियों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पायी और अब तक चारों बेटियां कुंवारी है.

'मधुबनी क्षेत्र के निवर्तमान विधायक रामदेव महतो ने लोहट चीनी मिल के नहीं खुलने की सारी जिम्मेदारी निवर्तमान सरकार को ठहरायी है. श्री महतो ने कहा कि इस चीनी मिल को खोलने के लिए एनडीए सरकार ने एक नीति बनायी थी. जिसके तहत बन्द पड़ी मिल को खोलना था. लीज पॉलिसी के तहत यह काम करना था. लोहट चीनी मिल डालमिया समूह को दिया गया था लेकिन वर्तमान भ्रष्ट सरकार के कारण ऐसा नहीं हो पाया. डालमिया को अज्ञात लोगों द्वारा धमकियां मिलनी शुरू हो गयी और इन्हें सुरक्षा कारणों से इसे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा. इसके बाद जो दूसरे बीटर आये वो लीज की न्यूनतम राशि को जमा करा पाने में असमर्थ थे जिसके कारण लोहट चीनी मिल को लीज पर लेने का जो कार्य था वो अधूरा ही रह गया. इसमें राज्य सरकार की बड़ी नाकामी थी. मधुबनी के निवर्तमान विधायक रामदेव महतो इस बार अपने चुनावी घोषणा-पत्र में इसे प्रमुखता दे रहे हैं.'

बिहार की जनता को उम्मीद थी कि सरकार परिवर्तन के बाद उद्योग की स्थापना की जायेगी. निवर्तमान सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि नये उद्योग की स्थापना एवं बन्द उद्योग को खोला जायेगा लेकिन यहां की जनता लोहट चीनी मिल के नहीं खुलने से अपने-आपको ठगा महसूस कर रही है क्योंकि इन्हें इम्मीद थी कि विकास पुरूष कहे जाने वाले अवश्य रूप से इद्योग की काया पलट करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इम्मीद है कि इस चुनाव में लोहट चीनी मिल स्थानीय एवं ज्वलंत मुद्दा रहेगा.■

feedback@chauthiduniya.com

पूर्णिया

दिलजलों ने बिगाड़ा सबका गणित

नीरज सिंह feedback@chauthiduniya.com

पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल सात सीटे हैं. यहां पर मतदान सबसे अंतिम चरण में 5 नवंबर को होगा. लेकिन सभी सीटों पर दलीय प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद महागठबंधन और एनडीए के घटक दलों के टिकट के दावेदार प्रत्याशियों ने अपने ही दल के उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है. साथ ही कई आरोप लगाकर बागी उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूद गए हैं. जिससे चुनावी मुकाबला संघर्षपूर्ण और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

मालूम हो कि पूर्णिया जिले में सदर पूर्णिया कस्बा, धमदाहा, रूपौली, बनमन्खी, बायसी और अमौर समेत विधानसभा की सात सीटें हैं. विगत 2010 के विधानसभा चुनाव मे पूर्णिया बायसी अमौर और बनमन्खी पर भाजपा ने कब्जा जमाया था. धमदाहा रूपौली पर जदयू ने और कस्बा पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया जबकि राजद का खाता तक नहीं खुला लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में दलों और बागियों की बहुलता के कारण चुनाव संघर्षपूर्ण और रोमांचक होता दिख रहा है. 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्णिया में भाजपा के दिवंगत विधायक राजकिशोर केसरी ने कांग्रेस के रामचरित्र यादव को लगभग 19 हजार मतों के अंतर से हराया था. पुन: राजकिशोर केसरी के निधन से होनेवाले उपचुनाव में राजकिशोर केसरी की पत्नी ने रामचरित्र यादव को हराया. लेकिन इसबार भाजपा ने अपने सीटिंग विधायक किरण केसरी का टिकट काटकर भाजपा जिला उद्योग मंच के अध्यक्ष विजय खेमका पर दांव खेला है, जिसको लेकर अंगद मंडल, तारा साह, पवन भगत जैसे टिकट के कई दावेदारों ने विरोध को लेकर मोर्चा खोल दिया है और पार्टी में गुटबाजी चरम पर है वहीं कुछ कार्यकर्ता भितरघात में लग गये हैं हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार किरण केसरी को विधान परिषद में भेजने का आश्वासन देकर मना लिया गया है. दूसरी तरफ कांग्रेस ने पिछली बार के उम्मीदवार रामचरित्र यादव का टिकट काटकर इंदू सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जिससे रामचरित्र यादव, कर्नल अक्षयवट यादव, भोला साह जैसे कांग्रेसी दावेदार निर्दलीय या अन्य किसी दूसरे दल से चुनावी समर में कूद रहे हैं. महागठबंधन में जदयू की तरफ से जितेन्द्र यादव, दिवाकर चौधरी और पूर्णिया सासंद संतोष कुशवाहा ने अपने भाई शंकर कुशवाहा के लिए दावा ठोंक रखा था लेकिन सीट कांग्रेस की झोली में चले जाने से जदयू सासंद संतोष कुशवाहा नाराज हो गये हैं. यहां से जितेन्द्र यादव जदयू टिकट के प्रबल दावेदार थे, टिकट नहीं मिलने से वे भी महागठबंधन से नाराज हो चुके हैं. असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन ने छह उम्मीदवारों की घोषणा की है.

दिलीप यादव

ज्योति रानी

निरंजन कुशवाहा

धमदाहा सीट से जदयू ने मंत्री लेसी सिंह को पुन: मैदान में उतारा है जिसके खिलाफ रालोसपा ने शिवशंकर ठाकुर को टिकट दिया है. धमदाहा सीट पर भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक दिलीप यादव और भाजपा जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योति रानी टिकट के प्रबल दावेदार थे. महागठबंधन बनते देख राजद के पूर्व विधायक दिलीप यादव भाजपा में शामिल हुए थे. धमदाहा में पूर्व में मुकाबला लेसी सिंह और दिलीप यादव के बीच ही होता रहा है. टिकट नहीं मिलने से नाराज दिलीप यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं. विधानसभा के नये परिसीमन में धमदाहा में कुशवाहा मतदाताओं की संख्या में काफी इज़ाफा हुआ था जिससे रालोसपा की तरफ से निरंजन कुशवाहा टिकट के प्रबल दावेदार थे. रालोसपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी के कर्मठ नेता निरंजन कुशवाहा को टिकट न देकर एक साठ-गांठ के तहत लेसी सिंह के खिलाफ बेहद कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिया है. निरंजन कुशवाहा भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं. धमदाहा विधानसभा से भाजपा को सीट नहीं मिलने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देने का भी सिलसिला चालू है. रूपौली में जदयू ने पुन: मंत्री बीमा भारती पर दाव खेला है जिसके खिलाफ भाजपा ने परमानंद मंडल को मैदान में उतारा है. टिकट नहीं मिलने से नाराज लोजपा के पूर्व विधायक और पूर्णिया जिला परिषद अध्यक्ष के पति शंकर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे भाजपा प्रत्याशी की परेशानी बढ़ने वाली है और मुकाबला रोचक और संघर्षपूर्ण हो गया है. बनमन्खी विधान सभा से भाजपा ने पुन: कृष्णा कुमार ऋषिदेव को मैदान में उतारा है. बनमन्खी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यहां के नाराज मतदाता आखिर में विधायक कृष्ण कुमार को वोट करेंगे. बनमन्खी विधानसभा में भूंइया मतदाताओं की संख्या काफी है जिससे यहां हवा एनडीए के पक्ष में है. कस्बा विधानसभा से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक अफाक आलम को एक बार फिर मौका दिया है वहीं एनडीए की तरफ से पूर्व भाजपा विधायक प्रदीप दास भाजपा के टिकट पर मैदान में है. बायसी विधानसभा से महागठबंधन की तरफ से वर्तमान राजद विधायक हाजी अब्दुस सुहान को एक बार फिर मौका दिया गया है, जबकि एनडीए गठबंधन में यह सीट रालोसपा को मिली है. रालोसपा ने यहां से अत्यंत नये चेहरे अजीजुर रहमान को मैदान में उतारा है जिसे बायसी की जनता कमजोर प्रत्याशी मान बैठे हैं. बायसी भाजपा कोटे की सीट थी जहां से 2010 में सतोष कुशवाहा भाजपा के टिकट पर विधायक बने अब जदयू से पूर्णिया के सांसद हैं. बायसी से पूर्व विधायक रुकमुद्दीन, मो. शमीम, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके निसार अहमद, विनोद यादव, भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन एकाएक बायसी सीट रालोसपा के खाते में चले जाने से सभी हतप्रभ हैं. रुकमुद्दीन जहां सपा की साइकिल पर सवार हो चुके हैं वहीं अन्य दूसरे दलों से भाग्य आजमाने में लगे हैं. इसराईल आजाद यहां से पप्पू यादव की जनअधिकार पार्टी के उम्मीदवार हैं.

70 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या वाली इस सीट पर गुलाम सरवर ओवैसी के उम्मीदवार है. अमौर में भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक सबा जफर को एकबार फीर मौका दिया है. वहीं कांग्रेस से जलील मस्तान मैदान में है. भाजपा के तरफ से कई टिकट के दावेदार थे. टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी इम्मीदवार सपा, एनसीपी, बसपा, ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार बन गए. ■

एक नज़र

चुनावी हलचल

दरभंगा में लोजपा की लोकप्रियता दांव पर

दरभंगा में लोजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है. चुनाव के दौरान लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान की सभाओं में आपार भीड़-उमड़ रही थी. लिहाजा चुनाव में लोजपा की दमदार उपस्थिति का अनुमान चुनाव विश्लेषकों द्वारा लगाया जा रहा है. लोजपा को दरभंगा क्षेत्र में तीन सीट मिली है. गौड़ाबौराम से विनोद सहनी, हायाघाट से रमेश चौधरी और कुशेश्वर स्थान से धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को लोजपा का प्रत्याशी बनाया गया है. धनंजय कुमार रामविलास के दामाद भी हैं. दूसरी तरफ गौड़ाबरौराम से भाजपा के विनोद मिश्र को टिकट मिलना तय माना जा रहा था लेकिन किसी कारणवश यह लोजपा के खाते में चली गयी और अंतरकलह है और एक जाति वर्ग विशेष भाजपा (एनडीए) से नाराज है. सुशील मोदी की खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई. इधर सांसद किर्ती झा आजाद तीन बार चुने गये लेकिन एक बार भी मंत्री पद नहीं मिला लेकिन झा का कहना है कि मिथिलांचल की जनता एनडीए को जीत दिलायेगी. रामविलास की भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पायेगी? वहीं ब्राह्मण वर्ग एनडीए से नाराज चल रहा है. **- राजेश**

अब सर्जरी खगड़िया में भी उपलब्ध

अब खगड़िया के मरीजों को जेनरल एण्ड लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए बेगूसराय व पटना जाने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे मरीजों को खगड़िया में ही सर्जरी कराने की सुविधा उपलब्ध हो गई है. शहर के अस्पताल रोड स्थित साधना नर्सिंग होम में जेनरल एण्ड लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए मशीन लगाई गई है. जिसका उद्घाटन नर्सिंग होम के संचालक डॉ. एच प्रसाद, अनिल जायसवाल एवं सदाशिव जायसवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया. अब उक्त क्लीनिक पर कई प्रकार की सुविधा मिलेगी. जहां डॉ रजनी रंजन द्वारा इलाज किया जायेगा. इधर एच प्रसाद ने बताया कि एपेंडिक्स, हॉर्निया गोल, बच्चेदानी आदि के ऑपरेशन में सिर्फ एक छोटा सा छेद करना होगा. उन्होंने कहा कि अब ऐसे मरीजों को खगड़िया से बाहर ऑपरेशन के लिए नही जाना होगा. इस मौके पर डॉ पवन कुमार, डॉ. प्रेम कुमार, डॉ जगतरंजन सहित कई बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोग मौजूद थे. **- गीता कुमार**

दादरी और बीफ पर पीएम कन्यूजः अशफाक

दादरी कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस कांड को लेकर सभी दल के नताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. वहीं जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के संयोजक अशफाक रहमाने ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा कि आरएसएस द्वारा जिस प्रकार से अफवाहें फैलाकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है वह भारत जैसे गंगा जमुनी संस्कृति वाले देश के लिए घातक है. उन्होंने कहा कि आरएसएस यदि खुद न्याय करने लगेगी समाज में अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो जायेगा. डॉ. रहमान ने बताया कि भाजपा के सांसद बेकार की बयानबाजी कर माहौल बिगाड़ रहे हैं. उनसे आग्रह है कि सम्भल कर बयानबाजी करें. आगे उन्होंने कहा कि सांप, चूहे, भी तो हिन्दू आस्था से जुड़े हुए हैं फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं क्या कहते हैं. उन्होंने कहा यदि धार्मिक आस्था के नाम पर सरकार यदि बीफ पर बैन लगाती है तो सराहनीय कदम होगा, हम इसका स्वागत करते हैं तथा दादरी पर प्रधानमंत्री के साफ-सुथरे बयान के साथ इचित कार्रवाई की मांग करते हैं. **- चौथी दुनिया ब्यूरो**

प्रत्याशियों ने किया जीत का दावा

चुनाव सम्पन्न होने के बाद प्रत्याशियों ने जीत का दावा अपने-अपने तरीके से किया है. खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी एवं निवर्तमान विधायक पूनम देवी यादव ने जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि हमने जो विकास का कार्य किया है, उसके कारण लोगों ने हमें प्यार व सम्मान के साथ मतदान किया है. वहीं हम प्रत्याशी राजेश कुमार, बहुजन मुक्ति पार्टी के मनोज कुमार एवं जनअधिकार पार्टी के मनोहर कुमार यादव ने भी जीत का दावा किया है. इन नेताओं का कहना है कि पिछले दस साल से हमने जो मान-सम्मान दिया व दुख-सुख में साथ रहे उसके कारण लोगों ने हमें अधिक मतदान किया है. वहीं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से महागठंधन के प्रत्याशी रामानंद सिंह आरएन सिंह, भाजपा प्रत्याशी रामानुज चौधरी,जनअधिकार पार्टी के डॉ. सुलेही मेहता आदि ने जीत का दावा किया है. जबकि अलौली विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रदेश अध्यक्ष सह प्रत्याशी पशुपति कुमार पारस तथा महागठबंधन उम्मीदवार चन्दन राम ने जीत का दावा किया है. वहीं बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी मिथलेश कुमार निषाद एवं निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार पांडव ने भी जीत का दावा किया है. श्री पांडव यादव ने किया कि इसबार बेलदौर विधानसभा के लोगों ने हमें दलगत भावना से ऊपर उठकर वोट दिया है. उन्होंने कहा कि वहां के स्थानीय विधायक से बहुत सारे लोग दुखी हैं जबकि निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश विद्यार्थी ने भी जीत का दावा किया है.■

- गीता कुमार

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से
प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आयुर्वेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची
उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम...
जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए...
आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।
REPL प्लाजा
Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

रास न आई दोस्ती, बिखरा तीसरा मोर्चा

अपने को तीसरा मोर्चा से अलग करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कहने वाले तारिक अनवर ने कहा कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भाजपा के पक्ष में लहर चलने की बात कह कर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चुनाव में भाजपा का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि एनसीपी किसी भी सूरत में भाजपा का समर्थन करने वाली पार्टी के साथ नहीं रह सकती है. अनवर ने पप्पू यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकलाप से यह लगता है कि उनकी भी एनडीए के साथ सांठगांठ है.

दिवाकर

राजनीति में न कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन, सभी सही मौके की तलाश में होते हैं जब जैसा अवसर मिला वैसा ही कार्य करते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में एनडीए और महागठबंधन को सत्ता की कुर्सी से रोकने के लिए सपा, एसीपी, जन अधिकार पार्टी और कई पार्टीयों ने मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन किया, जिसका नाम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा रखा गया, लेकिन चुनाव के पहले चरण के बाद ही तीसरा मोर्चा गठबंधन धराशायी हो गया अब इसे अवसर वादी कहेंगे या कुछ और जिस प्रकार इन पार्टीयों ने तीसरा मोर्चा का गठन किया और

> नंदा ने कहा कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को धर्म निरपेक्षता का प्रमाण पत्र किसी से लेने की जरूरत नहीं है. यह देश की जनता जानती है कि मुलायम सिंह यादव ने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है और हमारी लड़ाई भाजपा से है.उन्होंनें कहा कि नीतीश और लालू की वजह से बिहार मे भाजपा ने इतनी मजबूती बनाई है. तारिक अनवर खुद ही चलकर उनके पास आए थे उन्हें न्योता नहीं दिया गया था.

चुनाव के शुरूआती पल में उनका विखंडन हो गया. इसका मतलब क्या निकाला जाये? ज्ञात हो कि तीसरा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के रूप में तारिक अनवर के नाम का ही एलान हुआ था. अपने को तीसरा मोर्चा से अलग करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कहने वाले तारीक अनवर ने कहा कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने भाजपा के पक्ष में लहर चलने की बात कह कर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चुनाव में भाजपा का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि एनसीपी किसी भी सूरत में भाजपा का समर्थन करने वाली पार्टी के साथ नहीं रह सकती है. अनवर ने पप्पू यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकलाप से यह लगता है कि उनकी भी एनडीए के साथ सांठगांठ है.

गौरतलब है कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कैमुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार में भाजपा सरकार बना रही है बिहार में माहौल भाजपा के पक्ष में है. उन्होंने भाजपा के अच्छे कामों कि तारीफ भी की एवं कहा कि भाजपा अच्छा काम कर रही है. मुलायम सिंह यादव के इस बयान से राजनीति गरमा गई थी वह भी यह बयान उस समय आया जब बिहार में प्रथम चरण का मतदान हो रहा था. गौरतलब है कि बिहार चुनाव के लिए सपा,एनसीपी,जन अधिकार पार्टी,नेशनल पीपुल्स पार्टी, समरस समाज पार्टी और नूर मोहम्मद की पार्टी ने मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान 19 सितम्बर को किया था. जिसमें सपा 85, जन अधिकार पार्टी 64, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 40, समरस समाज पार्टी 28, नेशनल पीपुल्स पार्टी 03 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हुआ था.

काफी जोर शोर से बिहार में तीसरा मोर्चा का गठन हुआ था नेताओं में आक्रमकता दिखी थी सब उर्जा से भरपूर लबरेज और अपनी पार्टी के जीत को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ही इस गठबंधन में दरार आ गई और तीसरा मोर्चा की हवा चुनाव के मध्य में ही फूस हो गई. वैसे देखा जाये तो बिहार में इससे पहले भी कई गठबंधन हुए लेकिन वो मंजील पर पहुंचने से पहले ही धराशायी हो गए, जिसका सबसे ताजा उदाहरण महागठबंधन का है जो चुनाव घोषणा से पूर्व पांच पार्टीयों से मिलकर बना था. जिसमें राजद, जदयू,कांग्रेस, एनसीपी और सपा शामिल थी लेकिन इस महागठबंधन की भी हवा निकल गई. एनसीपी और सपा ने अपने आप को इस महागठबंधन से अलग करते हुए तीसरा मोर्चा के गठन किया.

समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के नेता व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद किरणमय नंदा ने कहा कि मोर्चा मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा. एनसीपी के जाने से मोर्चा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होनें कहा कि एनसीपी नेता तारिक अनवर ने नीतीश और लालू के इशारे पर साजिश के तहत मोर्चा का साथ छोड़ा है. वह पहले भी लालू-नीतीश के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ थे. नंदा ने कहा कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव को धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र किसी से लेने की जरूरत नहीं है. यह देश की जनता जानती है कि मुलायम सिंह यादव ने कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की है और हमारी लड़ाई भाजपा से है. उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू की वजह से बिहार मे भाजपा ने उतनी मजबूती बनाई है. तारिक अनवर खुद ही चलकर उनके पास आए थे उन्हें न्योता नहीं दिया गया था.

वहीं दूसरी तरफ जन अधिकार पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह कुषवाहा ने तारिक अनवर पर धोखेबाजी का आरोप लगाया. उन्होने कहा कि तारिक अनवर का कोई जनाधार नहीं उनके अलग होने से मोर्चे के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. समाजवादी धर्म नरपेक्ष मोर्चा मजबूत है.

बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा के साथ ही कई मोर्चा बना और कई मोर्चा बनते बनते टूट गया. जिसमें महागठबंधन में फुट और तीसरा मोर्चा में हुई विखंडन मुख्य है. तीसरा मोर्चा में सबसे बड़ी पार्टी सपा ही है जो सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और इसके मुखिया के इस तरह बयान के कारण तीसरा मोर्चा का विखंडन हो गया. तीसरा मोर्चा के गठन का राह कभी भी आसान नहीं रही है चाहे केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य की स्तर पर हमेशा तीसरा मोर्चा बनते बनते ही धराशायी हो जाता है. देखना है कि कब तीसरा मोर्चा मजबूत तरीके से अपने को भारतीय राजनीति में स्थापित कर पाता है और कब तीसरा मोर्चा का अपना वाजूद मजबूत करपाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सहरसा विधानसभा

जन अधिकार की मेहरबानी राजद के लिए परेशानी

संजयसोनी

महागठबंधन व राजग गठबंधन के बीच घमासान लड़ाई से इंकार नहीं किया जा सकता है. यहां दोनों दल के उम्मीदवार पहले भी एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं. कोई हार कर सबक के साथ अपनी रणनीति अपना रहे हैं तो कोई जीत के जश्न की रणनीति को अपना रहे हैं. लेकिन राजग के भाजपा उम्मीदवार के लिए लड़ाई आसान इसलिए है कि राजद में कोई नया चेहरा नहीं दिया गया है. कांग्रेस के खाते में यह सीट चली जाती तो भाजपा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती. सहरसा में राजद से अरूण कुमार यादव तो भाजपा से आलोक रंजन मैदान में हैं. लेकिन इस सीट पर महागठबंधन को पराजित करने के लिए ही जन अधिकार पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर संजना तांती को उम्मीदवार बनाया है.

आलोक रंजन

अरुण कुमार यादव

कोशी प्रमंडल में भाजपा के खाता खोलने का श्रेय पूर्व विधायक संजीव कुमार झा को ही जाता है. यही वजह है कि कोशी क्षेत्र में भाजपा की चर्चा उनके बगैर करना उचित नहीं होगा. प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा विधानसभा सीट से ही भाजपा ने वर्ष 2005 के फरवरी में संजीव कुमार झा को बिहार सरकार के वित्तमंत्री शंकर टेकरीवाल के विरूध मैदान में उतारकर खाता खेलने का काम किया था. झा 2005 के अक्टूबर में भी महिषी के पूर्व विधायक अब्दुल गफुर को पराजित कर विधानसभा पहुंचे. उस वक्त से सहरसा सीट भाजपा के कब्जे में है और 2010 के चुनाव में भाजपा ने उम्मीदवार बदलकर भाजपा से आलोक रंजन को टिकट दिया और निवर्तमान विधायक रंजन की टक्कर 2010 में भी राजद के अरूण यादव से ही हो चुकी है. इस बार भी राजद के अरूण कुमार यादव व भाजपा के निवर्तमान विधायक आलोक रंजन के बीच ही मुख्य मुकाबला होना तय है. वर्ष 2010 के चुनाव में स्वतंत्र व कांग्रेस उम्मीदवार को प्राप्त मतों के गणित को ही भाजपा व राजद जीत का अपना समीकरण मान रहे हैं. जबकि इस बार के वोटों का समीकरण सीधे आर-पार की है. कोई लाग लपेट नहीं है. आलोक रंजन को अन्य जातियों से ज्यादा अपने ही जाति के बीच संघर्ष करने की जरूरत है. वैश्य समाज सहित अन्य पचपनिया का रूझान भी भाजपा के पक्ष में दिख रहा है तो लालू का माय समीकरण के साथ पचपनिया का बड़ा तबका महागठबंधन के साथ होनें की उम्मीद दिख रही है. भाजपा प्रत्याशी से लोगों को कुछ खास अपेक्षाएं मसलन बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज और जल निकासी के लिए लंबित ड्रेनेज योजना परेशानी का सबब बन सकता है. पार्टी के असंतुष्ट खेमा से थोड़ी परेशानी उत्पन्न हुई, जिसे अपने काबिलियत से सुलह भी कर लिया है. लेकिन अगर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व मधेपुरा के सांसद सक्रिय रहे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है. जन अधिकार पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने लायक बहुमत नहीं मिली तो वह भी हास्यापद होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

मुन्ना के लिए करो या मरो के हालात

आखिरकार सोनवर्षा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के नाम की घोषणा होते ही सुपौल की राजनीतिक फिजा बदल गयी. वैसे राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि मैराथन के इस घोड़े को पार्टी ने मैदान में उतारने से पहले टिकट के लिए इतना दौड़ा दिया कि उनके तो नहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह में कुछ थकान जरूर आयी है. फिर भी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना को पहाड़ से टकराने की आदत रही है और सफलता भी मिली है.

विजेंद्र प्रसाद यादव

कुशोर कुमार मुन्ना

संजय सोनी

राजग गठबंधन का नेतृत्व घटक भाजपा ने काफी सोच-समझकर सुपौल जिले के सुपौल विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है. इस विधानसभा सीट से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केन्द्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को भी पार्टी लड़ाने का मूड बना रही थी. तो बिहार के जाने माने संवेदक व भाजपा नेता कार्तिक प्रसाद सिंह की संभावित उम्मीदवारी के दावेदारी की वजह से भी उम्मीदवार घोषित करने में भाजपा को विलंब हुई. आखिरकार सोनवर्षा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के नाम की घोषणा होते ही सुपौल की राजनीतिक फिंजा बदल गयी. वैसे राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि मैराथन के इस घोड़े को पार्टी ने मैदान में उतारने से पहले टिकट के लिए इतना दौड़ा दिया कि उनका तो नहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह में कुछ थकान जरूर आयी है. फिर भी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना को पहाड़ से टकराने की आदत रही है और सफलता भी मिली है.

सुपौल विधानसभा सीट पर लगातार जदयू के निवर्तमान विधायक सह राज्य के वरीय काबिना मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव का कब्जा रहा है और उनके मुकाबले में भाजपा से पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना मैदान में टक्कर देने पहुंचे हैं. पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के मिजाज की यह तासीर रही है उनका टक्कर काबिना मंत्री से ही होता रहा है. सुरक्षित सीट होने से पहले सोनवर्षाराज विधानसभा का वर्ष 1990,1995, 2000 से 2005 तक लगातार प्रतिनिधित्व बिहार के कद्दावर तत्कालीन काबिना मंत्री अशोक कुमार सिंह को वर्ष 2005 के फरवरी माह में हुए चुनाव में पटखनी देकर पहली बार विधायक बने. इसके बाद राजद ने ही खुद 2005 के अक्टूबर माह में हुई विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बदल दिया. फिर मुन्ना ने जीत हासिल कर बिहार विधानसभा पहुंचे और इसके बाद यह सीट आरक्षित हो गयी. इसके बाद से ही मुन्ना का कोई स्थाई क्षेत्र नहीं रह सका और वह अपना स्थाई क्षेत्र बनाने की जुगत में ही सुपौल की जनता का दामन थामा. सहरसा से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी उनको जनता का पूरा सहयोग मिला. लेकिन सुपौल में भाजपा संगठन का रिश्ता नीतीश के मुख्यमंत्री व सुशील कुमार मोदी के मुख्यमंत्री काल तक काबिना मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव के साथ कुछ ज्यादा ही मधुर रहा है.

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि मंत्री यादव से भाजपा के पुराने रिश्ते की मिठास का लाभ महागठबंधन के उम्मीदवार को अंदर ही अंदर मिल सकता है. इसलिए भाजपा के आलाकमान को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाने व सहलाने की जरूरत है. हालांकि पूर्व विधायक मुन्ना चुनाव जीतने के माहिर रणनीतिकार माने जातें हैं. लेकिन आमजन कहते हैं कि यहां एक ओर जहां भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है तो दूसरी तरफ यह क्षत्रिय छत्रपों की अग्नि परीक्षा भी कही जा रही है. खैर, इस सीट का मुकाबला न केवल रोचक होगा बल्कि खास जाति का ईमानदारी से सहयोग मिला तो परिणाम सभी को चौंका जरूर देगा. सूत्रों का कहना है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष नागेन्द्र नारायण ठाकुर पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जिला अध्यक्ष की नाराजगी पार्टी टीम को कहीं रास्ते से न भटका दे.

इसलिए मुन्ना को महागठबंधन के इस कद्दावर उम्मीदवार को पटखनी देने के लिए पार्टी आलाकमान को कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत कड़ी की व्यवस्था करनी पड़ सकती है. हालांकि जदयू उम्मीदवार यादव को लोग कुसहा त्रासदी के दंश झेलने के बाद भी भारी मतों से राजद के उम्मीदवार रविन्द्र कुमार रमण से 15 हजार 400 वोट के अंतर से जीत दर्ज करा चुके हैं. इस वक्त ये जल संसाधन मंत्री थे और वर्ष 1990,1995, 2000, 2005 व 2010 तक लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

02 नवंबर-08 नवंबर, 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड

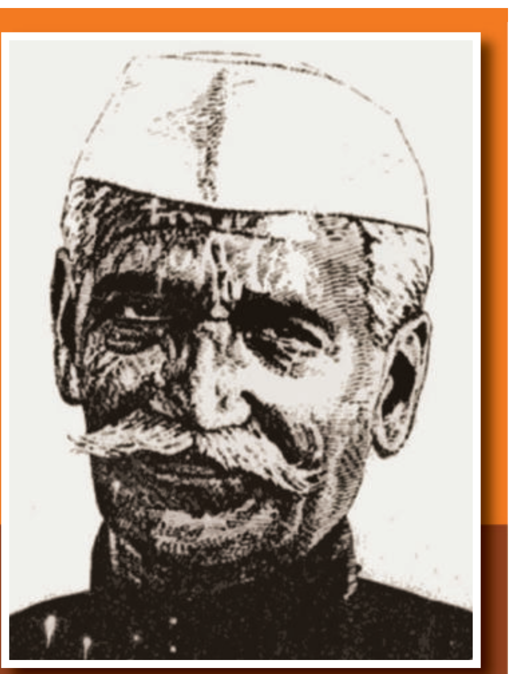

समाजवाद के पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव की कोठी भू-माफियाओं के कब्जे में

समाजवादी सिद्धांतों की कब्र पर होटल

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत में समाजवाद के कर्णधार आचार्य नरेंद्र देव की ऐतिहासिक कोठी, जो एक जमाने में कांग्रेसी नीतियों की मुखालफत का मुख्य केंद्र हुआ करती थी, आज अपना स्वरूप खोकर कोहिनूर पैलेस (होटल) में तब्दील हो चुकी है. कोठी के उत्तराधिकारियों से क्रय करके इस तवारीखी कोठी को होटल में गुपचुप तरीके से तब्दील कर दिया गया, जिसको लेकर समाजवादी आन्दोलन से जुड़े लोकतंत्र रक्षा सेनानियों ने जब प्रबल विरोध करना शुरू किया, तो हुक्मरानों की नींद टूटी लेकिन अभी भी मुकामी हुक्मरान इस कोठी को मूल रूप की वापसी के लिए कोई ठोस कवायद शुरू नहीं कर रहे हैं. इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं.

आचार्य नरेंद्र देव कोठी को लेकर की गई खरीद फरोख्त में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं, पूंजीपतियों और नौकरशाहों की दुरभिसंधि एक बार फिर उजागर हुई है. अवध की पहली राजधानी फैजाबाद के गुलाबबाड़ी के ठीक पीछे स्थित तवारीखी महत्वूर्ण आचार्य नरेंद्र देव कोठी को कायदे कानून ताख पर रखकर होटल में तब्दील करने की प्रशासन ने मूक अनुमति दे ही नहीं दी, बल्कि होटल निर्माण में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों ने खुली छूट भी दे दी. नतीजतन कोठी के मूल स्वरूप को बिना छेड़छाड़ किए खिड़कियां, दरवाजे, फर्स, बाउंड्रीवाल सहित तमाम चीजों को ताज होटल की तर्ज पर नया आकर्षक रूप दे डाला गया. कोठी के पार्श्व में अत्याधुनिक ढंग से रेस्टोरेंट का निर्माण कराया गया है. जब शिकायतें समाजवादी सरकार के दरबार तक पहुंची और वहां से रोकथाम का हुक्मनामा जारी हुआ, तो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तर्ज पर मूल कोठी के निर्माण को रोकने के बजाय विकास प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया. लेकिन यह ताला भी बेनामी साबित हुआ और होटल मालिकों द्वारा आन्तरिक भाग के निर्माण कार्य में तेजी कर दी गई. नतीजतन रेस्टोरेंट भी बनकर तैयार हो गया, अब केवल उद्घाटन का इंतजार है. चूंकि मूल कोठी पर किसी तरह की कोई प्रशासन ने विधिक कार्रवाई नहीं की है, इसलिए ऐसा लगने लगा है कि आचार्य नरेंद्र देव की कोठी बहुत ही जल्द कोहिनूर पैलेस के नाम से जानी और पहचानी जाने लगेगी.

दूसरी ओर पुरातत्व विभाग का कहना है कि पुरातत्व संरक्षित ऐतिहासिक इमारतों की 200 मीटर की परिधि में किसी तरह का कोई नया निर्माण नहीं कराया जा सकता, लेकिन निर्माणकर्ताओं द्वारा इन नियमों की भी पूरी तरह अवहेलना की गई है. पुरातत्व विभाग के स्थानीय अधिकारी ने भी अभी तक निर्माण व रूप परिवर्तन को लेकर किसी तरह की कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की है. पुरातत्व विभाग के रवैये से साफ जाहिर होता है कि वह भी इस दुरभिसंधि का एक अंग बन चुका है.

सात करोड़ रुपये में बिकी आचार्य नरेंद्र देव की कोठी के सौदे में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी कर 50 लाख की कीमत का स्टाम्प अदा किया गया है. अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की साठगांठ में सालों से दिन रात तोड़-फोड़ और निर्माण कार्य चलता रहा. कोठी से आचार्य नरेंद्र के पुस्तकालय की हजारों किताबें लापता हो गईं. यह कोठी पुरातात्विक इमारत गुलाबबाड़ी से सटी है, इसलिए कानूनन इसके 200 मीटर के दायरे में न तो कोई निर्माण हो सकता है और न ही पुनर्निर्माण कराया जा सकता है. इसी नियम के तहत पुरातत्व विभाग के अधिकारी डीके जायसवाल ने निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ 5 फरवरी और 5 सितम्बर 2015 को नामजद तहरीर दी थी. लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की. पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने प्रदेश शासन और जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा, लेकिन उसपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि तोड़फोड़ बदस्तूर जारी रहा. वहीं होटल का नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसपर प्राधिकरण ने नक्शा तो निरस्त कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रोका जा सका. प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि कोठी को सील करने हम लोग गए थे, लेकिन व्यापारियों और उनके नेताओं की नोकझोंक ने पहली बार सील नहीं करने दिया. पुरातत्व विभाग के लोगों का कहना है कि गुलाबबाड़ी की जमीन पर 100 गुणा 25 फुट के प्लॉट पर रेस्टोरेंट बनवाने के लिए दीवार बनाई गई. पुरातत्व विभाग ने तहसील सदर के रास्व अधिकारियों से पुराना नक्शा और कागजात की मांग की है.

इस मामले में समाजवाद का नारा लगाने वाले फैजाबाद के जनप्रतिनिधि चुप हैं. नगर के विधायक तेजनारायण पांडेय पवन इस मामले में कुछ भी बोलना नही चाहते हैं. वहीं लोकतंत्र सेनानी परिषद ने इस मामले को उठाया है. इस संगठन के जिलाध्यक्ष माता प्रसाद तिवारी ने अपने साथियों समेत जिलाधिकारी से आचार्य नरेंद्र देव की कोठी को स्मारक बनाने की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से भी शिकायत की है. फैजाबाद में आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर आचार्य नरेंद्र देव नगर मोहल्ला, रेलवे स्टेशन और कृषि विश्वविद्यालय है. आचार्य के शिष्य रहे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने आचार्य जी के छोटे बेटे अशोक नाथ वर्मा को राज्य सभा सदस्य नामित करवाया था. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉ. निर्मल खत्री को भी परिवार का भरपूर राजनीतिक लाभ मिला. लेकिन कोठी बिकने पर वह भी चुप हैं. समाजवादी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने भी सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को पत्र लिखकर कहा है कि डॉ. लोहिया की जन्मस्थली, तो आप बचा नहीं पाए कम से कम आचार्य जी की कोठी तो बचा लीजिए. कोठी को स्मारक घोषित कर समाजवाद की विचारधारा को जिंदा रख लीजिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोकतंत्र रक्षा सेनानियों ने छेड़ी मुहिम

समाजवादी सिद्धांतों को पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव की कोठी के रूप परिवर्तन को लेकर मामला सुर्खियों में तब आया जब लोकतंत्र रक्षा सेनानी ने भू माफियाओं के खिलाफ खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर दिया. लोकतंत्र रक्षा सेनानी रमेश शर्मा ने जिले के हाकिमों के अलावां सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बाबत सीधे संवाद कायम किया, तो मामला सुर्खियों में आ गया. मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाने के बाद प्रशासन को भी लगने लगा कि यदि उसने बचाव की कवायद शुरू नहीं कि तो वे भी खरीद फरोख्त में मदद करने के दायरे में आ जाएंगे. लोकतंत्र रक्षा सेनानी रमेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि फैजाबाद नगर स्थित प्रख्यात समाजवादी मनीषी आचार्य नरेंद्र देव की ऐतिहासिक कोठी जो पुरातात्विक महत्व की है, को बचाने तथा भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध तत्परता से कार्रवाई कराने की पहल करें अन्यथा प्रदेश सरकार और पार्टी की धूमिल हो रही छवि और गहराती जाएगी. उन्होंने अवगत कराया है कि समाजवादी विचारधारा के प्रसार और समतामूलक समाज की संरचना के प्रयास के लिए विश्व स्तर पर चर्चित हस्तियों में डॉ. राम मनोहर लोहिया व आचार्य नरेंद्र देव का ही नाम है. फैजाबाद जिला डॉ. राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि और आचार्य नरेंद्र देव की कर्मभूमि रहा है. इसी कारण फैजाबाद के नगर में स्थित मोहल्ला रीडगंज में उनकी भव्य ऐतिहासिक कोठी बनी है. समाजवादी पार्टी के प्रसोवा व संसोवा बनने से पूर्व एकजायी स्वरूप वाली समाजवादी पार्टी के रहते इस ऐतिहासिक कोठी में उस जमाने के प्रख्यात नेताओं डॉ. लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी, पं. जवाहर लाल नहेरू सहित अन्य हस्तियों का इस कोठी में आना जाना लगा रहता था. आजादी के दशकों पहले बनी यह कोठी आजादी की लड़ाई में शामिल लोगों की स्वर्णिम यादगार की गाथा समेटे है. लगभग साल भर पहले नगर के कुछ भूमाफियाओं व नवधनाढ्यों ने मिलकर पारिवारिक विवाद का लाभ उठाते हुए कोठी पर कब्जेदारों से इसका बैनामा करा लिया और यहां होटल बनाने की कोशिश शुरू कर दी. विकास प्राधिकरण में नक्शा लंबित है, पुरातत्व संरक्षण विभाग की नवनिर्माण के बाबत आपत्ति है. लेकिन सारे नियम और कानून दरकिनार कर भूमाफियाओं ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जो वर्तमान समय में भी जारी है. अवैध निर्माण के बारे में पुरातत्व विभाग ने दो बार नगर कोतवाली में तहरीर देकर संबंधित लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया पर दुखद यह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है. इसकी वजह कुछ सपाइयों की इस मामले में मिलीभगत भी है. नौबत यह है कि सपा के कुछ पदाधिकारी ही मौके पर बैठकर अवैध निर्माण कार्य करवा रहे हैं. विकास प्राधिकरण के अधिकारियों या पुलिस के पहुंचने पर प्रदेश में सरकार होने के नाते वापस कर दे रहे हैं. इसी कारण भूमाफिया और गुंडे भी खुली चुनौती देकर मनमानी कर रहे हैं और अधिकारी मूकदर्शक बने हैं. ■

विकास प्राधिकरण का थोथा बयान

आचार्य नरेंद्र देव की कोठी को होटल में तब्दील करने के मामले पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि नक्शा स्वीकृत करने का आवेदन दिया गया था, लेकिन नक्शा स्वीकृत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी निर्माण को प्राधिकरण स्वीकृति नहीं देगा. यदि निर्माण हुआ है, तो इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी.

पुरातत्व विभाग लाचार

कोठी परिसर में अवैध निर्माण व पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में संरक्षण सहायक प्रथम गुलाबबाड़ी सर्किल डीके जायसवाल का कहना है कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए हमने कई बार पत्र लिखे, नगर कोतवाली में तहरीर दी, प्राधिकरण के सचिव को भेजे पत्र में नक्शा स्वीकृत नहीं करने की संस्तुति के साथ ही अनुरोध किया कि जो निर्माण कराया गया है वह पूर्णतया अवैध है उसे ध्वस्त किया जाए, लेकिन शासन तंत्र ने कोई कार्रवाई नहीं की. ■

कोठी के कौन-कौन हैं खरीदार

आचार्य नरेंद्र देव की कोठी और उससे जुड़ी जमीनों के एक नहीं कई खरीदार हैं. माना जा रहा है कि होटल के रूप में विकसित करने के लिए कई चरणों में जमीनों की खरीद की गई.

1- लेख पत्र सख्या 8501/13
क्षेत्रफल- 567.40 वर्ग मीटर
प्रतिफल की धनराशि-7600000
मालियत -6387000
विक्रेता- हरीश कुमार वर्मा व विनय कुमार वर्मा पुत्रगण स्व. योगेन्द्र देव वर्मा
क्रेता- ज्ञान प्रकाश मोटवानी

2- लेखपत्र संख्या- 8502/13
क्षेत्रफल-567.40 वर्ग मीटर
प्रतिफल-7600000
मालियत-6387000
विक्रेता- हरीश कुमार वर्मा व नियम कुमार वर्मा
क्रेता- मुकेश पटेल

3- लेखपत्र संख्या- 8503/13
क्षेत्रफल-636.78 वर्ग मी.
प्रतिफल- 5250000
मालियत- 4003000
विक्रेता- हरीश कुमार वर्मा व विनय कुमार वर्मा
क्रेता- ज्ञान प्रकाश मोटवानी

4-लेखपत्र संख्या- 8504/13
क्षेत्रफल- 636.78 वर्ग मी.
प्रतिफल-5250000
मालियत- 3639000
विक्रेता- हरीश कुमार वर्मा व निनय कुमार वर्मा
क्रेता- विनोद कुमार पटेल

5-लेखपत्र संख्या- 2042/13
क्षेत्रफल- 306.34 वर्गमीटर
प्रतिफल-920000
मालियत-920000
विक्रेता- डॉ. रजनीश वर्मा
क्रेता- श्रीमती आरती मोटवानी

सोनभद्र में मजदूरों की 'संगठित हत्या' का राज दफन करने की कवायद

मौत का कुआं खोदने वाले ही कर रहे हैं जांच

शिवदास प्रजापति

सफेदपोश खनन माफियाओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और तथाकथित जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ ने एक बार फिर खनन मजदूरों की संगठित हत्या का राज दफन करने की कवायद शुरू कर दी है. जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने अपने मातहत डिप्टी कलेक्टर गिरजा शंकर सिंह को पिछले दिनों बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए विस्फोट की मजिस्ट्रेट जांच सौंपी है. डिप्टी कलेक्टर हादसे के लिए जिम्मेदार विभिन्न पहलुओं के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर जिलाधिकारी को सौंपेंगे. वहीं सूबे की राजधानी स्थित खनन निदेशालय के निदेशक एसके राय ने सोनभद्र के खनिजों का अवैध दोहन कराकर खनन मजदूरों के लिए मौत का कुआं (पत्थर की खदान) तैयार कराने वाले विभागीय अधिकारी आरपी सिंह को जांच के लिए भेजा है, जो यहां जिला खान अधिकारी रह चुके हैं. गौर करने वाली बात है कि आरपी सिंह के कार्यकाल के दौरान जिले में अवैध खनन और परिवहन का गोरखधंधा जमकर फलफूल रहा था. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से हादसे की जांच करेंगे.

अगर वाराणसी परिक्षेत्र के खान सुरक्षा निदेशालय के डायरेक्टर यूपी सिंह की बात करें, तो इस मामले में वह और दो कदम आगे हैं. वाराणसी परिक्षेत्र के तहत शामिल सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली क्षेत्र में खनन व्यवसाय में करीब दस हजार से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी सुरक्षा और पंजीकरण ...

उनके रिश्तेदारों और नजदीकियों की संपत्ति में हुआ इजाफा उनकी साफ-सुथरी छवि को फीका भी कर रहा है. पिछले तीन साल से जिले में हो रहे अवैध खनन, परिवहन और विस्फोट की गतिविधियों की वजह से हुई मौतों ...

मृतकों के नाम और पते

(1) सूरत लाल पुत्र जोधी लाल, निवासी गांव- घघरी, थाना-बभनी.
(2) रामायन सिंह पुत्र राम लाल, निवासी गांव घघरी, थाना-बभनी
(3) जीत सिंह पुत्र मोती लाल, निवासी गांव-घघरी, थाना बभनी.
(4) ज्वाला पुत्र सुग्रीव, निवासी गांव कोटा, थाना-चोपन.
(5) विनोद पुत्र रामधनी, निवासी गांव-खैरटिया, थाना-ओबरा.
(6) राजेश कुमार गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता, निवासी- वार्ड-चार, थाना- घोरावल

नोट : दो शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है...

... खड़ा करती है. कहीं उनकी यह कवायद उस साजिश का हिस्सा तो नहीं जो पिछले दिनों हुए हादसे से उठने वाली आवाज को दफन करने के लिए बुनी गई है. जैसा बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान वर्ष 2012 में 27 फरवरी को बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे में शासन और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई से ...

विस्फोट में आठ मरे, सात घायल

रासपहरी पहाड़ी स्थित एक खदान के मैगजीन रूम (विस्फोटक रखने का कमरा) में हुए जबरदस्त धमाके में पिछले दिनों दो बालकों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज ओबरा तापीय परियोजना अस्पताल में हो रहा है. जिलाधिकारी ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच समेत तकनीकी जांच का आदेश जारी कर दिया है. उधर, खान निदेशालय ने जिलाधिकारी से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है. विभागीय अधिकारियों समेत क्षेत्रीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में रासपहरी पहाड़ी अंतर्गत अराजी संख्या-5593क की दो एकड़ भूमि में चोपन रोड निवासी विजया कीर्ति के स्वामित्व वाली फर्म में आशीष इंटरप्राइजेज के नाम से खनन पट्टा स्वीकृत है. इसकी मियाद 4 जुलाई 2019 तक है. स्थानीय लोगों समेत जिला खान विभाग के एक खनन सर्वेक्षक की मानें, तो इस खदान का संचालन अभिषेक सिंह उर्फ काके सिंह नामक व्यक्ति करता है, जो विजया कीर्ति का बेटा है. जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी के मुताबिक खदान की सीमा की दक्षिणी तरफ करीब 25 मीटर दूर में आशीष इंटर प्राइजेज का गोदाम (मैगजीन रूम) था, जहां अमोनियम नाइट्रेट और जिलेटीन रॉड जैसे विस्फोटक रखा जाता था. इन विस्फोटकों की आपूर्त डाला स्थित सन इंटरप्राइजेज नामक फर्म करती है. पास में ही मजदूरों का अस्थाई आवास भी है. गुरुवार दोपहर दो बजे मजदूरों ने देखा कि मैगजीन रूम से धुआं निकल रहा है. तीन मजदूर विस्फोटक को निकालने के लिए गोदाम के दरवाजे का ताड़ा तोड़ने लगे. तभी विस्फोट हो गया. विस्फोट की चपेट में आने से दो बालकों समेत आठ मजदूरों की मौत हो गई. सात अन्य घायल हो गए. ओबरा तापीय परियोजना अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है. इनमें कई की हालत गंभीर है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अन्य विस्फोट होने की आशंका से वे बचाव कार्य में जुट नहीं पाए. करीब दो घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी बचाव कार्य में लगे. तब तक जिलाधिकारी समेत अन्य आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. धीरे-धीरे शवों को बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. जानकारी के मुताबकि मृतकों में बभनी थाना क्षेत्र के सगोढ़ा गांव निवासी सूरज लाल, जीत सिंह और राम नारायण का नाम शामिल है. इनके अलावा विनोद, छोटू और ज्वाला समेत एक आठ वर्षीय बालक के मरने की बात कही जा रही है. हालांकि वे कहां के हैं, इसका पता नहीं चल पाया है. घटना में झारखंड के गढ़वा के देवरा गांव निवासी छोटेलाल, देव लाल, संतोष, बद्री, बबुंदर, सोनभद्र के बभनी थाना अंतर्गत गभरी निवासी प्रताप नारायण और अमरनाथ एवं लक्ष्मनधारी बैगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उनका इलाज ओबरा तापीय परियोजना अस्पताल में हो रहा है. उधर, जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने उक्त घटना की मजिस्ट्रेट जांच और तकनीकी जांच के आदेश दे दिये हैं. विस्फोटकों से संबंधित मामले में जांच डीआईजी, मिर्जापुर करेंगे. वहीं लखनऊ से मिली जानकारी के मुताबिक खान निदेशालय ने ...

घायलों के नाम और पते

(1) अनरसा पुत्र मोतीलाल, निवासी- गांव घघरी, थाना- बभनी.
(2) प्रताप नारायण पुत्र जद्दू लाल, निवासी घघरी, थाना-बभनी.
(3) बद्री केवट पुत्र भागीरथी, निवासी गांव-देवरा, थाना-महुअरिया, जिला-सिंगरौली, राज्य-मध्य प्रदेश
(4) संतोष कुमार पुत्र खेलावन, निवासी गांव-देवरा, थाना-महुअरिया, जिला-सिंगरौली, राज्य-मध्य प्रदेश
(5) छोटेलाल पुत्र शिव दास, निवासी गांव-देवरा, थाना-महुअरिया, जिला-सिंगरौली, राज्य-मध्य प्रदेश
(6) देवलाल पुत्र बाबा गौड़, निवासी गांव-देवरा, थाना-महुअरिया, जिला-सिंगरौली, राज्य-मध्य प्रदेश

देखने को मिला था. उस दौरान मारे गए करीब एक दर्जन मजदूरों के परिजनों/आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज तक मुआवजे के रूप में एक फुटी कौड़ी नहीं मिली. न ही इसके लिए जिम्मेदार खनन माफियाओं, ...

पड़ेगी करों की मार, तो वोट कौन देगा सरकार

रेनू शर्मा

...

नवाबों के शहर लखनऊ में हैं पुलिस से आठ गुना ज्यादा रजिस्टर्ड गुंडे

टुंडे नहीं, गुंडे बोलिए जनाब!

गणेशजी वर्मा

उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में सुधार के लिए तमाम योजनाओं का ढिंढोरा पीटती रहती है, लेकिन हालात यह है कि सपा सरकार के कार्यकाल में राजधानी लखनऊ में ही गुंडों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोत्तरी हुई है. स्थिति यह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिसकर्मियों से आठ गुना ज्यादा गुंडे रहते हैं. यह आधिकारिक सच है, क्योंकि यह रिकॉर्ड स्वयं पुलिस विभाग का है. राजधानी लखनऊ गुंडों का शहर बन चुका है. राजधानी लखनऊ में पुलिस की नहीं बल्कि गुंडों की चलती है. राजधानी में जितने गुंडे है उसके आधा पुलिसकर्मी हैं. यह पुलिस खुद कह रही है. पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें, तो राजधानी में पांच हजार से अधिक रजिस्टर्ड गुंडे हैं. यह संख्या विगत तीन वर्षों की है. जबकि सुरक्षा के नाम पर लखनऊ जनपद में कुल 43 थाने हैं, जिसमें महिला थाना भी शामिल है. यदि एक थाने में तैनात थानाध्यक्ष से लेकर पुलिसकर्मियों तक की संख्या 80 है, तो लखनऊ जनपद में कुल पुलिसकर्मियों की संख्या 3,440 आती है. जिसमें 25 प्रतिशत पुलिसकर्मी थाने के काम में और 25 प्रतिशत वीआईपी ड्यूटी में लगाए जाते हैं. शेष बचे 50 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही आम ड्यूटी पर रहते हैं, जिनके बूते सरकार कहती है कि आम लोगों की सुरक्षा हो रही है. गौरतलब है कि 50 प्रतिशत में से आधे दिन में तो आधे रात में ड्यूटी करते हैं. ऐसे में सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 860 है. यदि लखनऊ जनपद की कुल जनसंख्या लगभग 45 लाख है, तो एक पुलिसकर्मी के बूते 5,233 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है. यदि रात और दिन दोनों समय ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या निकाली जाए, तो एक पुलिसकर्मी पर लगभग 2616 लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है. अगर गुंडों की आधिकारिक संख्या से मिला कर देखा जाए, तो अजीबोगरीब दृश्य सामने आता है. पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 5,651 गुंडे हैं. यानी, 796 लोगों में एक गुंडा है. ऐसे में राजधानी की सुरक्षा कैसे होगी यह एक अहम सवाल बना हुआ है.

ट्रांसगोमती गुंडों की संख्या में अव्वल

राजधानी के ट्रांसगोमती क्षेत्र में गुंडों की संख्या सबसे अधिक है. ट्रांसगोमती में वर्ष 2014 में 641 गुंडे दर्ज हुए. जबकि इसी क्षेत्र के गाजीपुर थाना इलाके में 105 गुंडे रजिस्टर्ड हुए. राजधानी के सभी थानों में गाजीपुर इस मामले में प्रथम स्थान पर है. आधिकारिक आंकड़ा बताता है कि मानकनगर थाना क्षेत्र में सबसे कम गुंडे हैं. यहां वर्ष 2014 में मात्र पांच, वर्ष 2013 में शून्य जबकि वर्ष 2012 में 11 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. मात्र तीन वर्ष के आंकड़ों पर गौर करें, तो राजधानी में लगभग पांच हजार से अधिक गुंडे मौजूद हैं. यह आंकड़ा पुलिस का ही है. लखनऊ जनपद में वर्ष 2014 में लगभग 700 गुंडों की वृद्धि हो गई. वर्ष 2014 में पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1832 लोगों को गुंडों की उपाधि से नवाज दिया. जबकि वर्ष 2013 में यह कार्रवाई 1149 लोगों पर की गई. वहीं वर्ष 2012 में 1228 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया. आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में वर्ष 2014 में 683 गुंडों की वृद्धि हो गई. जबकि वर्ष 2013 में 79 गुंडे घट गए.

धारा 110 के तहत दर्ज गुंडे

वर्ष	संख्या
2012	1228
2013	1149
2014	1832

धारा 109 के तहत दर्ज गुंडे

वर्ष	संख्या
2012	762
2013	130
2014	10

गुंडा अधिनियम के तहत दर्ज गुंडे

वर्ष	संख्या
2012	133
2013	253
2014	287

बॉक्स

राजधानी के प्रमुख थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या

थाना	निर्धारित	उपस्थिति
कैसरबाग	270	88
अमीनाबाद	72	71
नाका	100	85
गोमतीनगर	100	80
हुसैनगंज	81	49
विभूतिखंड	86	55

गुंडा एक्ट के तहत तीन वर्षों में की गई कार्रवाई

थाना	2014	2013	2012
हजरतगंज	14	2	13
हुसैनगंज	25	15	61
गौतमपल्ली	9	0	7
महिला थाना	0	0	0
कैंट	16	7	24
आशियाना	22	3	12
पीजीआई	29	28	56
आलमबाग	29	8	6
मानकनगर	5	0	11
पारा	62	30	6
कृष्णानगर	22	26	28
सरोजनीनगर	18	16	11
बंथरा	35	45	40
कैसरबाग	35	8	12
अमीनाबाद	13	7	29
नाका	34	13	15
चौक	58	24	10
वजीरगंज	50	11	16
ठाकुरगंज	75	131	67
बाजारखाला	56	57	32
सआदतगंज	53	36	41
तालकटोरा	50	42	12
महानगर	17	28	26
हसनगंज	45	40	30
विकासनगर	49	11	13
अलीगंज	40	31	10
मड़ियावं	73	40	47
जानकीपुरम	56	24	22
चिनहट	83	31	46
गोमतीनगर	35	10	21
विभूतिखंड	19	9	0
गाजीपुर	105	25	44
इंदिरानगर	39	6	8
गुड़म्बा	80	12	28
बीकेटी	46	26	122
इटौंजा	30	64	47
मोहनलालगंज	67	33	29
गोसाईगंज	51	41	38
नगराम	53	27	32
निगोहां	21	21	40
मलिहाबाद	84	59	47
माल	48	50	23
काकोरी	81	52	36

संख्या और हौसला, दोनों बढ़ाने के उपाय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. समाजवादी सरकार द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति कर्मी की जा चुकी है. वित्तीय वर्ष 2014-15 में कर्तव्यपालन के दौरान मारे गए एवं घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के 103 कर्मियों के आश्रितों को 11 करोड़ 99 लाख 70 हजार रुपये की अनुग्रह धनराशि प्रदान की गई है, जबकि वर्ष 2015-16 में अभी तक 83 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 11 करोड़ 95 लाख 20 हजार रुपये की अनुग्रह धनराशि दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी के प्रति समर्पित पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने एवं उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस साल 100 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह तथा 400 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया है. पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी वर्ष से पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की व्यवस्था भी शुरू की गई है. इसके तहत, 95 राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को सम्मानित किया गया है. पुलिस कर्मियों में उत्साह बनाये रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें सेवा सम्बन्धी तमाम लाभ मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार के सत्ता में आने के बाद से विशेष अभियान चलाकर, लगभग 34 हजार अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदों पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है. उन्होंने कहा कि पुलिस बल के मुख्य आरक्षियों, उपनिरीक्षकों तथा निरीक्षकों के उपलब्ध पदों को बढ़ाते हुए इन्हें क्रमशः 60 हजार, 40 हजार तथा 5 हजार किया जाएगा. इस बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप कुल 30 हजार 575 कर्मियों को प्रमोशन के नए अवसर मिलेंगे. पुलिस बल में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर 38 हजार 315 तथा सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 3 हजार 784 पदों एवं कम्प्यूटर आपरेटर के 666 पदों की सीधी भर्ती की गई है. पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए 2 हजार 064 सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है. साथ ही, पुलिस विभाग के विभिन्न कैडरों की 16 सेवा नियमावलियों की समीक्षा कर भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है.

उमा भारती ने हरीश की पीठ थपथपाई

राजकुमार शर्मा

बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारधाम पहुंची भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री भारती उमा भारती हरीश रावत की संकटमोचन की सिद्ध हुईं. अपने भतीजे नील माधव के साथ बाबा के दर्शन के लिए पहुंची उमा भारती ने धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बहाने कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत की दिल से प्रशंसा की, जिसने राज्य में भाजपा के दिग्गजों के हरीश रावत को भ्रष्टाचार के मामले में घेरने की मंसा पर पानी फेर दिया.

उमा ने ऐसे समय में हरीश रावत की प्रशंसा की, जब भाजपा के दिग्गज नेता भूवनचंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक एवं नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ हमलावार थे. एक बात और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने जिस काम के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत की पीठ थपथपाई, उसकी सीबीआई जांच के लिए भाजपा सांसदों ने केंद्रीय गृहमंत्री का दरवाजा खटखटाया है.

निशंक ने आपदा के बाद से ही केदार क्षेत्र में आपदा में मारे गए लोगों के शव बिखरे होने की बात को मुद्दा बनाकर हरीश सरकार पर हमलावार थे. खण्डूड़ी भ्रष्टाचार के मामले में हरीश सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष भट्ट भी हरीश सरकार पर कालिख पोतने का कोई मौका नहीं गंवा रहे थे. उमा भारती का हरीश रावत की प्रशंसा करना भाजपा के दिग्गजों की मंशा पर पानी फेर दिया. आपदा के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को देखकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती इतनी खुश हुईं कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके न मनभेद हैं और न मतभेद. अच्छे काम की तारीफ करने में गुरेज नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केदारनाथ की तर्ज पर देश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी काम करने की जरूरत है. भारती ने कहा कि विषम परिस्थितियों में केदारनाथ धाम में काम किए जा रहे काम बेमिसाल है. जून 2013 में आई आपदा से निपटना आसान नहीं था. बावजूद इसके अब भी कुछ विषयों पर गंभीर होने की जरूरत है. मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता से पूरा करना होगा. दो दिवसीय भ्रमण पर केदारनाथ पहुंची केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुर्नुद्धार मंत्री उमा भारती ने कहा कि वह एक वर्ष बाद धाम में आई हैं. अब धाम में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा कि पावन केदारनाथ धाम, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है. धाम के गौरव को बनाए रखने के लिए केंद्र हर संभव मदद करेगा. केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के अलावा तीर्थ पुरोहितों व व्यवसायियों से भी बातचीत की और उनका दर्द सुना. केंद्रीय मंत्री भारती ने धाम में बने कॉटेज में ही भतीजे सहित रात्रि विश्राम भी किया. उमा भारती ने सरस्वती व मंदाकिनी नदी के

किनारे बनाई जा रही गेबिन, रॉक नेट और आरसीसी सुरक्षा दीवारों का निरीक्षण किया. मंदिर में एसएसआई द्वारा कराए जा रहे सुधारीकरण कार्य के बारे में जानकारी भी ली. केंद्रीय मंत्री ने प्राचार्य कर्नल कोठियाल से भी मुलाकात की और कहा कि धाम में किए गए कार्यों के लिए वह बधाई के पात्र हैं. हरीश सरकार ने अपनी उच्चप्राथमिकता में केदारधाम को सजाने सवारने के साथ सुरक्षित केदार का जो बीड़ा उठाया था, उस पर मोहर लगा कर साध्वी भारती ने बड़ा काम किया. केदारधाम अब पूरी तरह से सुरक्षित है का संदेश वैसे तो पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार के संतमंण्डल जो योगगुरू बाबा रामदेव जी के अगुवाई में केदारधाम गया था, उसने भी हरीश सरकार की सराहना की थी. उमा भारती द्वारा हरीश सरकार को शतप्रतिशत अंक दिए जाने को राजनीति के मर्मज्ञ शुभ संकेत मान रहे हैं. आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक रूख का भी संकेत बता रहे हैं. लोगो का मानना है कि शीघ्र ही मोदी सरकार की मेहरवानियों का पिटारा भी केदारधाम एवं उत्तराखंड के लिए खुलने वाला है. राजनीति के जानकारों का मानना है कि अपने भतीजे नील माधव के साथ पूजा के लिए केदारनाथ गईं उमा ने पावन धाम में ही माधव को अपना राजनीतिक वारिस भी मन से संकंल्पित किया. इस पूजा के बाद से माधव ही उनके राजनीतिक वारिस होगें पर भी मुहर लग गई है.

गैरसैंण को लेकर कांग्रेस व सरकार की राय अलग-अलग : भट्ट

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड राज्य गठन को प्रंदह वर्ष होने वाले हैं, लेकिन उत्तराखंड में राजधानी गैरसैंण का मामला अभी भी जिम्मेदार राजनीतिक दल और उसके नेताओं के बीच एक अबूक्ष पहेली बना हुआ है. राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण ही होगी की बात मुख्यमंत्री हरीष रावत ने कह कर इस मामले को नए सिरे से हवा दे दी है. गैरसैंण को लेकर कांग्रेस व सरकार की राय अलग-अलग है. समय-समय पर कांग्रेस गैरसैंण को लेकर शिगूफा छोड़ती रहती है, ताकि प्रदेश की जनता गैरसैंण को लेकर पूरी तरह से भ्रमित रहे. सरकार को स्थायी राजधानी के मसले पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, ताकि भ्रम की स्थिति दूर हो. यह सारी बात नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कही. अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखते हुए पहाड़ की भोली-भाली जनता को बेवकूफ बनाने के मकसद से एक नवंबर को गैरसैंण में हो रहे प्रांतीय अधिवेशन में इसे स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाने की बात कह रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ही स्थायी राजधानी को लेकर आपसी मतभेद हो चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ मंत्रीगण तो देहरादून में ही विधान भवन बनाने की वकालत तक कर चुके हैं. भट्ट ने कहा कि एक ओर तो कांग्रेस चार साल तक रायपुर में विधान भवन बनाने की पैरवी करती रही, वहीं दूसरी तरफ चार साल बाद अब चुनाव नजदीक आते देख इस डर से कि पहाड़ में कोई कार्य न होने से जनता में भारी आक्रोश है और ऐसे में चुनाव जीतना तो दूर उसकी जमानत बचाना भी मुश्किल है. गैरसैंण स्थायी राजधानी का मुद्दा उछालकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के झांसे में आने वाली नहीं है. वह कांग्रेस की असलियत जान चुकी है. भट्ट ने कहा कि गैरसैंण पर सरकार व कांग्रेस के स्वर अलग-अलग हैं. सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से स्पष्ट बताए कि आखिर वह करना क्या चाहती है. यदि वह इस संबंध में इतनी ही गंभीर है, तो सदन में स्थायी राजधानी की घोषणा करे. अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में संगठन व सरकार में मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं कि दोनों में दूरियां साफ नजर आ रही हैं. कांग्रेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बात करते हैं, कांग्रेस सरकार के मुखिया कुछ और ही राग अलापते हैं. वहीं प्रदेश के मुखिया का यह बयान कि उन्हें अपनों से खतरा है भाजपा से नहीं, स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार और संगठन की गहरी खाईं को वह भी महसूस कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचतान का खमियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज जिला मुख्यालय से लेकर तहसील व विकास खंडों तक में कोई काम नहीं हो रहा है. आम जनता को अपने एक छोटे से कार्य के लिए कई दिन कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन वहां इनकी सुनने वाला कोई नहीं है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और बिना लेन-देन के कोई कार्य नहीं हो पा रहा है. रावत कहते हैं कि जनता की भावना के अनुरूप ही सरकार फैसला लेगी, आगे जो जनता का रूख होगा, उसी के अनुसार काम होगा. मिशन 2017 को नजदीक देख सभी राजनीतिक दल फिर राजधानी के मुद्दे पर राजनीति गरमाने लगे हैं.